राष्ट्रीय संस्करण

बड़े मंच की बड़ी खिलाड़ी

वर्ष 5 अंक 53

मूल्य ₹8.00, नई दिल्ली, सोमवार, 2 अगस्त, 2021

दैनिक जागरण

www.jagran.com

पृष्ठ 14

ऐतिहासिक रविवार

- पीवी सिंधू ने ओलिंपिक में लगातार दूसरा पदक हासिल किया
- भारत के लिए दो व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली महिला
- 1980 में स्वर्ण जीतने के बाद हाकी में पदक जीतने का मौका

मैं काफी खुश हूं, क्योंकि मैंने इतने वर्षों तक कड़ी मेहनत की है। मेरे अंदर भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा था। मुझे खुश होना चाहिए कि मैंने कांस्य पदक जीता या दुखी होना चाहिए कि मैंने फाइनल में खेलने का मौका गंवा दिया। मैं सातवें आसमान पर हूं। मैं इस लम्हे का पूरा लुत्फ उठाऊंगी। मेरे परिवार ने मेरे लिए कड़ी मेहनत की है और काफी प्रयास किए, जिसके लिए मैं उनकी आभारी हूं।
पीवी सिंधू, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: टोक्यो ओलिंपिक में रविवार का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक रहा। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधू ने कांस्य पदक जीता। वह पहलवान सुशील कुमार के बाद व्यक्तिगत पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय व पहली महिला खिलाड़ी बनीं। वहीं, भारतीय पुरुष हाकी टीम क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को हराकर 1980 के बाद ओलिंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची। मीराबाई चानू और लवलीना के बाद सिंधू तीसरी महिला खिलाड़ी हैं, जिन्होंने इस ओलिंपिक में भारत का पदक पक्का किया।

पीवी सिंधू, हम सभी आपके शानदार प्रदर्शन से उत्साहित हैं। टोक्यो ओलिंपिक में कांस्य पदक जीतने के लिए आपको बधाई। आप भारत का गौरव हैं और हमारे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं।
नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

विश्व चैंपियन और रियो ओलिंपिक की रजत पदक विजेता सिंधू ने चीन की बिंग जियाओ को 53 मिनट में सीधे गेम में 21-13, 21-15 हराकर कांस्य पदक जीता। सिंधू के क्रास कोर्ट स्मैश और ड्राप शाट का चीन की खिलाड़ी के पास कोई जवाब नहीं था। महिला सिंगल्स का स्वर्ण पदक चीन की चेन यू फेई ने जीता। उन्होंने फाइनल में चीनी ताइपे की ताई जु यिंग को 21-18, 19-21, 21-18 से हराया।

ब्रिटेन को हराकर हाकी टीम सेमीफाइनल में: भारतीय पुरुष हाकी टीम ने ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराकर 41 साल से चले आ रहे ओलिंपिक पदक के सूखे को खत्म करने की ओर कदम बढ़ाए। भारत की ओर से दिलप्रीत सिंह (सातवें), गुरजंत सिंह (16वें) और हार्दिक सिंह (57वें मिनट में) ने गोल किए। ग्रेट ब्रिटेन के सैमुअल इयान वार्ड (45वें मिनट में) ने भी गोल दागा। मंगलवार को सेमीफाइनल में भारतीय टीम मौजूदा विश्व चैंपियन बेल्जियम से भिड़ेगी, जिसने क्वार्टर फाइनल में स्पेन को 3-1 से हराया।

भारत ने ओलिंपिक में आखिरी पदक 1980 मास्को ओलिंपिक में स्वर्ण के रूप में जीता था, लेकिन तब सिर्फ छह टीमों ने भाग लिया था। राउंड रोबिन आधार पर शीर्ष पर रहने वाली दो टीमों के बीच स्वर्ण पदक का मैच हुआ था। इस तरह से भारत 1972 में म्यूनिख ओलिंपिक के बाद पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचा है।

भारत के अन्य परिणाम

- मुक्केबाज सतीश कुमार (91 किग्रा से अधिक) को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा।
- घुड़सवार फवाद मिर्जा 11.20 पेनाल्टी अंक के साथ 22वें स्थान पर रहे।
- अनिर्बान लाहिड़ी चौथे और अंतिम दौर में एक ओवर 72 के स्कोर के साथ पुरुष गोल्फ स्पर्धा में 42वें स्थान पर रहे।

जीत के बाद भारतीय हाकी टीम के खिलाड़ी गुरजंत सिंह • रायटर

जागरण विशेष

जब जाना है खाली हाथ तो जाएं देकर कुछ सौगात

वाराणसी: दादा के पार्थिव शरीर को अंतिम स्नान कराए जाने के समय प्रशांत गाडे के बालमन में जो भाव फूटे, उनसे मानव कल्याण की धारा बह निकली। प्रशांत हजारों दिव्यांगों को सस्ते रोबोटिक हाथ की सौगात दे चुके हैं। (पेज-5)

नीतीश कुमार सही मायने में पीएम मैटेरियल : उपेंद्र

पटना : जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को पीएम मैटेरियल बताया है। कुशवाहा ने रविवार को कहा, देश में नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त जिन कुछ अन्य लोगों में पीएम पद संभालने की क्षमता है, उनमें नीतीश प्रमुख हैं। उन्होंने कहा, मैं नरेंद्र मोदी को चुनौती दिए जाने की कोई बात नहीं कह रहा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में पूरी एकजुटता है। मोदी अच्छा काम भी कर रहे हैं, परंतु उनके अतिरिक्त भी देश में लोग हैं, जो प्रधानमंत्री पद के लिए क्षमता रखते हैं। (पेज-4)

घाटी में आतंकियों के मददगारों को अब न पासपोर्ट मिलेगा, न सरकारी नौकरी

राष्ट्र विरोधियों पर नकेल ▸ आतंकी समर्थकों की घुसपैठ रोकने को पुलिस ने उठाया बड़ा कदम

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

- कानून व्यवस्था भंग करने में लिप्त किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलेगा पासपोर्ट या सरकारी सेवा के लिए क्लीयरेंस
- पढ़ाई के नाम पर पासपोर्ट ले पाकिस्तान गए 40 लड़के बने आतंकी, सुरक्षा बलों ने लौटने वाले 27 को किया ढेर
- आतंकी गतिविधियों में शामिल रह चुके 24 सरकारीकर्मियों को किया जा चुका है बर्खास्त

जम्मू-कश्मीर में पत्थरबाजों पर अब शिकंजा कसने लगा है। पत्थरबाजों की पहचान करके उन्हें नौकरियों और पासपोर्ट से वंचित किया जाएगा। जागरण आर्काइव

जम्मू-कश्मीर में देश के खिलाफ साजिश रचने वालों पर सरकार ने नकेल कस दी है। पत्थरबाजी और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले तत्व अब न सरकारी नौकरी में घुस पाएंगे और न विदेश भागकर राष्ट्र विरोधी एजेंडा चला पाएंगे। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बीते तीन दशक से भी ज्यादा समय से कश्मीर में जारी अलगाववाद और आतंकवाद के दौर में पहली बार इस तरह का बड़ा आदेश जारी किया है। पुलिस के सीआइडी विंग ने अपने सभी क्षेत्रीय स्टाफ को निर्देश दिया है कि वे ऐसे तत्वों के पासपोर्ट को मंजूरी न दें। यह आदेश सरकारी तंत्र में राष्ट्रविरोधी और आतंकी समर्थकों की घुसपैठ रोकने की कवायद के तहत उठाया गया है। इससे पूर्व सरकारी विभागों में विभिन्न पदों पर आसीन होकर राष्ट्र के खिलाफ काम करने वाले 24 कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा चुका है।

गौरतलब है कि कई पत्थरबाज और आतंकी सहृदयता और मुख्यधारा में शामिल होने की आड़ में या फिर भ्रष्ट तत्वों की मदद से पासपोर्ट प्राप्त कर विदेश भाग चुके हैं। इनमें दुख्तरान-ए-मिल्लत की अध्यक्षा आसिया अंद्राबी का पुत्र मुहम्मद बिन कासिम, टेरर फंडिंग के सिलसिले में तिहाड़ में बंद सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ शाह फंतोश की बेटी रुवा शाह, कश्मीर चैंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व चेयरमैन डा. मुबीन शाह समेत कई शामिल हैं, जिन्होंने कश्मीर को डायसपोरा बनाकर देश-विदेश में और इंटरनेट मीडिया पर आतंकवाद और अलगाववाद को हवा देने का एजेंडा चला रखा है। इनके अलावा कुछ वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय युवक पढ़ाई के नाम पर या फिर पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों से मुलाकात की आड़ में पासपोर्ट प्राप्त कर आतंकी शिविरों में गए हैं। पुलिस महानिरीक्षक (आइजीपी) विजय कुमार ने बताया कि 40 लड़के इसी तरीके से आतंकी बने हैं। उनमें से 27 मारे जा चुके हैं, जबकि 13 अब भी सीमा पार ही बैठे हैं।

कश्मीर में अपराध जांच विभाग (सीआइडी) की विशेष शाखा के एसएसपी ने शनिवार को जारी आदेश में कहा कि वे पासपोर्ट सेवा और सरकारी सेवा या सरकारी योजनाओं के संदर्भ में जब किसी व्यक्ति की जांच करते हुए उसकी सुरक्षा मंजूरी की रिपोर्ट तैयार करते हैं तो ध्यान रखें कि वे कानून व्यवस्था भंग करने में लिप्त न रहे हों। उसके बारे में संबंधित पुलिस स्टेशन से पता किया जाए। संबंधित पुलिस स्टेशन में या सुरक्षा एजेंसियों के पास अक्सर ऐसे लोगों की सीसीटीवी फुटेज, तस्वीरें, वीडियो, आडियो उपलब्ध रहती हैं, उनका संज्ञान लिया जाए।

आवेदक की पृष्ठभूमि की पूरी जांच होनी चाहिए

इससे पूर्व प्रदेश सरकार ने जम्मू-कश्मीर सिविल सर्विसेज (वेरीफिकेशन आफ कैरेक्टर) इंस्ट्रक्शंस, 1997 में संशोधन कर कहा, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले की पृष्ठभूमि की पूर्ण जांच होनी चाहिए। इसके लिए पुलिस सभी डिजिटल साक्ष्य और रिकार्ड का संज्ञान ले। इस संशोधन के बाद सरकारी नौकरी के इच्छुक आवेदक के लिए यह बताना अनिवार्य हो गया है कि उसके स्वजन या रिश्तेदार किसी राजनीतिक दल से संबंधित हैं या नहीं, उसने किसी सियासी गतिविधि में भाग लिया है या नहीं, उसका या उसके किसी स्वजन का किसी विदेशी संगठन के साथ संबंध है या नहीं। किसी प्रतिबंधित संगठन से कोई संबंध है या नहीं। उसे अपने रिश्तेदारों की भी पूरी जानकारी देनी होगी।

बहावलपुर के पाश इलाके में पाक सेना की सुरक्षा में रह रहा जैश सरगना अजहर पेज>>5

भाजपा ने परिवारवाद व जातिवाद की राजनीति को खत्म किया : शाह

- गृह मंत्री ने उप्र में विपक्ष पर बोला हमला-'चुनाव आते ही कपड़े बदलकर निकले विपक्ष में दम नहीं'
- लखनऊ में यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट आफ फारेंसिक साइंसेज का किया शिलान्यास
- मीरजापुर में विंध्य कारिडोर और रोप-वे की दी सौगात, योगी सरकार को जमकर सराहा

जो काम विपक्ष 15 वर्षों में नहीं कर पाया, योगी सरकार ने उसे चार साल में कर दिखाया। पहले उप्र में माफिया खुलेआम घूमते थे। आज कोई नहीं दिखता। योगी सरकार ने 11 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था को 22 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाया है जो देश में दूसरे नंबर पर है। -अमित शाह

लखनऊ में इंस्टीट्यूट आफ फारेंसिक साइंसेज का शिलान्यास करते अमित शाह। साथ हैं योगी आदित्यनाथ। जागरण

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

उत्तर प्रदेश में फिर प्रचंड बहुमत से कमल की सरकार आएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस भरोसे के साथ लखनऊ और मीरजापुर में रविवार को भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा। कहा कि चुनाव नजदीक आते ही विपक्ष के नेता नए कपड़े पहनकर आ जाते हैं। भाजपा ने उप्र में परिवारवाद व जातिवाद की राजनीति को खत्म किया है। जो सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, वे आगामी विस चुनाव में करारी हार का मन बना लें। शाह ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था में हुए बदलाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उनकी टीम की जमकर सराहना भी की।

कानून-व्यवस्था में उप्र सबसे आगे : गृह मंत्री ने रविवार को लखनऊ के पिपरसंड में यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट आफ फारेंसिक साइंसेज का शिलान्यास करने के बाद मीरजापुर जाकर विंध्य कारिडोर परियोजना का शिलान्यास और रोप-वे का लोकार्पण किया। दोनों स्थानों पर लोगों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, 2017 में भाजपा ने वादा किया था कि बेहतर कानून-व्यवस्था व विकसित प्रदेश देंगे। आज 2021 में गर्व से कह सकता हूं कि योगी व उनकी टीम ने कानून-व्यवस्था के मामले में प्रदेश को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया है। एक समय वह भी था, जब कानून-व्यवस्था के कारण सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को निवेशकों का सम्मेलन दिल्ली में कराना पड़ा था। उन्होंने कहा, विकास की 44 योजनाओं को आगे बढ़ने में उप्र प्रदेश सबसे आगे है।

जिस भूमि पर माफिया का कब्जा, वहीं इंस्टीट्यूट : योगी पेज>>6

यूएनएससी बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं मोदी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- एक अगस्त से भारत बना सुरक्षा परिषद का एक महीने के लिए अध्यक्ष
- बातचीत को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय नियमों के पालन पर आगे बढ़ने की होगी कोशिश

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की अध्यक्षता संभालने के बाद भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस अवसर का उपयोग करने को पूरी तरह से तैयार है। भारत रविवार (एक अगस्त, 2021) को एक माह के लिए सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना है। भारत ऐसे समय में यूएनएससी की अध्यक्षता करने जा रहा है, जब वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी, समुद्री सुरक्षा, अफगानिस्तान और आतंकवाद का मुद्दा काफी अहम है। ये सारे मुद्दे भारत के हितों को भी प्रभावित कर रहे हैं। बहुत संभव है कि पीएम नरेंद्र मोदी यूएनएससी के किसी एक कार्यक्रम की अध्यक्षता भारत के प्रतिनिधि के तौर पर करें। ऐसा करने वाले वह भारत के पहले प्रधानमंत्री बन सकते हैं।

अगले एक माह के कार्यक्रम का आधिकारिक एजेंडा यूएनएससी की तरफ से सोमवार को जारी किया जाएगा। एजेंडे में अहम मुद्दों को शामिल करने के लिए भारत अपने अहम महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार देशों जैसे फ्रांस, अमेरिका, रूस आदि के साथ लगातार संपर्क में है। भारत की तैयारियों को इस बात से समझा जा सकता है कि अगले एक महीने के दौरान यूएनएससी में अलग-अलग आयोजनों को पीएम नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला संबोधित करेंगे। पीएम मोदी किस आयोजन को संबोधित करेंगे इसका फैसला अभी होना बाकी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने इंटरनेट मीडिया पर लिखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी संभवतः नौ अगस्त को यूएनएससी में एक कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और ऐसा करने वाले वे भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि अभी इस बारे में अंतिम फैसला होना बाकी है। वैसे योजना में यह भी शामिल है कि विदेश मंत्री जयशंकर यूएनएससी में भारत के हितों से जुड़े किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर वहां उपस्थित होकर भारत का पक्ष रखें। जयशंकर ने भारत की मंशा साफ करते हुए इंटरनेट मीडिया के जरिये यह जानकारी दी है कि भारत की कोशिश संतुलन स्थापित करने की होगी। बातचीत को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय नियमों के पालन पर आगे बढ़ने की होगी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि भारत मुख्य तौर पर सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति व समृद्धि (पांच स) पर जोर देगा। भारत इसके पहले 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92 और 2011-12 में यूएनएससी का सदस्य रहा है।

दो माह पहले शुरू कर दी थी तैयारी

भारत ने दो माह पूर्व ही यूएनएससी की अध्यक्षता की तैयारी शुरू कर दी थी। विदेश मंत्री जयशंकर ने रूस व अमेरिका के विदेश मंत्रियों से बात की, ताकि जिन मुद्दों को भारत आगे लाना चाहता है, उसे समर्थन मिल सके। नई दिल्ली में रूस के राजदूत निकोलाई कुदाशेव ने कहा, भारत ने समुद्री सुरक्षा, शांति दल व आतंकवाद जैसे मुद्दे उठाने का फैसला किया है, जो स्वागतयोग्य है। फ्रांस के राजदूत एमानुएल लीनैन ने कहा, भारत का पूर्ण सहयोग करेंगे, ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कायम हो सके।

भारत-चीनी सेना के बीच हाटलाइन स्थापित

- सिक्किम में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी भी तरह की झड़प को रोकने के लिए हुई अहम पहल
- उत्तरी सिक्किम में इस साल जनवरी में हुई थी झड़प, दोनों तरफ के कई जवान घायल हुए थे

नई दिल्ली, एएनआइ : सिक्किम में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी तरह की झड़प से बचने और विश्वास तथा सौहार्दपूर्ण संबंधों की भावना को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों की तरफ से अहम पहल हुई है। रविवार को उत्तरी सिक्किम के कोंगरा ला में भारतीय सेना और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के खंबा दजोंग में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के बीच हाटलाइन स्थापित की गई।

भारतीय सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि संयोग से रविवार यानी एक अगस्त को पीएलए दिवस भी था। दोनों देशों के बीच यह छठी हाटलाइन है। इसके साथ ही पूर्वी लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में दोनों सेनाओं के बीच दो-दो हाटलाइन हो गई हैं। सेना ने कहा, 'दोनों देशों के सशस्त्र बलों के पास कमांडर स्तर पर संचार के लिए सुस्थापित तंत्र हैं। विभिन्न सेक्टरों में स्थापित ये हाटलाइन संवाद को मजबूत करने, सीमाओं पर शांति व सौहार्द बनाए रखने में अहम योगदान करती हैं।' हाटलाइन के उद्घाटन में दोनों तरफ की सेनाओं के कमांडर मौजूद रहे। हाटलाइन के माध्यम से दोस्ती और सद्भाव के संदेश का आदान-प्रदान किया गया।

विश्वास बहाली की ओर अहम कदम। फाइल

नाकू ला में दोनों तरफ के सैनिकों के बीच हुई थी झड़प : समाचार एजेंसी आइएएनएस के मुताबिक, यह हाटलाइन इस लिहाज से अहम है क्योंकि इसी साल 20 जनवरी को उत्तरी सिक्किम के नाकू ला में दोनों तरफ के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। चीनी सैनिक भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें भारतीय जवानों ने रोक दिया। इस झड़प में कई सैनिक घायल हुए थे।

चीनी सैनिकों का रवैया रहता है आक्रामक

अरुणाचल प्रदेश से लेकर पूर्वी लद्दाख तक चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हाल के दिनों में बेहद तनाव की स्थिति है। चीनी सैनिकों का रवैया आक्रामक रहता है, लेकिन भारतीय सैनिकों की सतर्कता से उनकी एक नहीं चलती और अक्सर झड़पें होती रहती हैं।

एक दिन पहले ही सैन्य कमांडर स्तर की हुई थी बातचीत : पूर्वी लद्दाख में टकराव के सभी बिंदुओं से सैनिकों को हटाने को लेकर शनिवार को ही दोनों देशों के बीच सैन्य कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। करीब नौ घंटे तक चली इस वार्ता में भारत ने साफ कहा था कि देपसांग, गोगरा और हाटस्प्रिंग से चीन अपने सैनिकों को हटाए।

सेहत की डोज

टीके की एक भी डोज लेने पर गंभीर नहीं हो रहा कोरोना संक्रमण, आंकड़े दे रहे गवाही, दोनों डोज लेने वाले मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति कम, अधिकाधिक टीकाकरण साबित हो सकता है रक्षा कवच, झारखंड, मप्र, बिहार व कानपुर में एक भी डोज न लेने वाले मरीज काफी

कोरोना का टीका न लगवाने वाले ही ज्यादा हो रहे संक्रमित

जागरण टीम, नई दिल्ली

कोरोना की तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है। केंद्र सरकार का टीकाकरण पर खास ध्यान है। जुलाई माह में 13 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है। दरअसल कोरोना महामारी से युद्ध में टीका एक अहम हथियार बनकर सामने आया है। दैनिक जागरण द्वारा झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में की गई एक पड़ताल के मुताबिक, बीते कुछ समय में इस महामारी से संक्रमित होने वालों में अधिकांश वह लोग हैं जिन्होंने टीके की एक भी डोज नहीं ली है। टीके की दोनों डोज लेने के बाद भी संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या बेहद कम है। इससे साफ है कि टीका लगवाना कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रहने का कारगर उपाय है। आइए आंकड़ों के जरिये देखें कि टीका लगवाने वाले और न लगवाने वालों पर कोरोना अब कैसे असर डाल रहा है:

झारखंड: टीका न लगवाने वाले 89 फीसद को हुआ संक्रमण : झारखंड में अभी 270 संक्रमित मरीज हैं, इनमें से 89 फीसद मरीजों ने टीका नहीं लगवाया है। जागरण ने संक्रमित मरीजों का हाल लिया तो पाया कि महज 11 फीसद लोगों ने ही टीके की पहली डोज ली है। दोनों डोज लेने वाले गिने-चुने लोग संक्रमित हुए। जिसने एक डोज भी ली है, उसे भी गंभीर संक्रमण नहीं हुआ। महज तीन प्रतिशत संक्रमित ऐसे रहे, जिन्होंने दोनों डोज लगवाई हैं। इनमें एक प्रतिशत से भी कम को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। शेष होम आइसोलेशन में हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अधिक से अधिक टीकाकरण से ही हम सुरक्षित हो सकते हैं। झारखंड में सबसे अधिक 49 संक्रमित रांची में मिले जिसमें केवल पांच ने ही टीके की पहली डोज ली थी। दूसरी डोज इनमें से किसी को भी नहीं लगी थी। गढ़वा जिले में पिछले हफ्ते चेन्नई से लौटा एक मजदूर संक्रमित था। लापरवाही से 19 लोग संक्रमित हो गए। इनमें किसी ने टीका नहीं लगवाया था।

मध्य प्रदेश: 54 फीसद ने नहीं लगवाया टीका, कोरोना से जकड़ा : मध्य प्रदेश की बात करें तो कोरोना से पिछले दो महीने में संक्रमित हुए मरीजों में से 34 फीसद ने टीके की पहली डोज ली है। 12 फीसद मरीज ऐसे भी हैं जो कोरोना रोधी टीके की दोनों डोज लगवा चुके हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग की टीकाकरण स्टेटस रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। इन हालिया संक्रमित मरीजों में 54 फीसद ऐसे हैं, जिन्होंने टीके की एक भी डोज नहीं लगवाई है। यानी आधे से अधिक संक्रमित वह हैं जिन्हें टीका नहीं लगा है। यह कुल 576 मरीजों का विश्लेषण है।

ऐसे लोग संक्रमित कम हुए, जिन्होंने टीके की एक या दोनों डोज ले ली थी। दोनों डोज लेने वाले संक्रमित भी हुए तो गंभीर रूप से बीमार नहीं हुए। तीसरी लहर से बचाव में टीकाकरण, मास्क व शारीरिक दूरी का अनुपालन हथियार बनेंगे।
-डा. अजीत प्रसाद, राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, झारखंड

बिहार: केवल 14 फीसद ऐसे मरीज जिन्होंने दोनों डोज लीं : बिहार के आंकड़े भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि टीका कोरोना से बचाव का कवच है। बिहार में इस वक्त कुल एक्टिव केस 456 हैं जिसमें 170 यानी 37.28 फीसद ने टीके की एक भी डोज नहीं लगवाई है। इसमें से 220 यानी 48.24 फीसद पहली डोज लगवा चुके हैं। कुल 456 संक्रमितों में महज 66 यानी 14.47 फीसद लोग टीके की दोनों डोज ले चुके हैं।

कानपुर: 36 में महज छह ऐसे जिन्हें लगा है टीका : कानपुर में वर्तमान में कोरोना के कुल 36 एक्टिव केस हैं। इनमें कोई अस्पताल में भर्ती नहीं है। गुरुवार को यहां कोरोना के 30 संक्रमित मिले थे। चार का पूर्ण टीकाकरण होने और दो को सिंगल डोज लगे होने की जानकारी मिली है।

सोनीपत में निहंगों ने सीआरपीएफ जवानों पर किया तलवार से हमला

जागरण संवाददाता, सोनीपत

यह कैसा आंदोलन

- आधी रात को ड्यूटी से लौटते समय रसोई ढाबे के पास किया हमला
- निहंगों की कार गलत तरीके से खड़ी होने से लगा था लंबा जाम

हरियाणा के सोनीपत जिले के कुंडली बार्डर पर कृषि सुधार कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन में शामिल निहंगों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों पर हमला बोल दिया। उन्होंने एक जवान को सिर व पीठ पर तलवार से वार कर घायल कर दिया और फरार हो गए। सीआरपीएफ के एएसआइ की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कुंडली बार्डर पर धरना स्थल पर पुलिस के साथ सीआरपीएफ के जवान भी तैनात हैं। शनिवार रात करीब दो बजे सीआरपीएफ के छह जवान ड्यूटी पूरी करके सरकारी वाहन से कैंप की ओर जा रहे थे। सीआरपीएफ के एएसआइ शंभू सिंह ने पुलिस को बताया कि जब उनका वाहन रसोई ढाबे के पास मोड़ पर पहुंचा तो वहां जाम लगा हुआ था। जवान नीचे उतरे तो पाया कि आंदोलन में शामिल निहंगों की एक कार सड़क पर गलत तरीके से खड़ी थी, जिससे वाहनों को निकलने में परेशानी हो रही थी। जवानों ने निहंगों से कार सड़क से हटाने तो कहा तो सात-आठ निहंगों ने गालियां देनी शुरू कर दीं। मना करने पर एक निहंग ने तलवार से हमला कर जवान शाबिर अंसारी को घायल कर दिया। इसके बाद निहंग भाग निकले। घायल जवान को उपचार के लिए कंपनी के अस्पताल में ले जाया गया। वहीं घटना की जानकारी पुलिस को दी गई।

निहंगों ने पहले भी किया है लोगों पर हमला पेज>>5

20 फीसद कोविशील्ड की और 40 फीसद कोवैक्सीन की डोज दिल्ली में सोमवार से पहली खुराक के लिए इस्तेमाल होगी। 31 जुलाई तक टीकाकरण केंद्रों पर कोविशील्ड की पहली डोज देने पर रोक लगाई गई थी।

अस्पतालों में होंगी आक्सीजन की तिहाई जरूरतें पूरी

कोरोना से जंग की तैयारी ▶ दिल्ली के अस्पतालों में लगाए गए 79 आक्सीजन प्लांट

इस माह के अंत तक 78 अतिरिक्त प्लांट शुरू होने की उम्मीद

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना की तीसरी लहर की आंशका के मद्देनजर अस्पतालों में आक्सीजन की आपूर्ति व आइसीयू बेड बढ़ाने के लिए तैयारी चल रही है। इसके तहत दिल्ली के बड़े सरकारी व निजी अस्पतालों में 160 आक्सीजन प्लांट लगाए जाने हैं। इनमें से अब तक 79 आक्सीजन प्लांट ही लग पाए हैं। इस तरह 49.37 फीसद काम पूरा हो पाया है। हालांकि, इस माह के अंत तक 78 अतिरिक्त आक्सीजन प्लांट लगाने का काम पूरा हो जाएगा। ऐसे में दिल्ली में तीसरी लहर आने पर यदि जरूरत पड़ी तो अस्पताल बैकअप के रूप में आक्सीजन की एक तिहाई जरूरतें खुद पूरी करने में सक्षम होंगे।

वैसे दिल्ली लिक्विड मेडिकल आक्सीजन के लिए दूसरे राज्यों पर ही निर्भर है। अस्पतालों में 160 प्रेशर स्विंग एडसार्प्शन (पीएसए) प्लांट लगने पर आक्सीजन की कुल उत्पादन क्षमता 148.11 मीट्रिक टन होगी। दूसरी लहर में आक्सीजन की मांग बढ़ने पर दो मई को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत 19,357 आक्सीजन बेड व 5172 आइसीयू बेड के लिए कुल 512.15 मीट्रिक टन आक्सीजन के आवंटन का प्रावधान किया गया था। हालांकि, तब आक्सीजन की कुल जरूरत 598 मीट्रिक टन बताई गई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सब कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 300 से 400 मीट्रिक आक्सीजन की जरूरत बताई गई है। यदि तीसरी लहर में प्रतिदिन 400 मीट्रिक टन आक्सीजन की जरूरत पड़ी तो प्लांटों से 37 फीसद और यदि 500 मीट्रिक टन आक्सीजन की जरूरत पड़ी तब भी प्लांटों से 29.62 फीसद आक्सीजन की जरूरत पूरी हो सकेगी। शेष आक्सीजन के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता बनी रहेगी।

अस्थायी अस्पताल में आइसीयू बेड तैयार : दूसरी लहर के दौरान मई के पहले सप्ताह में अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए कुल 21,541 बेड थे। इनमें 5234 आइसीयू बेड शामिल थे। बाद में बेडों की संख्या बढ़कर 27 हजार से ज्यादा हो गई थी। तीसरी लहर के लिए 30 हजार बेड की व्यवस्था करने की बात कही गई है। इन सभी बेड पर आक्सीजन उपलब्ध कराने की तैयारी चल रही है।

अस्पतालों में बच्चों के इलाज के लिए की जा रही व्यवस्था : अस्पतालों में बच्चों के इलाज के लिए जनरल वार्ड में बेड व आइसीयू बेड की व्यवस्था की जा रही है। एम्स में बच्चों के लिए 40 आइसीयू बेड आरक्षित रहेगा। लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज के अस्पताल में बच्चों के इलाज के लिए करीब 450 बेड व चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में 250 बेड की व्यवस्था की गई है। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में 100 आइसीयू बेड की व्यवस्था की गई है। लोकनायक अस्पताल में भी बच्चों के इलाज के लिए 150 बेड का आइसीयू तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा रामलीला मैदान व पूर्वी दिल्ली में 500-500 आइसीयू बेड के दो अस्थायी अस्पताल तैयार रखे गए हैं। छतरपुर स्थित कोविड केयर सेंटर में भी 500 बेड हैं, लेकिन इसमें जरूरत पड़ने पर 5000 बेड की व्यवस्था की जाएगी।

एक दिन में 40 हजार नए मामलों को ध्यान में रखकर तैयारी: दिल्ली में तैयारियों के लिए गठित विशेषज्ञों की कमेटी के सदस्य डा. अरुण गुप्ता ने कहा कि दूसरी लहर में कोरोना के प्रतिदिन 26 हजार तक मामले आ रहे थे। अभी इस बात को ध्यान में रखकर तैयारी की जा रही है कि यदि 40 हजार भी मामले आए तो आक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के निदेशक डा. बीएल शेरवाल ने कहा कि डाक्टरों को प्रशिक्षित करने का काम शुरू कर दिया गया है। दो बैच में अब तक 60 डाक्टरों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। तीसरे बैच का प्रशिक्षण शुरू किया गया है। अगस्त में पूरे माह प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा।

कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए पीएम केयर फंड से लोकनायक अस्पताल में लगाए गए नए आक्सीजन प्लांट। संजय

कोरोना की संक्रमण दर 0.12 फीसद हुई, 85 नए मामले

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : राजधानी में कोरोना के मामलों के कम होने का सिलसिला थम गया है। रविवार को संक्रमण दर 0.08 फीसद से बढ़कर 0.12 फीसद हो गई जबकि, कोरोना के 85 नए मरीज मिले। एक दिन पहले 58 नए मामले आए थे। ऐसे में एक बार फिर संक्रमण बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहीं पिछले 24 घंटे में 83 मरीज ठीक हुए व एक मरीज की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दिल्ली में कोरोना के अब तक कुल 14 लाख 36 हजार 350 मामले आए हैं। इसमें से 14 लाख 10 हजार 714 मरीज ठीक हो चुके हैं। इससे मरीजों के ठीक होने की दर 98.21 फीसद है। वहीं मृतकों की कुल संख्या 25 हजार 54 हो गई है। इससे मृत्यु दर 1.74 फीसद है। दिल्ली में मौजूदा समय में 582 सक्रिय मरीज हैं। इसके अलावा 292 कंटेनमेंट जोन हैं।

आक्सीजन प्लांटों की स्थिति

दिल्ली सरकार के अस्पतालों में लगने हैं आक्सीजन प्लांट	66
पीएम केयर फंड से आक्सीजन प्लांट लगाने की योजना	17
दिल्ली सरकार के अस्पतालों में लगे आक्सीजन प्लांट	36
31 अगस्त तक लगाए जाने वाले अतिरिक्त आक्सीजन प्लांट	27
तीन अन्य आक्सीजन प्लांट लगाने के लिए निर्धारित समय	15 अक्टूबर
केंद्र सरकार के अस्पतालों में लगने हैं आक्सीजन प्लांट	10
केंद्र के अस्पतालों में अब तक लगे आक्सीजन प्लांट	6
चार अन्य आक्सीजन प्लांट लगाने के लिए निर्धारित समय	15 अगस्त
निजी अस्पतालों में लगने हैं आक्सीजन प्लांट	84
निजी अस्पतालों में अब तक लगे आक्सीजन प्लांट	37
अभी आक्सीजन प्लांट लगाने का काम बाकी	47

पिंक व ग्रे लाइन के नए कारिडोर पर छह से चलेगी मेट्रो

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- पिंक लाइन के पूरे 59 किलोमीटर नेटवर्क पर सीधी उपलब्ध होगी मेट्रो सेवा, सफर होगा आसान
- केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी व सीएम केजरीवाल दिखाएंगे हरी झंडी

आखिरकार पिंक लाइन के त्रिलोकपुरी-मयूर विहार पाकेट एक व ग्रे लाइन के नजफगढ़-ढांसा बस स्टैंड कारिडोर पर मेट्रो का परिचालन शुरू करने की तारीख घोषित हो गई है। छह अगस्त को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हरी झंडी दिखाकर दोनों कारिडोर पर मेट्रो का परिचालन शुरू करेंगे। उसी दिन दोपहर तीन बजे से यात्रियों के लिए मेट्रो सेवा उपलब्ध हो जाएगी।

त्रिलोकपुरी-मयूर विहार पाकेट एक के बीच मेट्रो का परिचालन शुरू होने से पिंक लाइन दिल्ली मेट्रो का सबसे बड़ा कारिडोर बन जाएगा। इसके 59 किलोमीटर नेटवर्क पर शिव विहार से मजलिस पार्क तक सीधी मेट्रो सेवा उपलब्ध हो जाएगी। इससे यात्रियों का सफर आसान हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) का कहना है कि दोनों कारिडोर पर परिचालन शुरू होने से दिल्ली मेट्रो का कुल नेटवर्क 390 किलोमीटर व कुल स्टेशन 286 हो जाएंगे।

मौजूदा समय में पिंक लाइन के अलग-अलग दो हिस्सों पर मेट्रो का परिचालन हो रहा है। इसके तहत मजलिस पार्क से मयूर विहार पाकेट एक और त्रिलोकपुरी से शिव विहार के बीच मेट्रो का परिचालन हो रहा है। इन दोनों कारिडोर के बीच का 290 मीटर हिस्सा जमीन विवाद के कारण पहले नहीं बन पाया था। अब त्रिलोकपुरी से मयूर विहार पाकेट एक के बीच कारिडोर तैयार हो चुका है। 23 जुलाई को मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) ने कारिडोर का तकनीकी निरीक्षण करने के बाद उसी दिन परिचालन के लिए मंजूरी दे दी थी।

पिंक लाइन आनंद विहार रेलवे स्टेशन, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के अलावा साउथ एक्सटेंशन, लाजपत नगर मार्केट व आइएनए को जोड़ती है। इसलिए, पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, साउथ एक्सटेंशन, लाजपत नगर मार्केट व आइएनए पहुंचना आसान हो जाएगा। इसके अलावा दक्षिणी दिल्ली के इलाकों से आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचना आसान हो जाएगा।

वहीं मौजूदा समय में ग्रे लाइन के 4.3 किलोमीटर हिस्से पर द्वारका से नजफगढ़ के बीच मेट्रो सेवा उपलब्ध है। नजफगढ़ से ढांसा बस स्टैंड के बीच मेट्रो का परिचालन शुरू होने से ग्रे लाइन का नेटवर्क करीब एक किलोमीटर बढ़ जाएगा और द्वारका से सीधे ढांसा बस स्टैंड तक मेट्रो उपलब्ध हो सकेगी। इससे नजफगढ़ के आसपास स्थित गांवों के लोगों व ढांसा बार्डर के नजदीक स्थित हरियाणा के गांवों के लोगों के लिए दिल्ली पहुंचना आसान हो जाएगा।

न्यूज गैलरी

दिल्ली में हुई तेज बारिश, आज भी आरेंज अलर्ट

नई दिल्ली : दिल्ली में रविवार को तेज बारिश हुई। इससे तापमान में भी गिरावट आई। अधिकतम व न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इस वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। सोमवार को भी दिल्ली के कई इलाकों में तेज बारिश होगी। इस वजह से मौसम विभाग ने एक दिन के लिए आरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे सप्ताह बारिश की संभावना जताई गई है। रविवार को दिल्ली में 40.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। दरअसल रात से ही कई इलाकों में तेज बारिश शुरू हो गई थी। इस वजह से सुबह साढ़े आठ बजे तक 28.2 मिलीमीटर बारिश हुई। सुबह नौ बजे के बाद 12.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वैसे रिज एरिया में सबसे अधिक 126.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। (राब्यू)

सागर धनखड़ हत्याकांड में आज दायर होगा आरोप पत्र

नई दिल्ली: पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में क्राइम ब्रांच सोमवार को आरोप पत्र दायर करेगी। मामले में ओलंपियन सुशील कुमार सहित कुल 18 आरोपित बनाए गए हैं, जिनमें 15 आरोपितों को पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। ये सभी तिहाड़ जेल में बंद हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मामले में 100 से अधिक गवाह बनाए गए हैं। अहम सुबूत के तौर पर सबसे अधिक इलेक्ट्रानिक सुबूत को आरोप पत्र में रखा गया है। आरोप है कि सुशील कुमार ने अपने सहयोगी अजय सहरावत के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने के लिए साजिश रची। (जासं)

डीएसीसी बना इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने वाला पहला निकाय

नई दिल्ली : दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने वाला राष्ट्रीय राजधानी का पहला सरकारी निकाय बन गया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पालिसी 2020 के मुताबिक दिल्ली सरकार के सभी विभागों को लीज माडल के जरिये इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना है। इस कड़ी डीपीसीसी ने पांच साल की अवधि के लिए 29 टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक कारों को किराये पर लिया है, जो पूरी तरह से ग्रीन व्हीकल अपनाने वाली दिल्ली की पहली सरकारी संस्था बन गई है। (राब्यू)

पतंगबाजी में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर होगी कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से किया आग्रह
- नियमों के उल्लंघन पर पांच साल तक की हो सकती है सजा

स्वतंत्रता दिवस पर पतंगबाजी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से चीनी मांझे या तेज धार वाले सिंथेटिक धागे का उपयोग न करने को कहा है। इस मांझे के उपयोग पर 2017 से प्रतिबंध लगा है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग ने कहा कि इस मांझे का उपयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। नियमों के उल्लंघन करने पर पांच साल तक की सजा या एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

दिल्ली सरकार ने कहा है कि लोगों को चीनी मांझे पर लगे प्रतिबंध के उल्लंघन की शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। दिल्ली पुलिस के लिए 100 नंबर, मंडलायुक्त के लिए 1077, नगर निगम उत्तरी के लिए 155304, नगर निगम दक्षिणी के लिए 155305 व नगर निगम पूर्वी के लिए 155303 पर शिकायत दे सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार के प्रमुख वन्यजीव वार्डन के हेल्पलाइन नंबर 1800118600 पर भी शिकायत कर सकते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा पहले ही जारी की जा चुकी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चीनी मांझे के नाम से लोकप्रिय नाइलोन, प्लास्टिक या किसी अन्य कृत्रिम पदार्थों से बने पतंग उड़ाने के धागों की बिक्री, उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति और उपयोग पर प्रतिबंध है। इसके साथ ही पतंग उड़ाने के लिए किसी अन्य ऐसे धागे का भी उपयोग नहीं किया जा सकता है, जिसमें कांच या धातु चढ़ा हो। सरकार ने कहा है कि पतंगबाजी के शौकीन केवल सूत के धागे का उपयोग कर सकते हैं, जिसे धातु, कांच, गोंद जैसे पदार्थ चढ़ा कर कड़ा नहीं किया गया हो।

बता दें कि चीनी मांझे के उपयोग से राजधानी में कई लोग घायल हो चुके हैं। इसके अलावा ऐसे मांझे में फंसकर पक्षियों की भी जान जाती रही है। इन घटनाओं को देखते हुए ही सरकार ने इन पर प्रतिबंध लगाया है।

डीटीसी में सफर करने वाली महिलाओं की गलत संख्या बता रही सरकार : विजेंद्र

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : भाजपा ने दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को हर साल दो हजार करोड़ रुपये का घाटा होने के लिए आप सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। रोहिणी से विधायक व भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि भ्रष्टाचार व गलत नीतियों की वजह से डीटीसी घाटे में है। इस बीच उन्होंने दिल्ली सरकार पर बसों में मुफ्त सफर करने वाली महिलाओं का गलत आंकड़ा बताने का भी आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के मंत्री ने विधानसभा में डीटीसी को भारी नुकसान होने की बात स्वीकार की है। इसकी जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए। सरकार के मुताबिक मार्च से जुलाई के बीच डीटीसी में करीब 80 फीसद यात्रियों को गुलाबी टिकट दिया गया। मुफ्त सफर करने वाली महिलाओं को गुलाबी टिकट दिया जाता है। सरकार द्वारा दी गई यह जानकारी गलत है, क्योंकि डीटीसी की बसों में हमेशा महिला यात्रियों की संख्या 50 फीसद से कम रहती है। इसलिए इन आंकड़ों की जांच की जानी चाहिए। सरकार अपने भ्रष्टाचार और डीटीसी के कुप्रबंधन को छिपाने के लिए सरकारी खजाने को भारी नुकसान हो रहा है।

नगर निगमों के फंड को लेकर फिर तेज होगी सियासत

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

नगर निगमों के बकाया फंड को लेकर आने वाले दिनों में राजनीति तेज होगी। भाजपा दिल्ली सरकार पर नगर निगमों को फंड नहीं देने का आरोप लगा रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि नगर निगमों का अब कुछ भी बकाया नहीं है। उसे कुछ देने के बजाय उल्टा नगर निगमों से 6837 करोड़ रुपये कर्ज वसूल करना है। भाजपा इस मुद्दे को लेकर अब एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी कर रही है। उसका कहना है कि सूचना के अधिकार (आरटीआइ) से मिली जानकारी के अनुसार भी सरकार से निगमों को लगभग 13 हजार करोड़ रुपये बकाया लेना है।

भाजपा पिछले काफी समय से दिल्ली सरकार पर नगर निगमों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाती रही है। उसका कहना है कि भाजपा शासित निगमों को बदनाम करने के लिए उसे वित्तीय रूप से बदहाल करने की साजिश रची जा रही है। फंड की कमी से जनहित के काम प्रभावित हो रहे हैं। निगम कर्मचारियों को समय पर वेतन देने में दिक्कत हो रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता का कहना है कि कोरोना महामारी के दौर में भी सरकार निगमों के साथ भेदभाव कर रही है। बावजूद इसके कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निगमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

बकाया फंड की मांग को लेकर भाजपा के तीनों महापौर मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना दे चुके हैं, फिर भी सरकार का रवैया नहीं बदला है। पिछले दिनों विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भाजपा पार्षदों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया था। भाजपा विधायकों ने सदन में भी यह मुद्दा उठाया था, जिसके जवाब में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने निगमों पर किसी तरह का बकाया नहीं होने की बात कही थी।

अब भाजपा इसे लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना ने कहा है कि निगमों के बकाया फंड को लेकर दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है। सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के तहत मिली जानकारी के अनुसार पूर्वी दिल्ली नगर निगम का 1628.59 करोड़ रुपये, उत्तरी दिल्ली नगर निगम का 2596.13 करोड़ रुपये और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का 7330.04 करोड़ रुपये सरकार पर बकाया है।

भाजपा नेताओं ने बनाई आप सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : भाजपा के सभी 278 मंडलों की कार्यकारिणी की बैठक रविवार को हुई, जिसमें नगर निगम चुनाव की तैयारी और आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाई गई। आने वाले दिनों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सरकार के खिलाफ कार्यकर्ता मोर्चा खोलेंगे। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता व अन्य नेताओं ने आप सरकार को सभी मोर्चों पर विफल बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाने का आह्वान किया। कार्यकारिणी में प्रस्ताव पास कर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की गई।

प्रदेश अध्यक्ष ने कृष्णा नगर मंडल व आया नगर मंडल में और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी हरकेश नगर मंडल में आयोजित कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कोरोना काल में बिजली के भारी भरकम बिल, जलसंकट, बदहाल परिवहन व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा की बदहाली आदि को लेकर जनता के बीच जाने की सलाह दी। नेताओं ने कहा कि कोरोना संकट के समय दिल्ली सरकार ने लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया था। अस्पताल में लोगों को जगह नहीं मिल रही थी।

चिड़ियाघर खुलने के पहले दिन उमड़ी भीड़

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : साढ़े तीन महीने के लंबे इंतजार के बाद रविवार को दिल्ली का चिड़ियाघर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। छुट्टी का दिन होने के कारण बड़ी संख्या में लोग चिड़ियाघर देखने पहुंचे। चिड़ियाघर को दो पालियों में सुबह आठ से दोपहर एक बजे और एक से शाम पांच बजे तक 1500-1500 की संख्या में पर्यटकों के लिए खोला गया। चिड़ियाघर खुलने के बाद सुबह नौ बजे से ही प्रवेश के लिए लोगों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं। अधिकतर लोग परिवार के साथ चिड़ियाघर पहुंचे थे।

आनलाइन टिकट लेने में पर्यटकों को असुविधा न हो, इसके लिए जगह-जगह क्यूआर कोड छपे हुए बोर्ड लगाए गए थे। क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करके लोग टिकट खरीदकर अंदर प्रवेश कर रहे थे। चिड़ियाघर देखने के लिए उमड़ी भीड़ के चलते दोपहर तीन बजे तक ही एक दिन में तीन हजार लोगों के प्रवेश के लिए निर्धारित टिकट बिक गए। इससे बाद में आए पर्यटकों को प्रवेश नहीं मिला।

गफ्फार मार्केट खाली करने के निगम के आदेश पर कोर्ट की रोक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- एनडीएमसी ने मार्केट खाली करने का दिया था आदेश
- व्यापारियों को बड़ी राहत, तीस हजारी कोर्ट में पांच अगस्त को होगी सुनवाई

तीस हजारी कोर्ट ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उसने गफ्फार मार्केट के व्यापारियों को दुकानें खाली करने को कहा था। इस मामले में कोर्ट ने पांच अगस्त के लिए अगली सुनवाई निर्धारित कर दी है।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 23 जुलाई को गफ्फार मार्केट के पास एमसीडी मार्केट के बिल्डिंग जर्जर होने का हवाला देकर दुकानें खाली करने के नोटिस दिया था। इस नोटिस को चुनौती देते हुए मार्केट एसोसिएशन ने अदालत में वाद दायर कर कहा कि निगम गफ्फार मार्केट की दुकानों से वर्तमान दुकानदारों को बेदखल करके नई इमारत बनाकर नए लोगों को बेचना चाहता है। यह भी आरोप लगाया कि नगर निगम बिल्डर माफिया से मिलकर लीज पर दी गई दुकानों का सर्वे कर रहा है और इमारत को खतरनाक दिखाकर खाली करने को कह रहा है। उल्लेखनीय है कि निगम ने आइआइटी से इस इमारत की ढांचागत मजबूती का आडिट कराया था। आडिट में यह बात सामने आई थी कि इमारत काफी कमजोर है। इसलिए निगम ने इस इमारत को जर्जर घोषित कर दिया था। निगम के जोन उपायुक्त ने आदेश में भी आइआइटी रुड़की की रिपोर्ट का हवाला दिया गया था।

गौरतलब है कि 23 जुलाई के नोटिस में व्यापारियों को निगम ने तीन दिन का समय इमारत खाली करने के लिए दिया था। मामले ने तूल पकड़ा तो निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष जोगीराम जैन ने 10 दिन के लिए निगम के आदेश पर रोक लगा दी। निगम का कहना है कि चूंकि बिल्डिंग जर्जर है इसलिए इसे तोड़कर एक नया व्यावसायिक परिसर बनाया जाएगा।

झीलों में घर या समस्याओं का समंदर

यह कोई झील या तालाब नहीं ये देश की राजधानी दिल्ली के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का किराड़ी इलाका है जो हर साल मानसून में झील का रूप ले लेता है हालात ये है कि बारिश बंद होने के बाद भी कई दिन सड़के, गलिया, मैदान पानी में डूबे रहते हैं। जलजमाव के कारण बीमारियों का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोग नारकीय जीवन बिताने को मजबूर। हरीश कुमार

अवैध निर्माण

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अरावली में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के लिए तैयार की गई सूची में सामने आए नाम

अरावली में नेताओं, अफसरों के भी हैं फार्म हाउस

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद

अरावली के जंगल में मंगल करने के लिए जमीन खरीद कर फार्म हाउस बनाने वालों में नगर निगम के अधिकारी से लेकर पूर्व मंत्रियों, राजनेता व उनके रिश्तेदार भी शामिल हैं। बड़े शैक्षणिक संस्थान सहित धार्मिक स्थल व होटल भी बने हुए हैं। कुछ बेहद प्रभावी लोगों ने तो खुद स्वयं अपने नाम की बजाय नजदीकी रिश्तेदारों के नाम फार्म हाउस खरीदे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अरावली में ऐसे अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के लिए तैयार की गई सूची में यह जानकारी सामने आई है। अब ये प्रभावशाली लोग राहत पाने के लिए इधर-उधर हाथ-पैर मार रहे हैं। उधर प्रशासन यहां जल्द कार्रवाई शुरू करने की तैयारी में जुटा हुआ है।

यहां सबसे पहले इनकी बिजली सप्लाई काटने की तैयारी हो रही है। ताकि तोड़फोड़ के समय कोई दिक्कत न हो। खोरी बस्ती में चल रही तोड़फोड़ की कार्रवाई से ही मशीनरी, पुलिस बल लिया जाएगा। पता चला है कि

अतिक्रमण का नजारा। फाइल फोटो

कुछेक फार्म हाउस से सामान भी शिफ्ट करना शुरू कर दिया गया है। कुछ अदालत से मिले स्टे की प्रति फार्म हाउस के बाहर चस्पा कर रहे हैं।

किस-किसके हैं फार्म हाउस : सूची से पता लगा है कि जिले के एक पूर्व मंत्री का अनखीर गांव की राजस्व संपदा में 11 एकड़ में फार्म हाउस है। अनंगपुर में एक जज का 1.21 एकड़ में फार्म हाउस है। एक और पूर्व मंत्री का मेवला महाराजपुर की राजस्व संपदा में 2.28 एकड़ में फार्म हाउस है। जिले के ही एक राजनेता के रिश्तेदार का मेवला महाराजपुर में ही 9.49 एकड़ में फार्म हाउस है। नगर निगम के वरिष्ठ नगर योजनाकार रहे की पत्नी के नाम से मेवला महाराजपुर में 3.26 एकड़ में फार्म हाउस है। इसी गांव की राजस्व संपदा में एक शैक्षणिक संस्थान 35.18 एकड़ में बना हुआ है। नगर निगम के पूर्व पार्षद सहित शहर के एक बिल्डर ने भी फार्म हाउस बनाया हुआ है। गोशाला, आश्रम सहित सरकारी संस्थान भी अरावली में हैं।

जल्द कार्रवाई शुरू करने की मांग : सेव अरावली संस्था के संस्थापक जितेंद्र भड़ाना, कैलाश बिधूड़ी ने बताया कि अरावली में गैर कानूनी रूप से जब इतने बड़े स्तर पर खरीद-फरोख्त हो रही थी तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अब इन पर जल्द कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। अरावली के अंदर अवैध निर्माणों तक बिजली भी पहुंच चुकी है। एक-एक किलोमीटर तक बिजली के खंभे लगे हुए हैं, ट्रांसफार्मर लगा दिए गए। इसी वजह से यहां अवैध निर्माण बढ़ते चले गए। ऐसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।

बारिश से फिर बढ़ा यमुना का जलस्तर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : पहाड़ों पर मूसलधार बारिश ने फिर से राजधानी में यमुना का जलस्तर बढ़ा दिया है। रविवार दोपहर को जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। खादर के क्षेत्र में अस्थायी रूप से रहने वाले लोगों के लिए प्रशासन ने सड़क किनारे टेंट लगाकर बसेरे बनाए हुए हैं, टेंट में रहने वाले लोगों के लिए बारिश आफत साबित हुई। बारिश से उनका सामान भीग गया। प्रशासन का कहना है कि हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसे ओखला बैराज से पानी को उत्तर प्रदेश की ओर भेजा जा रहा है।

एसडीएम प्रीत विहार राजेंद्र कुमार ने बताया कि शुक्रवार को यमुना का जलस्तर घटना शुरू हो गया था, देर रात को फिर से जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया। दोपहर तीन बजे जलस्तर 205.32 मीटर पहुंच गया था, जबकि शाम सात बजे 205.30 मीटर पहुंच गया था।

शादी करने से खत्म नहीं हो जाता दुष्कर्म का आरोप : हाई कोर्ट

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली

- एफआइआर रद करने की युवक की याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज
- समझौता होने की दलील के आधार पर मांगी गई थी राहत

दुष्कर्म पीड़िता से शादी कर लेने से युवक पर लगा दुष्कर्म का आरोप समाप्त नहीं हो जाता है। दुष्कर्म एक गंभीर अपराध है और दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाने के आधार पर इसे निरस्त नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ ने यह अहम टिप्पणी करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ दुष्कर्म की धारा में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने से इन्कार कर दिया।

युवती ने आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता ने एक होटल में ले जाकर उससे दुष्कर्म किया। युवती ने कहा कि शादी करने की शिकायत में ही उसने आरोपित के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात की थी। हालांकि, बाद में उसने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया था।

एफआइआर रद करने की मांग को लेकर याचिका दायर कर आरोपित ने दलील दी कि उन दोनों के बीच समझौता हो गया है और उन्होंने शादी कर ली है। इसलिए, इस मामले में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया जाए।

दिल्ली हाई कोर्ट। फाइल फोटो

508 किलोमीटर लंबे मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे नेशनल हाई स्पीड रेल कार्पोरेशन लिमिटेड ने कहा है कि उसने बुलेट ट्रेन के लिए ढांचा तैयार कर लिया है। यह ट्रेन महाराष्ट्र, दादरा, नागर हवेली और गुजरात से होकर गुजरेगी।

असम और मिजोरम के बीच निकलने लगी शांति की राह

राहत ▸ गृह मंत्री अमित शाह ने असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों से की बात, सीमा विवाद को लेकर दोनों राज्यों के बीच चल रही तनातनी

26 को दोनों राज्यों के बीच हुई हिंसा में असम के छह पुलिसकर्मियों और एक आम नागरिक की मौत हो गई थी

नई दिल्ली, प्रेट्र : असम और मिजोरम के बीच शांति की राह निकलने लगी है। दोनों पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सीमा पर तनाव खत्म करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा से फोन पर बात की। इस दौरान सार्थक बातचीत के जरिये सीमा विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने का फैसला किया गया। इस बीच, दोनों राज्यों की सीमा पर तनाव अभी बरकरार है। आवश्यक वस्तुएं ले जा रहे ट्रकों समेत वाहनों की आवाजाही पर छठे दिन भी बंद रही, हालांकि लोगों के आने-जाने पर कोई रोक नहीं है।

26 जुलाई को दोनों राज्यों के बीच हुई हिंसा में असम के छह पुलिसकर्मियों और एक आम नागरिक की मौत हो गई थी तथा 50 से अधिक लोग घायल हो गए थे। केंद्र के दो शीर्ष अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार असम और मिजोरम के बीच मौजूदा सीमा विवाद का शांतिपूर्ण समाधान चाहती है तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों मुख्यमंत्रियों के लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों व पुलिस महानिदेशकों ने 28 जुलाई को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में भाग लिया था जिसमें संघर्ष स्थल पर एक तटस्थ बल (सीआरपीएफ) तैनात करने का निर्णय हुआ। एक अधिकारी ने कहा कि दोनों राज्य सरकारें सहयोग कर रही हैं और केंद्र सरकार को विश्वास है कि सीमा पर अब और कोई संघर्ष नहीं होगा।

दोनों मुख्यमंत्रियों ने जताई समाधान की उम्मीद

मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा और असम के सीएम हिमंता बिस्व सरमा की फाइल फोटो। आर्काइव

मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने ट्वीट कर कहा, 'मुझे अब भी केंद्र से असम-मिजोरम तनाव के सौहार्दपूर्ण समाधान की उम्मीद है।' वहीं, असम के मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, 'असम-मिजोरम सीमा पर जो कुछ हुआ, वह दोनों राज्यों के लोगों को अस्वीकार्य है। सीमा विवाद का समाधान केवल चर्चा से हो सकता है।'

सरमा के खिलाफ एफआइआर वापस लेगा मिजोरम

मिजोरम के मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार सरमा के खिलाफ एफआइआर वापस लेने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि असम के पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे अथवा नहीं। सीमा पर हिंसा के बाद दोनों राज्यों की पुलिस ने एक-दूसरे के नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थीं। मिजोरम की एफआइआर में मुख्यमंत्री सरमा को भी नामित किया गया था। एएनआइ के मुताबिक, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा का कहना है कि सीमा विवाद के संबंध में असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना एक सामान्य चीज है।

सरमा बोले, असम पुलिस के समक्ष पेश होने को तैयार

असम के सीएम सरमा ने कहा है, 'मुझे समन भेजा गया तो मैं जांच में शामिल होने के लिए सिलचर से वैरेंगते तक पदयात्रा करके जाऊंगा। वे मुझे गिरफ्तार भी करते हैं और उससे हालात सामान्य होते हैं तो मैं तैयार हूं। मैं गुवाहाटी हाई कोर्ट से जमानत नहीं लूंगा।' अपने अधिकारियों के खिलाफ एफआइआर पर सरमा ने कहा, 'मुझे अपने अधिकारियों की रक्षा करनी होगी। असम में हुई घटना के लिए मैं मिजोरम पुलिस को उनकी जांच करने की अनुमति नहीं दे सकता। उन्हें जारी समन को हम स्वीकार नहीं करेंगे।' विवाद के समाधान के संदर्भ में उन्होंने कहा, 'हमारे वकील तैयारी कर रहे हैं जो पूरी होने वाली है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ताकि सीमा विवाद को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम गलत हैं तो हम स्वीकार करेंगे।' दोनों राज्यों द्वारा की जा रही जांच पर सरमा ने कहा, 'असम पुलिस या मिजोरम पुलिस को यह जांच क्यों करनी चाहिए। सीबीआइ या एनआइए को निष्पक्ष तरीके से यह जांच करने दीजिए।'

सेटेलाइट इमेजिंग से होगा सीमाओं का निर्धारण

▸ कुछ माह पूर्व गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था सुझाव

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने सीमा विवादों के निपटारे के लिए सेटेलाइट इमेजिंग के जरिये पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाओं का निर्धारण करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि यह कार्य नार्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (एनईएसएसी) को दिया गया है जो अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) और पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) की संयुक्त पहल है। उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करके एनईएसएसी पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास प्रक्रिया को बढ़ाने में मदद करता है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ महीने पहले सेटेलाइट इमेजिंग के माध्यम से अंतरराज्यीय सीमाओं के निर्धारण का विचार रखा था। शाह ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंतरराज्यीय सीमाओं और जंगलों के मानचित्रण में एनईएसएसी को शामिल करने और राज्यों के बीच सीमाओं का वैज्ञानिक सीमांकन करने का सुझाव दिया था। शिलांग स्थित एनईएसएसी पहले से ही इस क्षेत्र में बाढ़ प्रबंधन के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है।

सरकारी अधिकारियों ने कहा कि सीमाओं के निर्धारण में वैज्ञानिक तरीके अपनाने से, किसी भी विसंगति की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और राज्य सीमा विवाद के समाधान को बेहतर तरीके से स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा कि सेटेलाइट से मानचित्रण हो जाने के बाद पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाएं खींची जा सकती हैं और विवादों को स्थायी रूप से सुलझाया जा सकता है।

बता दें कि मिजोरम सरकार का दावा है कि इनर लाइन रिजर्व वन क्षेत्र में 509 वर्ग मील का हिस्सा उसका है जिसे 1875 में बंगाल पूर्वी सीमांत नियमन, 1873 के तहत अधिसूचित किया गया था, जबकि असम का कहना है कि 1993 में भारतीय सर्वेक्षण द्वारा खींची गई सीमा और संवैधानिक मानचित्र उसे स्वीकार्य है।

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर 7,800 से अधिक याचिकाएं

▸ उच्च न्यायालयों में दायर याचिकाओं के बारे में सरकार ने दी जानकारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर देशभर के उच्च न्यायालयों में 2019 से अब तक 7,800 से अधिक जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। कुछ उच्च न्यायालयों ने ऐसी जनहित याचिकाओं का अलग से रिकार्ड नहीं रखा है। दूसरी तरफ कुछ अदालतों में सलाना आधार पर आंकड़ा मौजूद नहीं है।

पिछले सप्ताह एक सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने राज्यसभा में यह आंकड़ा जारी किया। सरकार से पिछले दो वर्षों में सुप्रीम कोर्ट एवं विभिन्न हाई कोर्टों में दायर ऐसी जनहित याचिकाओं के बारे में पूछा गया था। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, 2019 से इस साल जुलाई तक सभी हाई कोर्टों में मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित 7,832 जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर ऐसी जनहित याचिकाओं के बारे में बताया गया है कि मांगी गई जानकारी के अनुसार सूचनाओं को सुरक्षित नहीं किया जाता है। हालांकि, सरकार ने 'सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी 08' के तहत दायर जनहित याचिकाओं की संख्या के बारे में जानकारी दी है। इस श्रेणी के अधीन पत्र याचिका व जनहित याचिका मामलों का निष्पादन किया जाता है।

2017-19 के बीच 24 हजार किशोरों ने की खुदकुशी : एनसीआरबी

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की तरफ से हाल ही में संसद में पेश आंकड़े न सिर्फ चौंकाते हैं, बल्कि किशोर व नवयुवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सचेत भी करते हैं। एनसीआरबी ने बताया है कि वर्ष 2017-19 के बीच 14-18 साल के 24 हजार से ज्यादा किशोरों व नवयुवाओं ने खुदकुशी कर ली। 4,046 मामलों की वजह परीक्षा में विफलता रही।

एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2017-19 के बीच कुल 24,568 किशोरों व नवयुवाओं ने खुदकुशी की, जिनमें 13,325 लड़कियां शामिल रहीं। वर्ष 2017 में 8,029, 2018 में 8,162 व 2019 में 8,337 किशोरों व नवयुवाओं ने आत्महत्या की। 639 ने विवाह से जुड़े मुद्दों पर आत्महत्या की, इनमें 411 लड़कियां शामिल हैं। 3,315 ने प्रेम संबंधों के चलते, 2,567 ने बीमारी के कारण व 81 ने शारीरिक शोषण के तंग आ कर खुदकुशी कर ली। प्रियजन की मौत, नशे का आदी होना, गर्भधारण करना, सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होना, बेरोजगारी व गरीबी आदि भी कारणों में शुमार रहे। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 3,115 किशोरों व नवयुवाओं ने आत्महत्या की।

भाजपा का दामन थाम मणिपुर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने राहुल पर बोला हमला

▸ गोविंदास ने कहा, वर्षों इंतजार के बाद भी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष से नहीं हो पाई मुलाकात

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस की मणिपुर इकाई के पूर्व अध्यक्ष गोविंदास कोंथौजैम ने रविवार को भाजपा का दामन थाम लिया। इसके बाद कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करना भी बेहद मुश्किल है।

गोविंदास ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ए. शारदा देवी, राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी व पार्टी के प्रदेश प्रभारी संबित पात्रा आदि की उपस्थिति में नई पारी की शुरुआत की। बिशनपुर से छह बार विधायक रहे गोविंदास कांग्रेस से पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। बीरेन सिंह ने गोविंदास को पुराना दोस्त बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास का एजेंडा पूर्वोत्तर के लोगों को काफी पसंद आ रहा है। केंद्रीय कैबिनेट में पूर्वोत्तर के पांच मंत्रियों को शामिल किया जाना पीएम मोदी की क्षेत्र के प्रति गंभीरता को जाहिर करता है। पात्रा ने कहा कि गोविंदास के भाजपा में शामिल होने से पार्टी के साथ-साथ पूर्वोत्तर को भी काफी फायदा होगा। गोविंदास ने बाद में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। नड्डा ने ट्वीट किया, 'मैं उनका पार्टी में स्वागत करता हूं और नई पारी के लिए शुभकामना देता हूं।'

समाचार एजेंसी एएनआइ के अनुसार, गोविंदास ने कांग्रेस की कार्यशैली पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, 'हमने वर्षों इंतजार किया, लेकिन राहुल गांधी समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात नहीं हो सकी। ऐसी पार्टी में काम करना मुश्किल था। पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरा देश तरक्की कर रहा है... इसलिए मैं यहां हूं।'

कांग्रेस की मणिपुर इकाई के पूर्व अध्यक्ष गोविंदास कोंथौजैम रविवार को नई दिल्ली में भाजपा का थामन थाम लिया। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया। एएनआइ

असम के एक और कांग्रेस विधायक भाजपा में

गुवाहाटी, आइएएनएस : कांग्रेस के दो बार के विधायक सुशांत बोरगोहेन रविवार को भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने शुक्रवार को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। जोरहाट जिले की थौरा विधानसभा सीट से चुने गए सुशांत ने विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही 126 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस सदस्यों की संख्या 29 से घटकर 27 रह गई है। सुशांत ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा से भी मुलाकात की। सरमा ने कहा कि युवा नेता सुशांत के शामिल होने से पार्टी को काफी लाभ मिलेगा। इससे पहले 21 जून को चार बार कांग्रेस विधायक रहे रूपज्योति कुर्मी ने भाजपा का दामन थाम लिया था।

पेगासस जासूसी मामले की जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में पांच को सुनवाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : पेगासस जासूसी मामले की मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा स्वतंत्र जांच कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट पांच अगस्त को सुनवाई करेगा। इसमें वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार की याचिका भी शामिल है।

सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची के अनुसार प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना व जस्टिस सूर्यकांत की पीठ पांच अगस्त को तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इनमें सरकारी एजेंसियों द्वारा विशिष्ट नागरिकों, नेताओं व पत्रकारों की पेगासस के जरिये कथित जासूसी की खबरों के संबंध में जांच कराने का अनुरोध किया गया है। शीर्ष अदालत ने 30 जुलाई को कहा था कि वह इस मामले में राम और कुमार की याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगी। पत्रकारों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पिछले हफ्ते अदालत से कहा था कि याचिका के व्यापक असर को देखते हुए तत्काल सुनवाई की जरूरत है। याचिका में कहा गया है कि कथित जासूसी भारत में विरोध की अभिव्यक्ति को दबाने और हतोत्साहित करने के एजेंसियों एवं संगठनों के प्रयास की बानगी है।

भारतीय छात्रों के विदेश जाने की रफ्तार थामने की कोशिश

▸ भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में ही पढ़ने को मिलेंगे विदेशी विश्वविद्यालयों से जुड़े प्रमुख कोर्स

▸ दोनों देशों के संस्थान मिलकर शुरू करेंगे संयुक्त कोर्स, यूजीसी ने जारी की गाइडलाइन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता को मजबूती देने की कोशिशों के साथ-साथ सरकार अब पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले भारतीय छात्रों को देश में ही रोकने की तैयारी में है। इसके तहत विदेशी विश्वविद्यालयों से जुड़े प्रमुख कोर्स अब उन्हें देश में ही उपलब्ध होंगे। इसे लेकर भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों ने विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर साझा कोर्स शुरू करने की मुहिम तेज की है। कोरोना संकट के दौर में वैसे भी भारतीय छात्र अब पढ़ाई के लिए विदेश जाने से थोड़ा हिचक रहे हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने एक गाइडलाइन जारी की है। इसके बाद कोई भी उच्च शिक्षण संस्थान ऐसे कोर्सों को शुरू कर सकेगा। लेकिन वे ऐसा कोई कोर्स शुरू नहीं कर सकेंगे जो देश की सुरक्षा और अखंडता को प्रभावित करता हो, साथ ही ऐसे किसी शोध को भी अनुमति नहीं दी जाएगी।

दो दर्जन संस्थानों ने किया अनुबंध, भारतीय संस्थान देंगे 50 फीसद क्रेडिट : देश के करीब दो दर्जन से ज्यादा उच्च शिक्षण संस्थानों ने संयुक्त कोर्स शुरू करने को लेकर विदेशी संस्थानों के साथ अनुबंध किया है। माना जा रहा है कि नए शैक्षणिक सत्र में इन सभी संस्थानों में यह कोर्स शुरू हो जाएंगे। यूजीसी के मुताबिक, विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर शुरू किए जाने वाले संयुक्त कोर्सों को कुछ इस तरह डिजाइन किया जा रहा है, जिसमें 50 प्रतिशत क्रेडिट भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों की ओर से दिया जाएगा। साथ ही डिग्री में विदेशी और भारतीय दोनों ही उच्च शिक्षण संस्थानों के नाम दर्ज होंगे।

यह पूरी पहल इसलिए भी अहम है क्योंकि कोरोना से पहले हर साल करीब छह लाख भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2019 में 5.88 लाख भारतीय छात्र पढ़ाई के लिए विदेश गए थे। इनमें से आधे छात्र अमेरिका, करीब 15 फीसद आस्ट्रेलिया, छह फीसद ब्रिटेन और सात फीसद कनाडा जाते हैं। बाकी छात्र अन्य देशों को जाते हैं।

शिक्षा बजट का दोगुना विदेश में शिक्षा पर करते हैं खर्च : रिपोर्ट के मुताबिक, विदेश जाने वाले ये छात्र हर साल पढ़ाई पर करीब 72 हजार करोड़ रुपये खर्च करते हैं जो देश में उच्च शिक्षा पर खर्च होने वाले बजट का करीब दोगुना है। इससे हर साल बड़ी मात्रा में भारतीय मुद्रा विदेश चली जाती है। इसके अलावा जो छात्र पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं, उनमें से ज्यादातर उसी देश के होकर रह जाते हैं। इससे देश को आर्थिक के साथ-साथ प्रतिभा का भी नुकसान उठाना पड़ता है। पिछले साल यानी वर्ष 2020 में कोरोना के चलते सिर्फ 2.61 लाख छात्र ही पढ़ाई के लिए विदेश जा पाए थे।

विदेशी छात्रों को लुभाने की भी कोशिश : शिक्षा मंत्रालय ने इस बीच विदेशी छात्रों को भी भारतीय संस्थानों की ओर आकर्षित करने की योजना बनाई है। यूजीसी ने इसके तहत सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने यहां विदेशी छात्रों की मदद के लिए काउंटर खोलने का निर्देश दिया है। अब तक करीब 160 उच्च शिक्षण संस्थानों ने अपने यहां यह दफ्तर खोल दिया है। इसके साथ ही इंटरनेट मीडिया और दूसरे माध्यमों से दुनिया के करीब 30 देशों में ब्रांडिंग भी कराई जा रही है।

पहली बार दुबई और कुवैत में होंगे नीट के नए केंद्र

दुबई, एएनआइ : शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए खाड़ी क्षेत्र के दुबई और कुवैत में नए केंद्रों की घोषणा की है। इस बड़े कदम से एनआरआइ अभिभावक और विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा की अफरातफरी और दबाव से राहत मिलेगी। अब ऐसे विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए विदेश यात्रा नहीं करनी होगी। एलेन कैरियर इंस्टीट्यूट ओवरसीज के प्रयासों और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ ही अन्य विभिन्न भागीदारों के समर्थन से नीट इस साल से कुवैत और दुबई में आयोजित की जाएगी। एलेन ओवरसीज के प्रबंध निदेशक केशव माहेश्वरी ने कहा कि खाड़ी देशों में कई भारतीय परिवार रहते हैं और हजारों विद्यार्थियों ने भारतीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन दिया है। इन विद्यार्थियों के लिए विशेष कोटा भी आवंटित किया गया है। दुनिया भर में कोविड-19 महामारी और नीट-यूजी परीक्षाओं के लिए केंद्रों की उपलब्धता के अभाव के कारण कई विद्यार्थियों ने एलेन से इस समस्या का समाधान तलाशने का आग्रह किया था।

नकवी बोले, तत्काल तीन तलाक के मामलों में आई 80 फीसद की कमी

कुप्रथा पर रोक

▸ तीन मंत्रियों ने तत्काल तलाक की पीड़िताओं से की बातचीत

▸ कानून लागू होने के दो साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस का आयोजन

नई दिल्ली, प्रेट्र : तत्काल तीन तलाक कुप्रथा के खिलाफ कानून लागू करने के दो साल पूरे होने पर रविवार को देशभर में विभिन्न संगठनों ने मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के तौर पर मनाया और कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार की सराहना की। इस अवसर पर केंद्र सरकार के तीन मंत्रियों ने भी तत्काल तीन तलाक कुप्रथा की पीड़िताओं से बातचीत की। समाचार एजेंसी एएनआइ के अनुसार, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एक कार्यक्रम में कहा कि यह कानून बनने के बाद से तत्काल तीन तलाक के मामलों में 80 फीसद की कमी आई है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी तथा श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव यहां मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्रियों ने कई मुस्लिम महिलाओं से भी बातचीत की, जो तत्काल तीन तलाक की पीड़ित थीं। बयान में कहा गया कि मुस्लिम महिलाओं ने एक अगस्त, 2019 को इस कुप्रथा के खिलाफ कानून लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। कानून के तहत इस कुप्रथा को अपराध करार दिया गया है। मुस्लिम महिलाओं ने मंत्रियों के साथ बातचीत में कहा कि मोदी सरकार ने देश की मुस्लिम महिलाओं में आत्मनिर्भरता, स्वाभिमान और आत्मविश्वास को मजबूत किया है। एक बार में दिए जाने वाले तीन तलाक कुप्रथा के खिलाफ कानून लाकर उनके संवैधानिक, मौलिक और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की है। इस मौके पर मुस्लिम महिलाओं को संबोधित करते हुए ईरानी ने कहा कि एक अगस्त तत्काल तीन तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं के संघर्ष को सलाम करने का दिन है।

मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के अवसर पर विचार व्यक्त करते केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। पीआइबी

'कांग्रेस सत्ता में जेम्स बांड थी, अब उठा रही जासूसी का मनगढ़ंत मुद्दा'

विपक्ष को घेरा

▸ नकवी ने 13 अगस्त से पहले मानसून सत्र खत्म होने की बातों को बताया अफवाह

▸ कहा, सरकार इस सत्र में जनता से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पेगासस जासूसी मामले को लेकर संसद में चल रहे गतिरोध के बीच रविवार को कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सत्ता में रहने के दौरान जासूसी की जेम्स बांड रही पार्टी अब फर्जी एवं मनगढ़ंत मुद्दे पर संसद का समय बर्बाद करना चाहती है। राज्यसभा के उपनेता ने कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों पर रैंट एंड रन (आरोप लगाओ और भाग जाओ) की नीति पर चलने का भी आरोप लगाया।

एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि सरकार इस मानसून सत्र में जनता से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि जल्द ही गतिरोध टूटेगा और दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारु रूप से चलेगी।

भाजपा के वरिष्ठ नेता ने संसद के मानसून सत्र को कम करने की बात को भी खारिज कर दिया और कहा कि इस तरह की अफवाहों का कोई आधार नहीं है। सत्र 13 अगस्त तक निर्धारित किया गया था और तब तक कार्य सूचीबद्ध है। यह पूछे जाने पर कि क्या संसद में गतिरोध खत्म करने के लिए कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, नकवी ने कहा कि कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दल रैंट एंड रन फार्मूला अपना रहे हैं। लोगों के मुद्दों पर बहस और चर्चा में भाग लेने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है।

उन्होंने पहले कहा कि हम कोरोना पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन बाद में नहीं माने। उन्होंने कहा कि हम किसानों पर चर्चा चाहते हैं और फिर उस पर सहमत नहीं हुए। देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की समस्या है, वे उस पर या मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं।

कवायद

जीओएस राष्ट्रीय नीति सैटनैव-2021 तैयार करने की योजना बना रहा, इसके मसौदे पर परामर्श के लिए इसरो की वेबसाइट पर रखा गया

सेटेलाइट नेविगेशन विकास की ऊंचाई छूने की तैयारी में जुटा

बेंगलुरु, प्रेट्र : भारत का उपग्रह आधारित नेविगेशन और वृद्धि सेवा क्षेत्र को विकास के ऊंचे पायदान तक पहुंचने की तैयारियों में जुटा है। इसके प्रभावी विकास, संचालन और रखरखाव के लिए एक नीतिगत प्रस्ताव लाया जाएगा।

अंतरिक्ष विभाग (जीओएस) सेटेलाइट आधारित नेविगेशन के लिए एक 'व्यापक और मूल' राष्ट्रीय नीति तैयार करने की योजना बना रहा है। इसे 'भारतीय उपग्रह नेविगेशन नीति 2021 (सैटनैव नीति- 2021) का भी नाम दिया गया है। इसके मसौदे को अब सार्वजनिक परामर्श के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की वेबसाइट पर रखा गया है। इसके बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा। यह उपलब्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने, उपयोग बढ़ाने, सेवाओं के प्रगतिशील विकास की दिशा में काम करने और अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने पर जोर देने के साथ उपग्रह आधारित नेविगेशन और वृद्धि सेवाओं में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना चाहता है।

पिछले कुछ दशकों में अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन सिस्टम द्वारा प्रदान की जाने वाली स्थिति, वेग और समय (पीवीटी) सेवाओं पर भरोसा करने वाले प्रयोगों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। सूचना व मोबाइल फोन प्रौद्योगिकी के आने के साथ भारत भर में करोड़ों उपयोगकर्ता जीवन के लगभग हर क्षेत्र में पीवीटी आधारित अनुप्रयोगों पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन सिस्टम हैं जो दुनिया भर में नेविगेशन सिग्नल प्रदान करते हैं। वर्तमान में, चार जीएनएसएस हैं- जैसे अमेरिका से जीपीएस, रूस से ग्लोनास, यूरोपीय संघ से गैलीलियो और चीन से बेईदो विश्व स्तर पर पीवीटी समाधान देता है। इसके अलावा, दो क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणालियां हैं। इसमें भारत से एनएवीआइसी और जापान से क्यूजेडएसएस परिभाषित कवरेज क्षेत्र के लिए नेविगेशन सिग्नल प्रदान करते हैं।

नेविगेशन सिग्नलों को हवाई, अंतरिक्ष, समुद्री और भूमि अनुप्रयोगों से लेकर ट्रैकिंग, टेलीमैटिक्स, स्थान आधारित सेवाओं (सेल फोन और मोबाइल उपकरणों का उपयोग करके), ऑटोमोटिव, सर्वेक्षण, मैपिंग और जीआइएस और विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए फ्री-टू-एयर की पेशकश की जाती है। जीएनएसएस विशेष रूप से अपने संबंधित देशों के रणनीतिक प्रयोगों के लिए सुरक्षित नेविगेशन सिग्नल भी प्रदान करता है क्योंकि फ्री-टू-एयर सिग्नल विरोधियों के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं।

यूरोपीय और इजरायली अंतरिक्ष एजेंसियों की मदद लेगा इसरो

बेंगलुरु, प्रेट्र : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने यूरोपीय और इजरायली अंतरिक्ष एजेंसियां के साथ मिलकर सहोयग बढ़ाने और साथ काम करने के अवसरों की पहचान करने पर चर्चा की है।

जागरण आर्काइव

अंतरिक्ष विभाग के सचिव और इसरो के चेयरमैन के. सिवन ने वर्चुअल बैठक में इजरायली अंतरिक्ष एजेंसी (आइएसए) के महानिदेशक एवी ब्लासबर्ग और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) के महानिदेशक जोसेफ शोबैशर से पिछले हफ्ते चर्चा की थी। सिवन और ब्लासबर्ग ने छोटे उपग्रहों और जीईओ-एलईओ (जियोसिंक्रोनास अर्थ आर्बिट-लो अर्थ आर्बिट) आप्टिकल लिंक के इलेक्ट्रिक प्रपलजन सिस्टम में सहयोग की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय लांचर के जरिये इजरायली उपग्रहों को भविष्य में भेजने और भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर इजरायल के साथ कूटनीतिक रिश्तों पर भी चर्चा हुई है।

कह के रहेंगे माधव जोशी

45 महिलाएं कराएंगी उत्तराखंड के रामनगर स्थित जिम कार्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों को सफारी। चयनित महिलाओं को देहरादून में जिप्सी चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद कार्बेट भारत का ऐसा पहला टाइगर रिजर्व होगा, जहां महिलाएं जिप्सी से सफारी कराएंगी।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
सोमवार 2 अगस्त, 2021

चौटाला चाहते हैं नीतीश करें तीसरे मोर्चे का नेतृत्व

अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़

- नीतीश-चौटाला की बंद कमरे में हुई राजनीति के कई पहलुओं पर चर्चा, केसी त्यागी बने मुलाकात के सूत्रधार
- अपने पुराने मित्र के लिए शाल लेकर आए नीतीश, चौटाला ने अपने हाथ से परोसा भोजन

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला से गुरुग्राम में मुलाकात की। इस दौरान जनता दल यूनाइटेड के महासचिव डा. केसी त्यागी भी मौजूद थे। जागरण

राजनीति में कुछ भी बेमतलब नहीं होता। हर मुलाकात का कोई न कोई मंतव्य छिपा होता है। भले ही उसे शिष्टाचार या कोई और रूप दिया जाए। हरियाणा के पांच बार मुख्यमंत्री रह चुके इनेलो प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रविवार को हुई मुलाकात को भी इसी राजनीतिक मंतव्य की एक कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी माने जाने वाले दोनों मित्र नेता बंद कमरे में घंटों साथ रहे। भोजन भी हुआ और राजनीति पर चर्चा भी। चौटाला की रणनीति है कि उनकी तीसरे मोर्चे की परिकल्पना को साकार करने के लिए नीतीश कुमार उसका नेतृत्व करें। हालांकि नीतीश ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं।

नीतीश कुमार इनेलो प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला के गुरुग्राम स्थित आवास पर मिलने पहुंचे। जनता दल (यू) के महासचिव डा. केसी त्यागी इस मुलाकात के सूत्रधार बने। जेबीटी शिक्षक भर्ती मामले में 10 साल की सजा पूरी कर चौटाला जब जेल से बाहर आए तो त्यागी उनसे मिलने गए थे। उस समय चौटाला की बाजू में फ्रैक्चर था। त्यागी और चौटाला ने उस समय साथ-साथ भोजन किया और दोनों के बीच करीब दो घंटे तक बातचीत हुई।

त्यागी ने वहीं फोन पर चौटाला से नीतीश कुमार की बात कराई। उसी समय नीतीश कुमार ने चौटाला का भोजन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। तब संभावना जताई जाने लगी थी कि सरकारें बनाने और बिगाड़ने में माहिर चौटाला जेल से बाहर आने के बाद चैन से बैठने वाले नहीं हैं।

दोनों नेताओं ने मुलाकात का दिन भी बहुत सोच-समझकर रखा। रविवार को फ्रेंडशिप डे था। नीतीश कुमार अपने पुराने दोस्त के लिए शाल लेकर आए। शाल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया तो अभिभूत चौटाला ने नीतीश कुमार को अपने हाथों से भोजन परोसा। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला और जदयू नेता केसी त्यागी भी इस मुलाकात के गवाह बने। अभय के बेटे करण चौटाला ने नीतीश की अगवानी की। अलग पार्टी बनाने से पहले यह काम दुष्यंत चौटाला किया करते थे।

केसी त्यागी से मुलाकात के बाद चौटाला ने जिस दमखम के साथ यह बयान दिया था कि वह भाजपा और कांग्रेस के विरुद्ध तीसरे मोर्चे का गठन करना चाहते हैं, तभी लग रहा था कि चौटाला कुछ ऐसा करेंगे, जिसके जरिये न केवल इनेलो के काडर बेस कार्यकर्ता को दोबारा पार्टी में पूरी मजबूती के साथ जोड़ा जाए, साथ ही पोते दुष्यंत चौटाला के जननायक जनता पार्टी बनाकर भाजपा के साथ खड़ा होने के फैसले पर भी सवाल उठाए जा सकें। चौटाला अपने पोते दुष्यंत की ज्यादा चर्चा भी नहीं करना चाहते, लेकिन परिवार और पार्टी में बिखराव से हुए नुकसान की भरपाई में पूरा दमखम लगा देना चाहते हैं। तीसरे मोर्चे के गठन की तैयारी चौटाला की इसी रणनीति का हिस्सा है।

अपने और पिता के पुराने मित्रों से होगी चौटाला की मुलाकात

चौटाला अपने पुराने साथियों और पिता चौधरी देवीलाल के मित्रों को बहुत महत्व देते हैं। वह इस बार भी स्व. देवीलाल की जयंती पर 25 सितंबर को राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन करने वाले हैं। यह आयोजन जींद, गुरुग्राम, हिसार या सिरसा में कहीं हो सकता है। चौटाला का दावा है कि तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात के बाद वह इसी जयंती समारोह में तीसरे मोर्चे के गठन का विधिवत एलान कर देंगे। इससे पहले उनकी ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, शरद यादव, चंद्रबाबू नायडू, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और मायावती के साथ मुलाकात होनी है। तीसरे मोर्चे के गठन का ऐसा ही प्रयास पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री स. प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल कर रहे हैं।

नीतीश कुमार सही मायने में पीएम मैटेरियल : कुशवाहा

राज्य ब्यूरो, पटना

- जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण हैं नीतीश में

जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने जाति आधारित जनगणना के बहाने रविवार को महत्वपूर्ण बात कह दी कि नीतीश कुमार सही मायने में पीएम मैटेरियल हैं। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त जिन कुछ अन्य लोगों में प्रधानमंत्री पद संभालने की क्षमता है, उनमें नीतीश कुमार प्रमुख हैं।

जाति आधारित जनगणना के संदर्भ में कुशवाहा ने कहा कि इसके लिए देश में माहौल बनना चाहिए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में लोग जाति आधारित जनगणना के लिए एकजुट हों। इसी क्रम में उन्होंने जोड़ा कि नीतीश कुमार पीएम मैटेरियल हैं। उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी को चुनौती दिए जाने की कोई बात नहीं कह रहा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में पूरी एकजुटता है। मोदी अच्छा काम भी कर रहे, परंतु उनके अतिरिक्त भी देश में लोग हैं, जो प्रधानमंत्री पद के लिए क्षमता रखते हैं। उपेंद्र ने कहा कि राजनाथ सिंह ने संसद में यह बात कही है कि अगली बार जनगणना होगी तो साथ में जाति आधारित जनगणना भी कराई जाएगी। इसलिए इस बात से केंद्र की सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर इस बार पुनः जाति आधारित जनगणना नहीं होती है तो दस वर्ष और इंतजार करना पड़ेगा। यह अच्छा नहीं है।

नीतीश बोले, हम काहे के लिए पीएम मैटेरियल रहेंगे... : बिहार के सीएम नीतीश कुमार से रविवार को जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हम काहे के लिए पीएम मैटेरियल रहेंगे। इन सब चीजों में मेरी दिलचस्पी नहीं। दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होकर रविवार को पटना लौटे नीतीश ने कहा कि जाति आधारित जनगणना के समर्थन में जो लोग हैं, वे सभी एक साथ पीएम नरेंद्र मोदी से मिलकर अपना पक्ष रखेंगे। कौन-कौन से लोग इस मसले पर प्रधानमंत्री से मिलने साथ में जाएंगे, इस बारे में वे सभी से बात करेंगे।

बाबुल सुप्रियो को मनाने की भाजपा ने कोशिश की तेज

कवायद ▸ सांसद जगन्नाथ बोले, बंगाल में पार्टी को उनकी जरूरत

राजनीति छोड़ने की घोषणा के बाद देर रात भाजपा अध्यक्ष से भी मिले बाबुल

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

भाजपा ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा करने वाले बंगाल के आसनसोल से पार्टी सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को मनाने की कोशिश तेज कर दी है। फेसबुक पोस्ट के जरिये राजनीति छोड़ने की घोषणा के कुछ ही घंटे बाद देर रात खुद बाबुल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने उनके घर पर पहुंचे और दोनों के बीच बैठक हुई। जानकारी के मुताबिक, इस दौरान नड्डा ने बाबुल को इस फैसले पर विचार करने को कहा है।

दूसरी ओर, बंगाल के राणाघाट से भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि भाजपा को सुप्रियो की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सुप्रियो पार्टी में बने रहेंगे और उन्हें पार्टी की बंगाल इकाई में कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएंगी।

बाबुल सुप्रियो। फाइल/इंटरनेट मीडिया

दूसरी ओर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी रविवार को कहा कि बाबुल पार्टी में ही हैं और रहेंगे। हालांकि एक दिन पहले घोष ने कहा था कि पार्टी में रहना व जाना किसी का निजी फैसला है।

इस बीच खबर है कि बाबुल मंगलवार तक पार्टी और राजनीति छोड़ने एवं सांसद पद से इस्तीफा देने के बारे में अंतिम निर्णय ले सकते हैं। दरअसल बाबुल ने शनिवार को कहा था कि वह राजनीति छोड़ रहे हैं और एक महीने के भीतर सांसद पद से भी इस्तीफा दे देंगे।

दिलीप घोष व टीएमसी नेता कुणाल घोष पर बाबुल ने साधा निशाना

राजनीति को अलविदा कहने पर लोगों ने कई तरह की प्रतिक्रिया की है, जिस पर बाबुल ने फेसबुक पर एक और पोस्ट किया। इसमें उन्होंने बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रवक्ता कुणाल घोष पर निशाना साधते हुए अपनी भावी योजना पर भी प्रकाश डाला। बाबुल ने लिखा कि अब दिलीप घोष और टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष की टिप्पणियों से हर रोज उन्हें नहीं जूझना पड़ेगा। वहीं, बाबुल के इस बयान पर दिलीप घोष ने कहा कि लोग मेरे बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, इस पर मैं ध्यान नहीं देता। मेरा महत्व है, इसीलिए लोग मुझ पर निशाना साधते हैं। दूसरी और कुणाल घोष ने कहा है कि बाबुल सुप्रियो नाटक कर रहे हैं। अगर उन्हें राजनीति छोड़ने ही है तो संसद सत्र चल रहा है, जाकर लोकसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा दे दें।

परिवर्तन पर सगुण और निर्गुण भाव के साथ सामने आ रहे जदयू दिग्गज

राज्य ब्यूरो, पटना : परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जो होगा अच्छा ही होगा और जो हो रहा वह भी अच्छा। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की ताजपोशी के बाद जदयू के दिग्गज कुछ इसी अंदाज में सगुण और निर्गुण भाव के साथ इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर सामने आए। पार्टी के निर्वतमान राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर लिखा कि दल हो या जीवन हमारी और आपकी भूमिकाएं समय-समय पर बदलती रहती हैं। जदयू मेरे लिए पार्टी मात्र नहीं, बल्कि यह जीवन का पर्याय बन चुकी है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक मेरी हर सांस पार्टी और पार्टी के साथियों के साथ जुड़ी होती है। मेरे अजीज साथी ललन बाबू को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई।

जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर कहा कि आशा नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ललन सिंह के नेतृत्व में जदयू जल्द नई ऊंचाइयों को छुएगा। बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने सगुण भाव में लिखा कि मुझे विश्वास है कि ललन सिंह के सक्षम नेतृत्व में पार्टी के संगठन को नया विस्तार मिलेगा।

बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर लिखा कि आपकी कर्तव्यनिष्ठा, संगठन में दायित्वों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता पार्टी और कार्यकर्ताओं को नई गति देने का काम करेगी।

भविष्य के लिहाज से अपनी चौहद्दी दुरुस्त करने में जुटे हैं बिहार के दल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सियासत

- बड़े दलों में महसूस की जाने लगी है छोटे दलों के साथ गठबंधन की जरूरत
- जातिगत समीकरणों को भी दुरुस्त करने में जुटे हैं सभी प्रमुख दल

उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी कई प्रयोग हो चुके हैं- पहले राजग गठबंधन, फिर महागठबंधन और फिर से राजग। भाजपा, जदयू और राजद मुख्य खिलाड़ी रहे जबकि छोटे दलों का खेमा बदलता रहा है। हालांकि वर्तमान गठबंधन सही चल रहा है लेकिन धीरे-धीरे इन तीनों प्रमुख दलों ने अपनी चौहद्दी जिस तरह मजबूत करनी शुरू की है, वह भविष्य की आहट देने लगा है। कमोबेश इन दलों में यह कवायद महसूस की जा रही है कि बड़े दलों के साथ हिस्सेदारी और परिणामस्वरूप आने वाले दबाव के बजाय छोटे दलों के समूह के साथ भविष्य की राह गढ़ी जानी चाहिए।

तीनों दलों के नेतृत्व पर ध्यान देने की जरूरत है। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद हैं और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, अगड़ी जाति से। उन्होंने हाल में इस्तीफे की पेशकश की थी लेकिन उन्हें मना लिया गया। नीतीश कुमार जहां खुद मुख्यमंत्री हैं। जदयू के प्रदेश संगठन की कमान वशिष्ठ नारायण सिंह की जगह उमेश कुशवाहा के हाथों में दी गई थी। अब पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद अगड़ी जाति से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को सौंपी गई।

भाजपा ने चुनाव से पहले संजय जायसवाल के हाथों संगठन की कमान दी थी और उपमुख्यमंत्री पद पर अति पिछड़ी जाति की रेणु देवी और ओबीसी से आने वाले तारकिशोर प्रसाद को बिठाया था। बिहार के कोटे से केंद्रीय मंत्रियों की बात की जाए तो हाल ही में गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास जैसा अहम मंत्रालय दिया गया। गिरिराज भी उसी प्रभावी भूमिहार जाति से आते हैं जिससे ललन सिंह। नित्यानंद राय के रूप में भी बिहार से केंद्रीय कैबिनेट में प्रतिनिधित्व है और और अश्विनी चौबे के रूप मे ब्राह्मण चेहरा भी शामिल है। जबकि जदयू के कोटे से आरसीपी सिंह ओबीसी से आते हैं। रोचक यह है कि अब तक सिर्फ एक मंत्री पद के प्रस्ताव से इनकार कर रहा जदयू इस बार क्यों माना। एक अटकल यह भी है कि लोजपा के खाते से आए पशुपति पारस के मंत्री बनाए जाने में भी क्या जदयू की भूमिका रही।

राजीव रंजन सिंह को हाल ही में जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। फाइल/इंटरनेट मीडिया

सभी दलों में मंथन तेज

सूत्रों की मानी जाए तो फिलहाल बिहार में राजग सरकार सही दिशा और गति से चल रही है। लेकिन भविष्य के लिए सभी दलों में मंथन तेज है। अब तक यह गणित भी काम करता रहा है कि जिधर दो दल मिल जाएंगे सरकार उसी की बनेगी। पर अब तीनों दल इससे आगे बढ़ना चाहते है। इसीलिए आने वाले दिनों में हर दल की ओर से छोटे दलों को अपनी ओर खीचने की ज्यादा कोशिश होगी। जदयू संगठन में हुआ नेतृत्व परिवर्तन भी इसी लिहाज से देखा जा रहा है। बताने की जरूरत नहीं है कि बिहार चुनाव से पहले जदयू से बागी हुए नेता जीतन राम मांझी की वापसी हो गई थी। बाद में कभी राजग तो कभी संप्रग में छलांग लगाते रहे उपेंद्र कुशवाहा भी जदयू के हिस्सा हो गए।

मप्र के मंत्री ने कहा-मेरे बच्चे नहीं लेंगे आरक्षण का लाभ

नईदुनिया, भोपाल

पहल

- कहा, आरक्षण लेना या नहीं लेना, व्यक्तिगत मामला
- मेडिकल कालेजों में ईडब्ल्यूएस व ओबीसी को आरक्षण की प्रशंसा की

मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रामखिलावन पटेल ने रविवार को कहा कि उनकी दोनों बेटियां पढ़ाई और नौकरी में आरक्षण का लाभ नहीं लेंगी। हालांकि समाज से अपील करने की बात पर मंत्री ने कहा कि यह व्यक्तिगत मामला है। किसी को आरक्षण लेने या न लेने को नहीं कहा जा सकता है।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को मेडिकल कालेजों में 27 फीसद एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10 फीसद आरक्षण देने के केंद्र सरकार के निर्णय की प्रशंसा की। कहा कि यह ऐतिहासिक निर्णय है। इससे वर्तमान शैक्षणिक सत्र में एमबीबीएस में 550 और पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों में एक हजार से ज्यादा ईडब्ल्यूएस विद्यार्थियों को लाभ होगा।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कमल नाथ सरकार ने ओबीसी को 27 फीसद आरक्षण का लाभ तो दिया, पर स्थगन भी ले लिया। इस कारण इस वर्ग को लाभ नहीं मिल पाया। भाजपा की सरकार बनने के बाद इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई और सरकार ने हर सुनवाई में महाधिवक्ता को भेजा। असर यह हुआ कि कोर्ट ने 14 फीसद आरक्षण दे दिया और 13 फीसद को रोका है, जो जल्द ही मिलेगा।

ऐसी घोषणा के कोई मायने नहीं : मध्य प्रदेश के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता अजय मिश्रा ने कहा कि ऐसी घोषणा के कोई मायने नहीं हैं क्योंकि ओबीसी में क्रीमीलेयर की व्यवस्था पहले से लागू है। ऐसे में किसी परिवार की वार्षिक आय आठ लाख रुपये से ज्यादा है, तो परिवार स्वतः आरक्षण के दायरे से बाहर हो जाता है। ये जबरिया की घोषणा है।

गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बीच जुबानी जंग हुई तेज

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

गुजरात में भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गांधीनगर में कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित भाई चावड़ा अब जाने की घड़ियां गिन रहे हैं, इसलिए वह गलत बयानबाजी कर रहे हैं। विपक्षी पार्टी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा महासचिव को रातोंरात बदला जाना मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की विदाई का संकेत है। दोनों पार्टियों के एक-दूसरे पर हमले से गुजरात की राजनीति में गर्माहट आ गई है।

गौरतलब है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को गुजरात भाजपा संगठन महासचिव के पद पर रत्नाकर की नियुक्ति कर दी। रत्नाकर को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल का करीबी माना जाता है।

उधर, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने भी कहा कि जनता ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह नकार दिया है। कुछ महीने पहले हुए पालिका और पंचायत चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह साफ हो गई। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीने से कांग्रेस आलाकमान अनिर्णय की स्थिति में है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चावड़ा और नेता विपक्ष परेश धनाणी की अपने-अपने पदों से विदाई निश्चित है।

देश-विदेश के विद्यार्थी पहुंच रहे हैं गुजरात

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद : गुजरात में शिक्षा के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। आयुर्वेद, रक्षा, फोरेंसिक साइंस और योग के विश्वविद्यालय यहां बनाए गए हैं। देश-विदेश के विद्यार्थी पढ़ने के लिए गुजरात आ रहे हैं। राज्य के गांव-गांव तक ब्राडबैंड की सुविधा पहुंच गई है। राज्य की जनता ने भाजपा को अपना आशीर्वाद दिया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि उनकी सरकार के पांच साल पूरे होने का यह उत्सव नहीं, बल्कि सेवा यज्ञ है। गुजरात को 13 वर्ष तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मिला है। आज देश में गुजरात माडल की चर्चा है। रूपाणी सरकार के पांच साल पूरे होने पर रविवार को ज्ञान शक्ति दिवस के रूप में मनाते हुए राज्य सरकार ने समारोहों की शुरुआत की। दूसरी ओर कांग्रेस ने इसके समानांतर शिक्षा बचाओ कार्यक्रम आयोजित कर सरकार का विरोध किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा एवं अन्य नेताओं ने अहमदाबाद के अंबाबाड़ी क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित कर 'शिक्षा बचाओ और रूपाणी सरकार होश में आओ' के नारे लगाए। इससे पहले प्रदेश के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कांग्रेस पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस को दशकों तक शासन करने का मौका मिला, लेकिन वह गुजरात का विकास नहीं कर पाई। अब विजय रूपाणी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल के नेतृत्व में गुजरात सरकार जनहित में काम कर रही है।

पंजाब में मुख्यमंत्री के लिए आप जल्द घोषित करेगी चेहरा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- पंजाब विस चुनाव को लेकर सीएम केजरीवाल ने की बैठक

पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) रणनीति बनाने में जुटी हुई है। पार्टी जल्द ही तय करने जा रही है कि पंजाब में सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कौन होगा। दरअसल, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पंजाब से पार्टी के विधायकों और प्रमुख नेताओं की रविवार को बैठक हुई है। इसमें विधायकों ने जल्द से जल्द पंजाब में मुख्यमंत्री के लिए पार्टी का चेहरा घोषित करने की मांग की। सूत्रों के मुताबिक इस पर बैठक में चर्चा भी हुई। माना जा रहा है कि पंजाब के ही किसी नेता पर पार्टी दांव लगाएगी।

बैठक के बाद आप के पंजाब अध्यक्ष एवं सांसद भगवंत मान ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने पर चर्चा की गई। पंजाब के विधायकों से एक-एक गांव और बूथ का ब्योरा लिया गया और उन पर विस्तार से बात हुई। पार्टी पिछली कमियों को दूर कर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। आप राजनीति से ऊपर उठकर किसानों की सेवा करेगी और आगामी दिनों में किसानों को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं की जाएंगी। मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा के सवाल पर मान ने कहा कि अभी तो सिर्फ विधायकों के राजनीतिक माहौल को लेकर बैठक हुई है। बहुत से विधायकों ने कहा कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर देना चाहिए। इस पर पार्टी संयोजक केजरीवाल ने कहा है कि वह जल्द ही इसकी घोषणा करेंगे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पार्टी के प्रधान हैं, उनका पंजाब में आना-जाना लगा रहेगा। कहा कि विधायक खुश हैं कि आप पंजाब में बहुत अच्छा कर रही है। करीब तीन घंटे तक चली इस बैठक में आप के पंजाब प्रभारी व विधायक जरनैल सिंह और सह प्रभारी एवं विधायक राघव चड्ढा, सभी विधायक और पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हरपाल सिंह चीमा आदि भी मौजूद थे।

विवाद : भाजपा एमएलसी की शिवसेना मुख्यालय पर टिप्पणी को लेकर तकरार

- पूर्व में सहयोगी रहे दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे के प्रति सख्त किया लहजा

मुंबई, प्रेट्र : महाराष्ट्र में भाजपा के विधान पार्षद (एमएलसी) की शिवसेना मुख्यालय पर कथित टिप्पणी को लेकर दोनों दलों में जुबानी जंग शुरू हो गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने रविवार को कहा कि 'मराठी मानुष' 'नशे के आदी नेताओं' को नहीं छोड़ेंगे। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा कि अगर कोई भाजपा पर हमला करता है तो पार्टी उसका उचित जवाब देगी।

भाजपा एमएलसी प्रसाद लाड ने शनिवार को एक पार्टी कार्यक्रम में कहा था कि अगर शिवसेना भवन (शिवसेना मुख्यालय) को गिराने की जरूरत पड़ी तो ऐसा किया जाएगा। हालांकि, बाद में उन्होंने खेद जताते हुए कहा कि उनके बयान को मीडिया ने गलत संदर्भ में पेश किया। उन्होंने अपनी टिप्पणी भी वापस ले ली थी। एक वीडियो संदेश में लाड ने कहा, 'मेरे मन में दिवंगत बाला साहेब ठाकरे के लिए अगाध सम्मान है। मैं शिवसेना भवन को पवित्र स्थान मानता हूं। मेरे कहने का अभिप्राय था कि आगामी बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव में भाजपा प्रतिद्वंद्वी शिवसेना को हरा देगी।' इसके बावजूद दोनों पार्टियों में जुबानी जंग शुरू हो गई।

शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता व राज्यसभा सदस्य राउत ने कहा, 'महाराष्ट्र में तुरंत नशामुक्ति कार्यक्रम चलाने की जरूरत है। वर्ना, शिवसेना भवन के सामने की फुटपाथ पर मराठी मानुष नशे के आदी इन नेताओं को नहीं छोड़ेंगे। शिवसेना भवन मराठी अस्मिता का चमकता हुआ प्रतीक है...समझने वालों को इशारा ही काफी है।' इससे पहले शिवसेना प्रमुख व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक कार्यक्रम में कहा, 'किसी को भी हमें थप्पड़ मारने की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि हम जवाब में इतना जोरदार थप्पड़ मारेंगे कि वे अपने पैरों पर भी वापस नहीं जा सकेंगे।'

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष फड़नवीस ने कहा कि विध्वंसक राजनीति भाजपा की संस्कृति नहीं है। उन्होंने कहा, 'हम पहले किसी पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने हमपर हमला किया तो चुप नहीं बैठेंगे। प्रभावी जवाब देंगे।' भाजपा विधायक नितेश राणे ने ट्वीट किया, 'आप सही हैं राउत साहब... महाराष्ट्र को नशामुक्त करने की जरूरत है... और इसकी शुरुआत कलानगर से होनी चाहिए।' गौरतलब है कि ठाकरे का निजी आवास मातोश्री मुंबई के कलानगर इलाके में स्थित है।

उप्र की 105 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगा वैश्य समाज

जासं, मथुरा : अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद की राष्ट्रीय व प्रांतीय कार्यसमिति बैठक में कई प्रस्ताव पास हुए।

परिषद ने निर्णय लिया कि उप्र में वैश्य बाहुल्य 105 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे। वृंदावन में एक होटल में परिषद की राष्ट्रीय व प्रांतीय कार्यसमिति बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. सुमंत गुप्ता ने कहा कि वैश्य समाज पैसा देता है, टैक्स देता है, लेकिन उसे राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलती। वैश्य समाज आज भी अछूता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल वैश्य समाज को अकेला न समझें। वैश्य समाज अब जाग चुका है। वह राजनीतिक भागीदारी चाहता है। केंद्रीय राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के समक्ष परिषद पदाधिकारियों ने जीएसटी में संशोधन की मांग रखी। मंत्री ने कहा कि वैश्य समाज राजनीतिक भागीदारी का मुख्य केंद्र है। जो राजनीतिक दल इस समाज से खुद को दूर रखेगा, उस दल को खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

बंगाल के कई सांसद और विधायक विभिन्न मामलों में भगोड़े

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- कलकत्ता हाई कोर्ट की आंतरिक रिपोर्ट में महापंजीयक ने किया उल्लेख

कलकत्ता उच्च न्यायालय की आंतरिक रिपोर्ट में महापंजीयक ने उल्लेख किया है कि राज्य के कई सांसद व विधायक विभिन्न मामलों में भगोड़े हैं। हाल में हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य के सांसदों व विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए निचली अदालतों को निर्देश दिया था। मामलों की स्थिति जानने के लिए हाई कोर्ट के महापंजीयक ने यह आंतरिक रिपोर्ट तैयार की है। इसमें कहा गया है कि कोलकाता के बिधाननगर स्थित एमपी-एमएलए अदालत में ज्यादातर विधायकों व सांसदों को भगोड़ा बताया गया है, जिसके कारण मामला ही शुरू नहीं हो पाया है। कार्यवाही की धीमी गति के कारणों का उल्लेख किया गया है। मसलन अदालत में नौ कर्मचारियों की जरूरत है, जबकि वास्तविक में चार कर्मचारी ही हैं।

अदालत में रिपोर्ट देखकर राज्य के मुख्य लोक अभियोजक शाश्वत गोपाल मुखर्जी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि सांसद व विधायक भगोड़े कैसे हो सकते हैं। यह आश्चर्य की बात है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के निर्देश पर महापंजीयक विभाग यह रिपोर्ट राज्य और केंद्र सरकार को भेजेगा। रिपोर्ट की समीक्षा के बाद केंद्र और राज्य सरकारों को हलफनामे के साथ अदालत को सूचित करना होगा कि मामलों के त्वरित निपटारे के लिए क्या किया जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई नौ अगस्त को है।

बंगाल में सीआइडी ने 27,267 मामलों की चार्जशीट समय पर नहीं दी है। इसे लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने कड़ी चेतावनी दी है। एक स्वतः संज्ञान मामले के परिप्रेक्ष्य में उच्च न्यायालय को सौंपी गई रिपोर्ट में महापंजीयक विभाग की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। इनमें से भारतीय दंड संहिता की 121 यानी देशद्रोह के अलावा अपहरण समेत सबसे जघन्य अपराध की चार्जशीट भी अटकी हुई है। 12 साल में कई मामले दर्ज नहीं हुए हैं। हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की खंडपीठ ने इस तरह की जानकारी से नाराजगी जताई। हालांकि सीआइडी का तर्क है कि मामलों में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाने के कई कारण हैं।

पंजाब में उद्योगों को झटका, 33 फीसद तक बढ़ सकता है ट्रांसपोर्टेशन खर्च

बढ़ेगी समस्या ▶ फास्ट गुड्स मूवमेंट होगी चुनौती, कंटेनर तेजी से भेजने में मिलती थी मदद

पंजाब से दूसरे राज्यों को सामान भेजना और एक्सपोर्ट भी होगा महंगा

मुनीश शर्मा, लुधियाना

लुधियाना के किला रायपुर स्थित अदाणी लाजिस्टिक्स पार्क के बंद होने से पंजाब के उद्योगों को बड़ा झटका लगा है। पोर्ट से दूरी और सीमावर्ती राज्य होने के चलते पंजाब के उद्योगों का तैयार माल दूसरे राज्यों और अन्य देशों को भेजना सबसे बड़ी चुनौती रहती है। इस पर माल जल्दी और कम लागत में भेजना हर उद्योगपति की प्राथमिकता रहती है। कच्चा माल लाने से लेकर एक्सपोर्ट के लिए समय पर सामग्री पहुंचाने के लिए कई दिन लग जाते हैं। अदाणी लाजिस्टिक्स पार्क ने फास्ट गुड्स मूवमेंट यानी सामान को तेजी से लाने व ले जाने के सिस्टम को पंजाब में नई दिशा दी थी। फ्रेट कारिडोर पर बल्क में सामान लाकर उद्योगों का 33 फीसद खर्च बचाने के लिए बनाए गए इस लाजिस्टिक पार्क के बंद होने से उनका खर्च 33 फीसद तक बढ़ सकता है। यहां रोज करीब 120 कंटेनर लोड व अनलोड होते थे।

अदाणी ग्रुप के पास खुद के यार्ड और जहाज हैं। इससे फास्ट मूवमेंट हो पा रही थी। उद्योगों को इससे काफी राहत मिल रही थी। जो सामान भेजने के लिए आम तौर पर 20 से 25 दिन का समय लगता था, वही तैयार माल अदाणी लाजिस्टिक्स की वजह से ग्राहकों तक 10 से 15 दिनों में पहुंचा रहा था। बड़ी प्राइवेट कंपनी के इस क्षेत्र में आने से जवाबदेही तय थी और दूसरी कंपनियों भी दबाव में थी, लेकिन अब अदाणी लाजिस्टिक्स के बंद होने से बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।

इसी जगह पर वेयरहाउसिंग कारपोरेशन का भी लाजिस्टिक पार्क है। पंजाब जैसे लैंड लाक राज्य के उद्योगों के लिए अदाणी लाजिस्टिक्स पार्क उनके खर्च को कम कर उन्हें दूसरे राज्यों के उद्योगों के मुकाबले प्रतिस्पर्धा की दौड़ में बनाए रखने में सहायक सिद्ध हो रहा था। किसान आंदोलन के कारण जिस तरह से राज्य में रिलायंस और अदाणी के कारोबार को निशाना बनाया जा रहा है, इसका असर आने वाले समय में दूसरे उद्योगों पर भी पड़ना तय है।

बड़ा समूह पंजाब आने से कतराएगा : अदाणी ग्रुप के पास पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर है और इसका लाभ पंजाब के उद्योगों को मिल रहा था। इसके बंद होने से तत्काल नुकसान तो होगा ही, लेकिन कोई बड़ा समूह दोबारा पंजाब आने से परहेज करेगा। कन्फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआइआइ) के पूर्व चेयरमैन राहुल आहूजा कहते हैं कि लुधियाना ड्राई पोर्ट की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसमें प्राइवेट प्लेयर्स के आने से एक नया बदलाव देखने को मिल रहा था। पंजाब के कारोबारियों के लिए ट्रांसपोर्टेशन एक अहम हिस्सा है। ऐसे में अगर यह प्रोजेक्ट बंद हो जाता है, तो फास्ट मूवमेंट में परेशानी होगी। चैंबर आफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग्स (सीआइसीयू) के अध्यक्ष उपकार आहूजा का मानना है कि पंजाब से एक्सपोर्ट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में इस कदम के बाद कोई बड़ी कंपनी पंजाब का रुख नहीं करेगी।

बड़ी कंपनी का इस तरह जाना घातक : रैमसन एक्सपोर्ट्स के एमडी वरुण कपूर कहते हैं कि किसी भी बड़ी कंपनी का इस तरह काम बंद करना बहुत घातक है। एक्सपोर्ट के लिए लाजिस्टिक्स पार्क की भूमिका अहम है। अदाणी समूह के पास पर्याप्त संसाधन हैं। ऐसे में उनका जाना बेहद चिंताजनक है।

लुधियाना के गांव किला रायपुर में अदाणी लाजिस्टिक के बाहर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से उसके मुख्य द्वार पर लगाई गई ट्रैक्टर ट्राली जो जनवरी माह से यहां खड़ी है। कुलदीप काला

एक्सपोर्ट-इंपोर्ट को लगेगा धक्का

अदाणी लाजिस्टिक्स से पंजाब से कई अहम उत्पाद एक्सपोर्ट के लिए भेजे जाते थे। इंपोर्ट में भी कच्चे माल को लेकर इस पार्क की भूमिका अहम रही है। यहां से स्क्रैप, मशीनरी, ड्राई फ्रूट्स, वेस्ट पेपर, ट्रैक्टर, वूलन, यार्न सहित कई अहम उत्पाद इंपोर्ट व एक्सपोर्ट के लिए आते जाते थे। अदाणी ग्रुप के पास खुद का इन्फ्रास्ट्रक्चर होने के चलते इसका किराया कम था। यहां से हीरो साइकिल, वर्धमान, वर्धमान स्पेशल स्टील, पीआर लाजिस्टिक्स जालंधर, अमृतसर के राइस एक्सपोर्टर, खन्ना पेपर मिल सहित कई कंपनियों का माल आता-जाता है।

वोट बैंक खोने के डर से बोलने से घबरा रहीं पार्टियां

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

एक तरफ पंजाब सरकार 'इन्वेस्ट पंजाब' मुहिम चलाकर राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने का प्रयास कर रही है, घर-घर नौकरी का वादा कर रही है। वहीं, दूसरी तरफ कृषि सुधार कानून का विरोध कर रहे अड़ियल किसानों के साथ खड़ी होकर रोजगार के रास्ते बंद कर रही है। किसान आंदोलन के कारण पंजाब में 400 युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से और सैकड़ों लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार देने वाले अदाणी समूह ने लुधियाना के रायकोट में स्थित अपना लाजिस्टिक्स पार्क बंद कर दिया, लेकिन सरकार ने इस मुद्दे पर बात तक नहीं की। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राजस्व को 700 करोड़ रुपये के नुकसान पहुंचाने वाले इस कदम पर चिंता तक नहीं जताई। एक हफ्ता पहले जब आदित्य बिरला समूह ने लुधियाना में 1000 करोड़ रुपये के निवेश करके पेंट फैक्ट्री और राजपुरा में 500 करोड़ रुपये से सीमेंट यूनिट लगाने की घोषणा की, तो मुख्यमंत्री ने खुले दिल से स्वागत किया था। राज्य के उद्योग मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा ने 91 हजार करोड़ रुपये के निवेश का दावा किया था, लेकिन अदाणी लाजिस्टिक्स पार्क के मुद्दे पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे वास्तविक स्थिति का अंदाजा नहीं है कि लाजिस्टिक्स पार्क बंद क्यों किया गया।

लुधियाना के गांव किला रायपुर में अदाणी लॉजिस्टिक्स के आगे जनवरी माह से धरने पर बैठे हुए संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य। कुलदीप काला

भाजपा ने सरकार को घेरा

सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही इस पर खुल कर बोल रही है। पार्टी महासचिव जीवन गुप्ता का कहना है कि सरकार पंजाब के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। पंजाब में निवेश तो आ नहीं रहा, बल्कि जिन कंपनियों ने निवेश किया भी है वे भी काम बंद कर रही हैं।

केजरीवाल बोले- पार्टी के झंडे व एजेंडे को छोड़ किसान आंदोलन को सहयोग दें

पंजाबियों के हितों की बात करने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी को भी 400 युवाओं का रोजगार छिन जाने में कोई अहित नहीं दिखा।

किसान वोले, किराए पर भी दिया तो भी नहीं होने देंगे काम

लाजिस्टिक्स पार्क के मुख्य गेट के बाहर धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि यदि इसे किराए पर भी दिया गया या इसका नाम बदल कर चलाने की भी कोशिश की गई तो भी हम यहां काम शुरू नहीं होने देंगे। किसानों ने मुख्य गेट के आगे ट्रैक्टर खड़े कर रखे हैं। आने-जाने का रास्ता बंद कर रखा है। जम्हूरी किसान सभा पंजाब के जिला कार्यकारिणी सदस्य हरनेक सिंह गुज्जरवाल का कहना है कि जिन कर्मियों की नौकरी गई है, वह लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं।

बिजली कंपनियों के साथ समझौते रद होने से टूटेगा भरोसा

पड़ेगा भारी

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़

▸ सरकार ने तलवंडी साबो प्लांट के साथ करार रद करने का लिया है फैसला

▸ पिछली सरकार में हुए 122 समझौतों की समीक्षा की भी तैयारी

पंजाब सरकार ने भले ही राजनीतिक दबाव में पिछली सरकार के कार्यकाल में बिजली कंपनियों के साथ हुए समझौते रद करने और उनकी समीक्षा के आदेश दे दिए हों, लेकिन यह फैसला पंजाब सरकार की निवेश की मुहिम को नुकसान पहुंचा सकता है। कैप्टन सरकार इसका कोई समाधान खोजने के बजाय निजी थर्मल प्लांटों के साथ हुए समझौतों को रद करने के फैसले लेकर उद्योगों के लिए नई मुसीबत खड़ी कर रही है। मुख्यमंत्री के 1920 मेगावाट के तलवंडी साबो थर्मल प्लांट से किए गए समझौते को रद करने का आदेश पंजाब को महंगा पड़ सकता है। इससे निवेशकों का भरोसा टूट सकता है।

इसके अलावा सोलर, को-जेनरेशन आदि के लिए 122 बिजली समझौतों की भी समीक्षा करने को कहा गया है। इससे निवेश पर असर पड़ सकता है। इन्वेस्ट पंजाब के अधिकारी इस फैसले से काफी आहत हैं। उन्हें हैरानी है कि कुछ ही समय पहले खुद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एलान किया था कि बिजली प्लांटों के साथ किए गए समझौते रद नहीं किए जाएंगे, क्योंकि इससे निवेश पर असर पड़ता है और बड़ी कंपनियों का पंजाब पर विश्वास डगमगाता है, लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टियों के साथ-साथ उनकी अपनी पार्टी के नेताओं ने बिजली समझौते रद करने को लेकर सरकार पर दबाव बनाया है, उससे मुख्यमंत्री ने इन समझौतों को रद करके फरवरी में बनने वाली नई सरकार के पाले में गेंद सरका दी है।

निवेशकों को मनाना मुश्किल

इन्वेस्ट पंजाब के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि निवेशकों को प्रदेश में निवेश करने के लिए मनाना बहुत मुश्किल है। अगर लुधियाना में लगने वाले बिरला ग्रुप के पेंट के कारखाने और राजपुरा में सीमेंट के प्लांट को छोड़ दिया जाए तो कोई भी बड़ा प्लांट नहीं आया है।

टैक्स हालीडे से भी पिछड़ी इंडस्ट्री

पंजाब की इंडस्ट्री पहले से ही आतंकवाद और पहाड़ी राज्यों को दिए गए टैक्स हॉलीडे के कारण बहुत पिछड़ गई है। आतंकवाद प्रभावित स्टेट का टैग अभी भी राज्य के माथे से उतर नहीं पाया है। इसलिए आटो मोबाइल कोई भी बड़ा यूनिट नहीं आया है। टाटा नैनो और फाक्सवैगन यहां अपने प्लांट स्थापित करने के इच्छुक थे, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ी।

2002 के बाद हिमाचल में हुआ विस्तार

आतंकवाद अभी खत्म ही हुआ था कि 2002 में केंद्र सरकार ने पहाड़ी राज्यों में उद्योग लगाने वालों को कर रियायतों का एलान करके रही सही कसर भी पूरी कर दी। पंजाब से बहुत से यूनिटों ने राज्य में विस्तार न करके हिमाचल के बद्दी, नालागढ़ आदि में निवेश किया। 2016 में ये रियायतें खत्म हुईं और राज्य में निवेश की संभावनाएं बढ़ ही रही थीं कि पहले किसान आंदोलन और अब बिजली के समझौतों को रद करने से बिजली की कमी से उभरी निवेश को प्रभावित कर सकती है।

पहले ही राज्य की इंडस्ट्री शिफ्ट कर गई है, लेकिन अब बिजली की कमी और समझौते रद करने जैसे कदम पंजाब के लिए घातक हो सकते हैं।

पोंछे बुजुर्ग दंपती के आंसू...बेटे-बहू को भेजा जेल

जागरण संवाददाता, कानपुर

बालीवुड फिल्म 'बागबान' की तरह कानपुर के चकेरी निवासी बुजुर्ग दंपती अपनों द्वारा अपनी बगिया से बेदखल होकर दर-दर की ठोकर सहते हुए सुबक रहा था। कोई राह न दिखी तो दंपती ने पुलिस से गुहार लगाई। मित्र पुलिस की मिसाल कायम करते हुए पुलिस आयुक्त ने इसका स्वतः संज्ञान लिया और बुजुर्ग के घर पहुंचे। खाकी ने न सिर्फ बागबां के आंसू पोंछे, बल्कि बेटे-बहू की करतूत पर उन्हें सबक सिखाते हुए जेल की राह दिखा दी। दोनों अब तीन दिन तक सलाखों के पीछे रहेंगे।

दरअसल, बुजुर्ग अनिल कुमार शर्मा के परिवार में उनकी पत्नी, बेटा अभिषेक और बहू हैं। अनिल कुमार का दो माह पूर्व किसी बात को लेकर बेटे-बहू से विवाद हो गया था। आरोप है कि इसके बाद बेटे और बहू ने उनके साथ मारपीट की। इस पर सात दिन पूर्व बुजुर्ग ने चकेरी थाने में बेटे और बहू के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। बुजुर्ग दंपती ने इसकी शिकायत थाने और डीसीपी पूर्वी से भी की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दो दिन पहले बेटे और बहू ने दोबारा मारपीट करते हुए बुजुर्ग माता-पिता को घर से निकाल दिया था। इस पर पीड़ित दंपती ने पुलिस आयुक्त असीम अरुण से शिकायत की। शनिवार रात मामला संज्ञान में आने पर बुजुर्ग दंपती को साथ लेकर फोर्स संग उनके घर पहुंचे। वहीं, बुजुर्ग दंपती से मारपीट करने के आरोप में उनके बेटे अभिषेक और बहू को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया था।

बेटे-बहू द्वारा पीड़ित बुजुर्ग से बात करते पुलिस आयुक्त असीम अरुण। वीडियो ग्रैब

> बुजुर्ग माता-पिता को अपमानित करने वालों के लिए यह सबक है। आगे अगर कहीं भी इस तरह की शिकायत मिलती है तो आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
> -असीम अरुण, पुलिस कमिश्नर, कानपुर

जुलाई में सामान्य से सात फीसद कम हुई बारिश

उप्र की धार्मिक नगरी वाराणसी में पिछले 48 घंटे में गंगा के जलस्तर में करीब चार मीटर की बढ़ोतरी हुई। रविवार को कई घाटों का आपस में संपर्क टूट गया। उफनाती गंगा की लहरें निरंजनी घाट स्थित श्री स्वयंभू प्रकट सुप्त हनुमान मंदिर के अंदर तक प्रवेश कर गईं। भैरव जायसवाल

नई दिल्ली, प्रेट्र : मौसम विभाग (आइएमडी) ने रविवार को बताया कि जुलाई में बारिश सामान्य से सात प्रतिशत कम दर्ज की गई। लेकिन एक जून से 31 जुलाई तक देश में कुल मिलाकर बारिश सामान्य से एक प्रतिशत कम रही है।

विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि जुलाई में हुई वर्षा दीर्घावधि औसत (एलपीए) के लगभग 93 प्रतिशत के आसपास है। बारिश का आंकड़ा जब 96 से 104 के बीच होता है तो उसे सामान्य कहा जाता है, जबकि 90 से 96 के बीच बारिश को सामान्य से कम माना जाता है।

जुलाई में तटीय और मध्य महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई। महाराष्ट्र में कई शहरों और कस्बों में बहुत भारी बारिश हुई, इसके चलते भूस्खलन जैसी भीषण घटनाएं हुईं जिनमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई और संपत्ति को भी भारी नुकसान हुआ। उत्तरी राज्यों- जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में बादल फटने की घटनाएं भी हुईं जिनमें कई लोग मारे गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी काफी अच्छी वर्षा हुई, लेकिन कुल मिलाकर जुलाई में सामान्य से सात प्रतिशत कम बारिश हुई। महापात्र ने कहा, 'हमने जुलाई में सामान्य बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया था जो कहीं-कहीं एलपीए का लगभग 96 प्रतिशत थी। जुलाई में देश में सर्वाधिक बारिश हुई, लेकिन उत्तर भारत में आठ जुलाई तक कोई बारिश नहीं हुई जो बारिश में कमी की वजह हो सकती है।'

दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल में अपने निर्धारित समय से दो दिन बाद तीन जून को पहुंचा था। हालांकि, यह 19 जून तक देश के पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों में तेजी से पहुंचा। लेकिन इसके बाद यह ऐसे चरण में पहुंच गया जिसमें कोई बारिश नहीं हुई। आठ जुलाई से यह पुनः सक्रिय होना शुरू हुआ था। दक्षिण-पश्चिम मानसून दिल्ली में 16 दिन की देरी से 13 जुलाई को पहुंचा और इसी दिन इसने समूचे देश को अपनी जद में ले लिया था।

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अनुमान : आइएएनएस के मुताबिक, मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में पांच अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश होने और राजस्थान में भारी से बहुत भारी बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सोमवार को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। हरियाणा में पांच अगस्त और हिमाचल प्रदेश में दो से चार अगस्त तक भारी बारिश होने का अनुमान है। प्रायद्वीपीय भारत, उससे जुड़े पूर्व मध्य भारत, महाराष्ट्र और गुजरात में अगले तीन-चार दिनों में बारिश में कमी आने की संभावना है।

सड़कों का 'बायोडाटा' बनवा रही मप्र सरकार

वैभव श्रीधर, भोपाल : मध्य प्रदेश में सड़कों पर नजर रखने के लिए शिवराज सरकार नवाचार करने जा रही है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ऐसा एप तैयार कर रहा है, जिसमें प्रत्येक सड़क की पूरी जानकारी रहेगी। एक क्लिक पर पता चल जाएगा कि सड़क का निर्माण कब हुआ, किसने बनाई, किस विभाग की है, कितनी लागत आई, गारंटी पीरियड कब तक है। इसका फायदा यह होगा कि सड़क के खराब होने की जानकारी जुटाने और संबंधितों के बारे में पड़ताल करने की मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। निर्माण एजेंसी के कर्तातर्ताओं की जिम्मेदारी भी तय करने में समय नहीं लगेगा। प्रदेश में बनने वाली नई सड़कों के लिए भी यह प्रक्रिया होगी।

प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के अलावा अन्य एजेंसियां भी सड़क निर्माण और संधारण का काम करती हैं। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि हमारी सरकार ने प्रदेश में सड़कों का जाल बुन दिया है। इसके अलावा नाबार्ड, एशियन डेवलपमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) की वित्तीय सहायता से सड़कें बनी हैं और निर्माण कार्य भी चल रहे हैं। इसकी प्रक्रिया चल रही है।

बहावलपुर के पाश इलाके में पाक सेना की सुरक्षा में रह रहा जैश सरगना अजहर

नई दिल्ली, प्रेट्र : पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठन जैश ए मुहम्मद के सरगना मसूद अजहर को सरकारी मेहमान की तरह बहावलपुर के घने बसे हुए पाश इलाके में रखा है ताकि उसके खिलाफ वैसी कार्रवाई न की जा सके जैसी अमेरिका ने अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन के खिलाफ की थी। यही नहीं, उसके आवासों की सुरक्षा पाकिस्तानी सेना के जवान करते हैं।

नए लांच हुए एक हिंदी समाचार चैनल ने अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य उजागर किया है। चैनल का कहना है कि उसके ऐसे निर्विवाद वीडियो साक्ष्य हैं जो पुष्टि करते हैं कि पाकिस्तान सरकार मसूद अजहर समेत आतंकवाद के आकाओं को सुरक्षित पनाहगाह उपलब्ध करा रही है। चैनल ने एक बयान जारी कर बताया कि मसूद के बहावलपुर में दो आवास हैं। इनमें से एक उस्मान-ओ-अली मस्जिद और नेशनल आर्थोपेडिक एंड जनरल हास्पिटल के ठीक बगल में है। सुरक्षा के लिए, पाकिस्तानी सेना के जवान उसके आवास के बाहर तैनात किए गए हैं। आवास के ठीक बगल में मस्जिद और अस्पताल होने का मकसद बिल्कुल साफ है कि यहां ओसामा जैसी कार्रवाई लगभग असंभव है। अगर कार्रवाई होती भी है तो आसपास रिहायशी इलाका होने से उसे और उसके साथियों को भाग निकलने का मौका मिल सकेगा।

मसूद का दूसरा आवास बहावलपुर में ही पहले आवास से करीब चार किलोमीटर दूर स्थित है। यह आवास जामिया मस्जिद के ठीक बगल में है और लाहौर हाई कोर्ट की बहावलपुर पीठ यहां से एक किलोमीटर और जिला कलेक्टर कार्यालय सिर्फ तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां भी वर्दी में पाकिस्तानी सेना के जवान बंगले की सुरक्षा में तैनात देखे गए।

बता दें कि मसूद अजहर भारत में संसद पर हमले, पठानकोट आतंकी हमले और 2019 में सीआरपीएफ कर्मियों पर आत्मघाती हमले समेत कई मामलों में वांछित है।

पुंछ के मेंढर में मिली बारूदी सुरंग, निष्क्रिय किया

जागरण संवाददाता, पुंछ : सुरक्षाबलों ने पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के नजदीक बारूदी सुरंग का पता लगाकर बड़ी दुर्घटना को टाल दिया है। जवानों को गश्त के दौरान मिली इस बारूदी सुरंग को निष्क्रिय कर दिया गया है। रविवार सुबह सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवान खोजी कुत्ते के साथ नियंत्रण रेखा के निकटवर्ती इलाके में रुटीन गश्त पर थे। तभी खोजी कुत्ते ने उस मार्ग पर विस्फोटक होने का संकेत किया। संकेत मिलते ही जवान सतर्क हो गए और इलाके को घेर कर तलाशी शुरू कर दी। इसी दौरान वहां बारूदी सुरंग मिली। फिलहाल, जांच की जा रही है कि यह बारूदी सुरंग इस इलाके में कैसे पहुंची। जांच की जा रही है कि यह किसी आतंकवादी संगठन की साजिश है या आतंकी घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय सेना द्वारा सुरक्षा के लिहाज से नियंत्रण रेखा पर बिछाई गई बारूदी सुरंग है।

निहंगों ने पहले भी किया है आम लोगों पर हमला

प्रथम पृष्ठ से आगे

कृषि कानूनों का विरोध करते-करते आंदोलनकारी अब कानून से भी ऊपर होने लगे हैं। कानून व्यवस्था के पालन को लेकर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों और आंदोलनकारी नेताओं के बीच कई बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन अपेक्षित नतीजा सामने नहीं आया है। निहंगों ने पहले भी कई लोगों पर हमला किया है। तीन महीने पहले कुंडली के बाइक सवार दो युवकों पर उस समय हमला किया था, जब वे आंदोलन वाले क्षेत्र से होकर निकल रहे थे। इनमें से एक युवक का हाथ तलवार के वार से कट गया था। पिछले दिनों ही क्षेत्र के गांव सेरसा के पूर्व पंच जगवीर सिंह की कार पर हमला कर दिया गया था। उनको जमकर पीटा गया। उन्होंने एक दुकान में छिपकर जान बचाई थी।

जागरण विशेष

जब जाना है खाली हाथ तो जाएं देकर कुछ सौगात

प्रशांत गाडे ने हजारों दिव्यांगों को बाहुबली बनाया, तीन लाख के जर्मन रोबोटिक हैंड का निर्माण दस हजार में कर रहे

कुमार अजय ● वाराणसी

इस कहानी की शुरुआत कोई दो दशक पहले हुई। मध्य प्रदेश के खंडवा निवासी गाडे परिवार के बुजुर्ग मुखिया का देहावसान हो गया। अंतिम गृह स्नान के लिए घर के आंगन में जब पार्थिव शरीर को वस्त्रों से मुक्त किया जाने लगा तो वहीं मौजूद दिवंगत के मासूम पौत्र प्रशांत गाडे के मन में बाल जिज्ञासा उभरी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? पिता बोले-बेटा, जहां दादा जी जा रहे हैं, वहां कोई कुछ नहीं ले जा पाता। इस कठोर सत्य की जड़ें प्रशांत गाडे के अंतस में गहराई तक बैठ गईं। उनके उत्कीर्ठित बालमन ने 'लेकर नहीं जा सकते तो क्यों न दुनिया को कुछ देकर जाएं' का फलसफा गढ़ा। प्रशांत आज स्वनिर्मित रोबोटिक हैंड (स्वचालित हाथ) का आरोपण कर हजारों दिव्यांगों को बाहुबली बना रहे हैं। असली नायक का मान पा रहे हैं।

दिव्यांग महिला के दर्द ने बदली जीवन की धारा: प्रशांत हाल ही में चार दिनों के काशी प्रवास में 90 से भी अधिक दिव्यांगों को स्पंदित हाथ का उपहार देकर पुणे रवाना हो गए। दिवंगत दादा की इच्छा पूरी करने के लिए प्रशांत ने इंजीनियरिंग में दाखिला तो लिया था, किंतु नौकरी व पैकेज की अंधी होड़ से उचाट होकर पढ़ाई बीच में छोड़ दी। एक दिन उनकी मुलाकात दोनों हाथों से वंचित एक दिव्यांग महिला से हुई। उस महिला के दर्द को प्रशांत ने अपना बना लिया और पढ़ाई में हासिल ज्ञान को गहन शोध की गहराइयों तक पहुंचाया।

जर्मन तकनीक से बने रोबोटिक हाथों को दिया नया रूप: जर्मन तकनीक से ढाई से तीन लाख रुपये में बनने वाले रोबोटिक हाथों को महज दस-बारह हजार रुपये में बनाकर प्रशांत ने अपना कौशल सिद्ध कर दिखाया। इन हाथों से दिव्यांग खाना खा सकते हैं, वजन उठा सकते हैं, कंप्यूटर और बाइक भी चला सकते हैं। बिजली से एक घंटे चार्ज करने के बाद एक हाथ 48 घंटे तक काम करता है। हालांकि जर्मन रोबोटिक हैंड को चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ती।

एक बच्चे को रोबोटिक हाथ लगाते प्रशांत गाडे ● सौ. स्वयं

प्रशांत के जज्बे से इंफोसिस की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति भी प्रभावित

28 वर्ष के इस नौजवान की कोशिशों को इंफोसिस की चेयरपर्सन और जानीमानी सामाजिक कार्यकर्ता सुधा मूर्ति का भी समर्थन हासिल है। सुधा मूर्ति पोषित अपने इनाली फाउंडेशन के माध्यम से हजारों दिव्यांगों को हाथ देकर प्रशांत ने अधूरे व्यक्तित्व को पूर्णता दी है। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित प्रशांत की वर्कशाप में 30 से ज्यादा इंजीनियर और वर्कर काम करते हैं। स्वयंसेवी संस्थाएं उनसे रोबोटिक हैंड लेकर दिव्यांगों में मुफ्त वितरित करती हैं। काशी में भी भारत विकास परिषद, वरुणा की ओर से आयोजित तीन दिवसीय निश्शुल्क शिविर में कटे बाजुओं वाले पीड़ितों को खुद के हाथों का सहारा प्रशांत ने दिया। इनमें पूर्वांचल के अन्य जिलों व बिहार के दिव्यांग भी शामिल हैं।

इस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें

10 जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं उप्र में। यहां संक्रमण की प्रतिदिन पाजिटिविटी दर 0.01 फीसद आ गई है जबकि पाजिटिविटी दर 98.6 फीसद हो गई है।

केरल में काबू में नहीं कोरोना, पांचवें दिन भी 20 हजार केस

बचाव की तैयारी ▸ राज्य में सख्ती के साथ शनिवार और रविवार को रहेगा लाकडाउन

चौबीस घंटे में देश भर में कोरोना संक्रमण के 41 हजार नए मामले मिले

जेएनएन, नई दिल्ली

केरल में कोरोना संक्रमण में कमी नहीं आ रही है। राज्य में लगातार पांच दिनों से 20 हजार से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं जो पूरे देश में मिलने वाले कुल संक्रमितों का आधा है। हालांकि, राज्य में संक्रमण को काबू में करने के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। केंद्र ने भी छह सदस्यीय एक टीम भेजी है जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी और हालात को काबू में करने के लिए स्थानीय प्रशासन की मदद करेगी। राज्य में शनिवार और रविवार को पूर्ण लाकडाउन लगा दिया गया है। वहीं तमिलनाडु से आने वालों के लिए निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट या टीकाकरण सर्टिफिकेट अनिवार्य बना दिया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से रविवार सुबह आठ बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश भर में 41 हजार से ज्यादा नए मामले पाए गए हैं और पांच सौ से ज्यादा लोगों की जान भी गई है। केरल में बढ़ते संक्रमण के चलते सक्रिय मामलों में वृद्धि हो रही है। वर्तमान में सक्रिय मामले 4,10,952 हैं जो कुल मामलों का 1.30 फीसद है। हालांकि, दैनिक और साप्ताहिक संक्रमण दर पांच फीसद से नीचे बनी हुई है। अब तक तीन करोड़ आठ लाख से ज्यादा लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं।

देश में कोरोना की स्थिति	
24 घंटे में नए मामले	41,831
कुल सक्रिय मामले	4,10,952
24 घंटे में टीकाकरण	60 .04 लाख
कुल टीकाकरण	47 .02 करोड़

राज्यों को अब तक 49.49 करोड़ डोज उपलब्ध कराई गई

मंत्रालय ने बताया कि केंद्र की तरफ से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कोरोना रोधी वैक्सीन की कुल 49 .49 करोड़ डोज मुहैया कराई गई हैं। आठ लाख से ज्यादा डोज भी जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएंगी। मंत्रालय ने बताया कि राज्यों के पास अभी तीन करोड़ से ज्यादा डोज बची हैं।

चेन्नई के अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जांच के लिए स्वैब सैंपल लेता स्वास्थ्यकर्मी। एएफपी

रविवार सुबह 08 बजे तक कोरोना की स्थिति	
नए मामले	41,831
कुल मामले	3,16,55,824
सक्रिय मामले	4,10,952
मौतें (24 घंटे में)	541
कुल मौतें	4,24,351
ठीक होने की दर	97.36 फीसद
मृत्यु दर	1.34 फीसद
पाजिटिविटी दर	2.34 फीसद
सा. पाजिटिविटी दर	2.42 फीसद
जांचें (शनिवार)	17,89,472
कुल जांचें (शनिवार)	46,82,16,510

रविवार शाम 06 बजे तक किस राज्य में कितने टीके	
गुजरात	3.34 लाख
बंगाल	1.31 लाख
पंजाब	1.12 लाख
महाराष्ट्र	0.80 लाख
बिहार	0.77 लाख
उत्तराखंड	0.63 लाख
झारखंड	0.57 लाख
जम्मू-कश्मीर	0.33 लाख
छत्तीसगढ़	0.24 लाख
मध्य प्रदेश	0.16 लाख
दिल्ली	0.10 लाख
उत्तर प्रदेश	0.07 लाख

जम्मू कश्मीर में अभी नहीं खुलेंगे शिक्षण संस्थान

राज्य ब्यूरो, जम्मू

कोरोना संक्रमण के उपजे हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर में अभी स्कूल, उच्च शिक्षण संस्थान और कोचिंग केंद्र बंद रहेंगे। हालांकि, शिक्षण संस्थानों में प्रशासनिक कार्यों को कराने के लिए कोरोनारोधी टीका लगवा चुके स्टाफ सदस्यों को बुलाया जा सकेगा। प्रदेश में अब किसी भी जिले में वीकेंड कर्फ्यू नहीं है, लेकिन रात्रि कर्फ्यू रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक जारी रहेगा। प्रदेश के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अटल ढुल्लु, गृह विभाग के प्रमुख सचिव, जम्मू और कश्मीर के मंडलायुक्त, जिला उपायुक्त और पुलिस अधिकारियों के साथ कोरोना की स्थिति पर बैठक की है। राज्य कार्यकारी समिति की इस बैठक में प्रति 10 लाख की तुलना में प्रति सप्ताह में मिलने वाले मामले, संक्रमण दर, अस्पतालों में बेड की क्षमता, वैक्सीनेशन अभियान पर ध्यान देने पर जोर दिया गया। समिति ने पाया कि पिछले सप्ताह के मुकाबले कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार आ रहा है। कोरोना की रोकथाम के लिए मौजूदा दिशा निर्देशों का पालन जारी रखने का फैसला किया गया।

कोरोना का जीनोम म्यूटेशन आबादी के स्तर पर कई रूपों में दिखता है

नई दिल्ली, प्रेट्र : हाल में हुए एक अनुसंधान में कहा गया है कि किसी संक्रमित व्यक्ति में सार्स-कोव-2 वायरस के जीनोम में होने वाला म्युटेशन जनसंख्या स्तर पर विविध स्वरूपों में दिखाई देता है। विज्ञानियों का कहना है कि यह अनुसंधान कोरोना वायरस के स्वरूपों के प्रसार और संक्रमण प्रभाव को लेकर पूर्वानुमान व्यक्त करने में बहुत उपयोगी साबित होगा। इस पर सभी विज्ञानियों की निगाहें टिकी हुई हैं।

अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि व्यक्तियों और आबादी के बीच वायरस में होने वाले उत्परिवर्तनों पर नजर रखने वालों को उन विषाणु स्थलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है जो कोविड-19 के लिए जिम्मेदार सार्स-कोव-2 के अस्तित्व के लिए अनुकूल या प्रतिकूल हैं। इस अनुसंधान में दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) से संबद्ध जिनोमिकी और समवेत जीव विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर स्थित जीवन विज्ञान संस्थान, गाजियाबाद स्थित वैज्ञानिक और अभिनव अनुसंधान अकादमी, हैदराबाद स्थित सीएसआईआर-कोशिकीय और आणविक जीवविज्ञान केंद्र (सीएसआइआर-सीसीएमबी) और जोधपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के अनुसंधानकर्ता शामिल थे।

कोविड पर अंकुश के लिए चार लाख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देगी भाजपा

नई दिल्ली, एएनआइ : कोविड-19 पर अंकुश के लिए भाजपा ने चार लाख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का फैसला किया है। ये कार्यकर्ता दो लाख गांवों में जाएंगे और महामारी से निपटने में लोगों की मदद करेंगे।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने खास बातचीत में कहा, 'पहली बार इतनी बड़ी संख्या में किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता महामारी से मुकाबले के लिए तैयार किए जाएंगे। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए चार लाख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 जुलाई को इस पहल को हरी झंडी दिखा चुके हैं।' चुग ने कहा कि इसकी शुरुआत के तीन दिनों के भीतर हम सफलतापूर्वक पहला पड़ाव पार कर चुके हैं। 1,03,872 कार्यकर्ताओं ने पार्टी की हेल्थ वालंटियर वेबसाइट पर पंजीयन कराया है। कोविड महामारी की दूसरी लहर की विभीषिका और तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए भाजपा प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने की तैयारी में जुटी है।

देश में जानवरों को जल्द लगेगी कोरोना से बचाव की वैक्सीन

वैभव शर्मा, हिसार

देश में जानवरों के लिए कोविड-19 की वैक्सीन जल्द मिल जाएगी। इस काम में हिसार के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र (एनआरसीई) के विज्ञानी जुटे हुए हैं। वैक्सीन को विकसित कर लिया गया है। पहले चूहों और उसके बाद कुत्तों पर ट्रायल के बाद इसे बाजार में लाया जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जानवरों के लिए वैक्सीन बनाने की जिम्मेदारी एनआरसीई सहित देश के तीन संस्थानों को दी है। इसमें बरेली के इज्जत नगर स्थित इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आइवीआरआइ) व भोपाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज (एनआइएचएसएडी) भी शामिल हैं। एनआरसीई के निदेशक डा. यशपाल के निर्देशन में वैक्सीन पर कार्य हो रहा है। वरिष्ठ विज्ञानी डा. बीआर गुलाटी बताते हैं कि पहले वायरस को कमजोर किया गया। फिर उसका प्रयोग वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में किया जा रहा है।

इंसानों से जानवर भी कोविड-19 से हो चुके हैं संक्रमित : कुछ समय पहले ही हैदराबाद में एशियन शेर और इटावा की लायन सफारी में भी कोविड-19 संक्रमित पशु मिले थे। इसके बाद तय हुआ कि इंसानों से पशुओं में कोरोना का वायरस फैलता है। पूरी संभावना है कि पशुओं से इंसानों में कोरोना फैलता हो। ऐसे में पशुओं का टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है।

जगी उम्मीद

- हिसार, बरेली और भोपाल स्थित संस्थानों के विज्ञानी कर रहे काम
- चूहों और कुत्तों पर ट्रायल के बाद बाजार में लाने की होगी कोशिश

इंसानों की तर्ज पर पशुओं को कोविड-19 से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीन बन चुकी है, अब इसमें आगे के ट्रायल किए जा रहे हैं। जल्द ही हम कोविड-19 की वैक्सीन बाजार में किसी कंपनी के माध्यम से उतारेंगे।

-डा. बीएन त्रिपाठी, उप महानिदेशक (पशु विज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।

पहले पशुओं पर किया सर्विलांस

विज्ञानियों ने पशुओं में कोविड-19 का प्रभाव देखने के लिए सर्विलांस का सहारा लिया। हरियाणा में 400 पशुओं पर सर्विलांस किया गया, जिसमें कई पशु कोरोना वायरस से संक्रमित मिले। इनमें गाय, भैंस और अश्व थे। दुधारू पशुओं में बुवाइन कोरोना वायरस मिला। यह वायरस संक्रमण नहीं फैलाता, मगर पशुओं को दस्त, बुखार, सर्दी जैसी समस्याओं से ग्रसित करता है। वैक्सीन बनाने के लिए इस सर्विलांस को आगे और भी किया जा रहा है।

देश में वैक्सीन की नहीं, राहुल गांधी में परिपक्वता की कमी : मांडविया

नई दिल्ली, एएनआइ : देश में कोरोना वैक्सीन की कमी के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पलटवार किया है। रविवार को मांडविया ने कहा कि देश में टीके की नहीं, बल्कि राहुल गांधी में परिपक्वता की कमी है।

कांग्रेस नेता के ट्वीट पर मांडविया ने कहा कि देश में टीकाकरण की गति ठीक बनी हुई है और इस महीने इसमें और तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि जुलाई में 13 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई हैं और अगस्त में यह संख्या और बढ़ने वाली है। मांडविया ने कहा कि हमें अपने स्वास्थ्यकर्मियों पर गर्व है। राहुल गांधी को भी स्वास्थ्यकर्मियों और अपने देश पर गर्व करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने सुना है कि टीका लेने वाले लोगों में राहुल गांधी भी शामिल हैं। मांडविया ने आगे कहा, 'लेकिन न तो अपने हमारे विज्ञानियों के बारे में एक शब्द कहा और न ही लोगों से वैक्सीन लेने की अपील की। इसका मतलब है कि आप टीकाकरण के नाम पर ओछी राजनीति में लगे हैं।

डेल्टा वैरिएंट से बचा रही कोरोना वैक्सीन की दो डोज

जागरण संवाददाता, पटना

कोरोना संक्रमण से बचना है तो वैक्सीन की दोनों डोज लेना जरूरी है। यह बात अस्पतालों के आंकड़ों से भी साबित हो रही है। जून और जुलाई में पटना एम्स और पटना मेडिकल कालेज अस्पताल (पीएमसीएच) में भर्ती कोरोना संक्रमितों में सिर्फ पांच फीसद ही ऐसे थे जो वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद अस्पताल पहुंचे। इनमें से 0.04 फीसद की ही मौत हुई है। हालांकि, जिन लोगों की वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद मौत हुई उनमें अधिकतर डाक्टर व चिकित्साकर्मी थे। इसका कारण उनका लगातार संक्रमितों के उपचार में लगा रहना बताया गया है।

वैक्सीन की दो डोज लेने वाले 90 फीसद हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर संक्रमण से सुरक्षित रहे। बताते चलें कि दूसरी लहर में प्रदेश में 80 फीसद से अधिक लोग कोरोना के डेल्टा वैरिएंट से संक्रमित हुए थे। विशेषज्ञों के अनुसार डेल्टा वैरिएंट वैक्सीन या पूर्व में हुए संक्रमण से विकसित एंटीबाडी की संख्या तेजी से कम करता है।

भर्ती होने वाले दस दिन में हुए स्वस्थ : पटना एम्स के कोरोना नोडल पदाधिकारी डा. संजीव कुमार ने बताया कि 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान के बाद जून व जुलाई में जितने रोगी भर्ती हुए, उनमें करीब दस फीसद लोग वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे। जिन पांच फीसद को भर्ती करना पड़ा उनमें से अधिकतर हेल्थ व फ्रंटलाइन वर्कर थे। हालांकि, इनमें से अधिकतर को औसतन दस दिन में डिस्चार्ज कर दिया गया। वैक्सीन लेने के बाद जो लोग संक्रमित हुए या जिनकी मौत हुई है, अब उन मामलों को आधार बनाकर कारण जानने को अध्ययन किया जा रहा है। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में गहन अध्ययन किया जा रहा है कि कितने फीसद लोग वैक्सीन की दो या सिंगल डोज लेने के बाद भर्ती हुए हैं। उनमें कैसे लक्षण थे, कितने दिन में स्वस्थ हुए, उनमें से कितने सामान्यऔर कितने हेल्थ केयर या फ्रंटलाइन वर्कर थे?

सिंगापुर में भी सजेगी काशी में बनी कृष्ण लीला की झांकी

मुकेश चंद्र श्रीवास्तव, वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से काशी में बनने वाले लकड़ी के खिलौनों के प्रोत्साहन को उठाए गए कदम के बाद देश-विदेश में मांग बढ़ गई है। सिंगापुर से 83 सेट के साथ ही दक्षिण भारत से भी 30 सेट भगवान श्रीकृष्ण लीला की झांकी का आर्डर मिला है।

काशी की शुभी ने इस झांकी की डिजाइन बनाकर कंपनियों से संपर्क किया था। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद शिल्पी व उद्यमी बिहारी लाल अग्रवाल के नेतृत्व में 24 परिवार झांकी बनाने में जुट गए। इसके कारण कोरोना काल में भी उन्हें रोजगार मिला। एक सेट बनाने में करीब ढाई माह का समय लगा। अब तक करीब 240 सेट झांकी बनाई जा चुकी है। इससे शिल्पकारों की आय भी बढ़ रही है। जन्म से लेकर महाभारत तक की लीला इस झांकी में श्रीकृष्ण जन्म से लेकर महाभारत तक की लीला शामिल हैं। गोपियों से रासलीला, मथुरा, वृंदावन, माखन चोरी, गोपियों का वस्त्र चुराने, गोवर्धन पर्वत, नाग नथैया, द्रौपदी चीरहरण, सुदामा चरित्र, मीराबाई, नाव में प्रभु, पूतना, कंस वध भी शामिल है। साथ ही इसी झांकी में तोता, मोर, गाय, घोड़ा आदि को भी दर्शाया गया है।

श्रद्धा का महासावन

शिव कृपा अनंत, शिव भक्ति अपरंपार

इस सृष्टि में जो-कुछ है, वह शिव ही है। शिव ही सत्य हैं और शिवत्व भी। शिव ही सृष्टि के रचनाकार हैं और संहारक भी। शिव को ही अमरत्व और पूर्ण आरोग्य के वरदान का अधिकार हासिल है। इसीलिए उन्हें महाकाल और देवाधिदेव महादेव कहा गया है। सृष्टि के आरंभ में जब कुछ नहीं था, शिव तब भी थे और जब प्रलयकाल होगा, तब भी रहेंगे। इस सृष्टि में जो भी सत्य है, वह शिव ही है और जिसमें शिवत्व है, वही सुंदर है। शिव त्रिनेत्र के प्रतीक हैं तो भूत-प्रेत व पिशाचों के स्वामी पशुपतिनाथ भी। वह शून्य की भांति सब-कुछ स्वयं में धारण कर लेते हैं। शिव ही एकमात्र पूर्ण हैं और जो पूर्ण है वही शिव है। श्रावण में शिव आराधना, उनकी महिमा का गुणगान और गंगाजल से शिवलिंग के अभिषेक का अलग ही महत्व है। सच्चे मन से की गई आराधना, पूजा और जलाभिषेक से वह जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। वह भक्त को समृद्धि, संतान, यश, सुख और आरोग्य की प्राप्ति कराते हैं। शिव सारे जग के पालनहार हैं और सबके आराध्य भी। सृष्टि की रक्षा को उन्होंने समुद्र मंथन से निकले विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। हलाहल की गर्मी गंगा में शांत हुई। तभी से श्रावण में गंगाजल से शिव के अभिषेक की परंपरा स्थापित हुई। शिव को जल, खासकर गंगाजल बेहद प्रिय है। इन दिनों शिव का गंगाजल से अभिषेक करने पर उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। शिव कृपा अनंत है। शिव भक्ति अपरंपार है।

स्वामी अवधेशानंद गिरि
आचार्य महामंडलेश्वर, श्रीपंचदशनाम जूना अखाड़ा, हरिद्वार

स्कैन करें और पढ़ें 'श्रावण मास' से संबंधित सभी सामग्री

निधि समर्पण करने वालों का अभिनंदन करेगी विहिप

नेमिष हेमंत, नई दिल्ली : अयोध्या में भव्य राममंदिर निर्माण में निधि अर्पित करने वाले 65 करोड़ से अधिक रामभक्तों का विश्व हिंदू परिषद (विहिप) धन्यवाद ज्ञापित करेगी। इसके लिए विहिप के स्थापना दिवस पर एक बार फिर से राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा, जो 27 से चार सितंबर तक चलेगा। 30 अगस्त को जन्माष्टमी है। 1964 में जन्माष्टमी के दिन ही विहिप की स्थापना हुई थी।

इस बार विहिप ने स्थापना दिवस कार्यक्रम को वृहद स्तर पर मनाने की तैयारी की है। इसमें अब तक की उपलब्धियों के साथ देश व हिंदू समाज के सामने मौजूदा चुनौतियों पर भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके तहत देशभर में 65 हजार से अधिक स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। इसमें विहिप के केंद्रीय पदाधिकारी भी भाग लेंगे। श्रीराम मंदिर निर्माण में आम जन की सहभागिता के लिए इसी वर्ष 15 जनवरी से 27 फरवरी तक चले निधि समर्पण अभियान में विहिप ने 65 करोड़ से अधिक लोगों को जोड़ा था। संगठन के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया कि स्थापना दिवस कार्यक्रम में विहिप के गठन के उद्देश्य, उपलब्धियों और हिंदू समाज के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी।

जज हत्याकांड में 17 गिरफ्तार, दो पुलिस पदाधिकारी निलंबित

जागरण संवाददाता, धनबाद

धनबाद में न्यायाधीश उत्तम आनंद की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। जिले भर में छापेमारी एवं सर्च अभियान चलाया गया है। संदिग्ध एवं पुराने वारंटियों को गिरफ्तार करने के साथ ही होटलों को सर्च किया गया है। लापरवाही के आरोप में दो पुलिस अधिकारियों को निलंबित भी किया गया। इसके साथ ही जिले भर में चलने वाले आटो की भी जांच की गई है। इतनी बड़ी कार्रवाई के दौरान 17 गिरफ्तारी, 243 हिरासत में और 250 आटो को भी जब्त किया गया है। हत्या के कारणों को जानने के लिए धनबाद पुलिस ने 53 वीडियो फुटेज को भी खंगाला है।

पुलिस की यह कार्रवाई एसआइटी टीम के मुखिया एडीजी संजय आनंद लाटकर और एसएसपी संजीव कुमार के निर्देश पर की गई है। एसएसपी ने बताया कि हत्याकांड के बाद से ही पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। छोटी सी छोटी चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। जो भी बातें सामने आ रही हैं, उसे भी चेक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी अपराध कर्मी को छोड़ा नहीं जाएगा। आटो जांच को लेकर भी उनके तेवर सख्त दिखे।

न्यायाधीश हत्याकांड

- धनबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जिले के सभी थाना क्षेत्रों में रात भर चली छापेमारी, दिन में आटो जांच

53 तस्वीरों और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस : हत्याकांड के बाद से धनबाद पुलिस ने सभी चौक चौराहों और रास्तों पर लगे सीसीटीवी फुटेज के अलावा दुकानों व प्रतिष्ठानों में लगे कैमरे की 53 तस्वीरों को खंगालने का काम किया है। पुलिस इन तस्वीरों से कांड के आरोपितों के मूवमेंट की जानकारी ली जा रही है। वे किससे मिले, भागने के लिए किन रास्तों का उपयोग किया समेत अन्य बिंदुओं पर जांच की जा रही है। चूंकि हत्या में चोरी के आटो को इस्तेमाल हुआ था तो पुलिस ने इसे लेकर रविवार को शहर में सघन जांच की। ऐसे 250 आटो जब्त किए गए हैं जिनके चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन का रजिस्ट्रेशन संबंधित आनर बुक नहीं था। आटो चालक की मालकिन के पति रामदेव लोहार से लगातार पूछताछ हो रही है, हालांकि इस संबंध में वह कुछ जानकारी होने से लगातार इन्कार कर रहा है।

मतांतरण अखिल भारतीय समस्या, कानून बने : आलोक कुमार

नईदुनिया, भोपाल : विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने मतांतरण के खिलाफ सख्त केंद्रीय कानून की हिमायत की है। उन्होंने कहा, देश में लालच, दबाव और धोखे से मतांतरण कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों ने इसे रोकने के लिए कानून बनाए हैं पर यह समस्या व षड्यंत्र राष्ट्रव्यापी है इसलिए इलाज भी अखिल भारतीय होना चाहिए। केंद्र सरकार संसद के आगामी सत्र में मतांतरण रोकने के लिए सख्त केंद्रीय कानून बनाए। तभी इस अभिशाप से मुक्ति मिलेगी। मतांतरण कराने वाले व्यक्तियों को जेल भेजने और संगठनों पर जुर्माना लगाने के सख्त प्रविधान हों।

आलोक कुमार रविवार को यहां विहिप के मध्यभारत प्रांत की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बाद में मीडिया से चर्चा में उन्होंने बताया कि मतांतरण के कई षड्यंत्र उजागर हुए हैं। लव जिहाद इसका सबसे घिनौना प्रकार है। अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को प्रलोभन देकर मत परिवर्तन कराने के कई मामले आ चुके हैं। मत परिवर्तन कराकर देश में विवाह न हों और मतांतरण पर रोक लगे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्रीय कानून बनाने संबंधी निर्देश दिए थे। इसको ही आधार बनाकर बात रखी जा रही है।

'जिस भूमि पर माफिया का कब्जा, वहीं इंस्टीट्यूट'

▸ प्रथम पृष्ठ से आगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2019 में गृह मंत्री अमित शाह जब लखनऊ में पुलिस साइंस कांग्रेस में आए थे, तब उन्होंने ही प्रदेश में फारेंसिक इंस्टीट्यूट के गठन का सुझाव दिया था। जिस भूमि पर इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है, उस 142 एकड़ भूमि पर माफिया का कब्जा था। राज्य सरकार ने इसे कब्जा मुक्त कराया। योगी ने कहा कि प्रदेश में चार वर्ष के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री की प्रेरणा का परिणाम है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था। माफिया का कब्जा था। प्रदेश सरकार ने माफिया की अब तक 1584 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर अपराधियों में कानून का भय व्याप्त किया है।

उत्तर प्रदेश के मीरजापुर में रविवार को मां विंध्यवासिनी का दर्शन-पूजन करते गृह मंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रेट्र

मां विंध्यवासिनी और बाबा विश्वनाथ के दरबार में पूजन

विंध्यधाम पहुंचकर शाह और योगी ने मां विंध्यवासिनी का दर्शन-पूजन किया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विंध्य कारिडोर के लिए भूमि पूजन किया।

कल्याण सिंह को देखने पहुंचे अमित शाह

जागरण संवाददाता लखनऊ : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह रविवार को उप्र के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को देखने एसजीपीजीआइ, लखनऊ पहुंचे। उन्होंने संस्थान के डाक्टरों से उनकी स्थिति के बारे में जानकारी ली।

गृहमंत्री ने कल्याण सिंह के परिवार वालों से मिलकर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। गृह मंत्री के साथ उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना भी थे। गृहमंत्री वहां करीब 20 मिनट रुके। पीजीआइ के निदेशक डा. आरके धीमन ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री की स्थिति गंभीर, किंतु नियंत्रण में है। वह क्रिटिकल केयर मेडिसिन, नेफ्रोलाजी, न्यूरोलाजी एवं कार्डियोलाजी विभागों के वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में हैं।

कोतवाल के सामने हाथ जोड़कर बैठे विधायक

जागरण संवाददाता, पीलीभीत

संपत्ति विवाद में सिफारिश न मानने से नाराज पीलीभीत से भाजपा विधायक संजय गंगवार रविवार को कोतवाल के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। बोले, आप भाजपा को हरवाने में लगे हुए हैं। पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि कोतवाल ने कानून के तहत कार्रवाई की बात कहते रहे। दोपहर को हुए घटनाक्रम की जानकारी रात को एसपी किरीट सिंह राठौड़ को हुई। जांच कराई, उसके आधार पर अतर सिंह को कोतवाली से हटा दिया गया। निरंजनकुंज कालोनी में एक मकान को लेकर भाई-बहन में विवाद चल रहा है। रविवार को भी मारपीट हुई तो पुलिस ने दोनों पक्षों पर शांतिभंग की कार्रवाई कर दी। इस मामले में विधायक संजय गंगवार युवती पक्ष से पैरवी कर चुके हैं। इसके बावजूद कार्रवाई होने पर उन्हें लेकर विधायक कोतवाली पहुंच गए। कोतवाल अतर सिंह से कहा कि आपका कोई इलाज नहीं हो सकता, आप तो भाजपा को हरवाने में लगे हैं। कुछ देर कोतवाल के सामने कुर्सी पर हाथ जोड़े बैठे रहे, इसके बाद उच्चाधिकारियों को फोन पर मामले की जानकारी देकर चले गए। वह इससे पहले भी कई बार कोतवाल की शिकायत कर चुके हैं।

उप्र के पीलीभीत में कोतवाल अतर सिंह के सामने हाथ जोड़े बैठे शहर विधायक संजय सिंह गंगवार। इंटरनेट मीडिया

निरंजनकुंज कालोनी में बहन-भाई में मकान को लेकर विवाद है। सीओ से जांच कराई जा रही है। कोई पुलिस कर्मी पक्षपातपूर्ण कार्य नहीं करेगा। -किरीट सिंह राठौड़, एसपी, पीलीभीत।

कोतवाल काफी समय से लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। जनता परेशान है। मकान के विवाद में उन्होंने पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की है। -संजय गंगवार, विधायक

एक शिक्षा तीन फायदे

वर्ल्ड इकोनामिक फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा किसी देश की मानव पूंजी का अहम घटक है। इससे व्यक्ति की दक्षता बढ़ती है। यह देश के विकास में तीन तरह से योगदान देती है :

1 वहां की कार्यशील आबादी की दक्षता बढ़ती है और वह किसी कार्य को जल्दी करने में सक्षम होती है।

2 माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक शिक्षा दूसरों द्वारा अर्जित ज्ञान को अगली पीढ़ी में पहुंचाने का माध्यम बनती है।

3 रचनात्मकता बढ़ती है और कोई देश नया ज्ञान, नई टेक्नोलाजी और नए उत्पाद विकसित करने में सक्षम होता है।

मुद्दा से संबंधित अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया mudda@jagran.com पर भेज सकते हैं।

यह नए दौर का भारत है। नई तरह की सोच रखता है। दुनिया से कदमताल करने के साथ अपनी परंपरा और मूल्यों को अक्षुण्ण रखना भी इसकी एक अदा है। कभी हम विश्व गुरु थे। हमारे मनीषियों ने दुनिया को ज्ञान का जो उजियारा दिया, उससे दुनिया तो आगे बढ़ी लेकिन वक्त की दौड़ में हम पिछड़ते गए। देश-काल और परिस्थितियां भी इसकी जिम्मेदार रहीं। 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक हम फिर से उठ खड़े होने लगे हैं। किसी देश के समग्र निर्माण में शिक्षा का अहम योगदान होता है। पुराने जमाने की सोच वाली 1986 में बनी शिक्षा नीति को त्याग कर हमने भविष्य की जरूरतों को ध्यान रख नई शिक्षा नीति लागू की। 29 जुलाई को इसके एक साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने नई शिक्षा नीति को राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में बड़ी आहुति करार दिया। सही बात है, कोई भी देश जो सीखेगा, वही सिखाएगा और उसी दिशा में उसके आचार-विचार और व्यवहार आगे बढ़ेंगे। कोविड-काल की चुनौतियों के मद्देनजर तमाम सहूलियतों की खूबियों वाली इस शिक्षा नीति का खुलापन और दबावरहित होना सबसे बड़ा गुण है। भारतीय शिक्षा क्षेत्र की चुनौतियां कम नहीं है। सबको शिक्षा, सस्ती शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाली शिक्षा आज समय की दरकार है। आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का है। युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस प्रोग्राम के साथ-साथ देश में डिजिटल और टेक्नोलाजी का बुनियादी ढ़ाचा खड़ा करने का काम जोरों पर है। देश की अर्थव्यवस्था को एआइ आधारित बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में ये कदम क्रांतिकारी साबित हो सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस देश में आज भी इंटरनेट स्पीड और स्मार्ट फोन की उपलब्धता के साथ शिक्षा से जुड़े तमाम संसाधन अविकसित स्तर पर हों, वहां शिक्षा क्षेत्र में उठाए गए ये कदम वैश्विक जगत से कदमताल में कितने उपयोगी साबित होंगे। ऐसे में नई शिक्षा नीति के एक साल पूरे होने पर इसकी अब तक की उपयोगिता और भविष्य की राह की पड़ताल आज हम सबके लिए बड़ा मुद्दा है।

नई शिक्षा नीति दूरदर्शी सोच

लाभ का गणित

- शिक्षा पर खर्च किया गया एक डालर अर्थव्यवस्था में 10 से 15 डालर का योगदान देने में सक्षम है।
- स्कूल में बिताया गया हर साल यानी पढ़ाई के हर बढ़ते स्तर के साथ व्यक्ति को मिलने वाला संभावित वेतन बढ़ता है।
- दुनिया के सबसे गरीब 46 देशों में यदि 15 से ज्यादा उम्र की 75 फीसद अतिरिक्त आबादी गणित की शिक्षा में कम से ओईसीडी के न्यूनतम मानक तक भी शिक्षा हासिल कर ले, तो उनकी अर्थव्यवस्था अपने आधार से 2.1 फीसद ऊपर उठ सकती है। इससे 10.4 करोड़ लोगों को बेहद गरीबी की सीमा से बाहर लाया जा सकता है। (यूनेस्को 2012)

राष्ट्र के पुनरुत्थान की नींव

अतुल कोठारी
राष्ट्रीय सचिव, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, नई दिल्ली

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में राष्ट्र के पुनरुत्थान की नींव रखी गई है। इस नीति के सुचारु एवं समग्रता से क्रियान्वयन द्वारा देश की शिक्षा बदलेगी। जब शिक्षा बदलेगी तो इस परिवर्तन का सकारात्मक समग्र असर देश पर पड़ेगा। इससे देश बदलेगा यानी समृद्ध, समर्थ एवं शक्तिशाली भारत के निर्माण में हम अग्रसर हो सकेंगे।

किसी भी राष्ट्र की उन्नति में वहां की शिक्षा व्यवस्था की महती भूमिका होती है। इसका स्पष्ट प्रभाव समाज, संस्कृति, राजनीति एवं अर्थव्यवस्था पर परिलक्षित होता है। इसलिए राष्ट्र का निर्माण करने हेतु सबसे पहले वहां की शिक्षा-व्यवस्था को सशक्त, समर्थ एवं राष्ट्रानुकूल बनाने की आवश्यकता होती है। यूनेस्को की डैलर्स समिति की रिपोर्ट के अनुसार, 'किसी भी देश की शिक्षा का स्वरूप उस देश की संस्कृति एवं प्रगति के अनुरूप होना चाहिए।' इसमें एक शब्द 'प्रकृति' को भी जोड़ना उचित होगा। तात्पर्य यह है कि किसी भी देश की शिक्षा-व्यवस्था जिस प्रकार की होगी, देश और समाज भी वैसा ही बनेगा। शिक्षा किसी भी राष्ट्र की आधारशिला होती है। शिक्षा का आधारभूत लक्ष्य चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास है। आज चरित्र का संकट एक प्रकार से विश्व की अधिकतर समस्याओं की जड़ में है। शिक्षा के इस महत्वपूर्ण लक्ष्य के साथ दो और सहायक बातें अपेक्षित हैं। शिक्षा के द्वारा देश एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो तथा राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान प्राप्त हो सके। किसी भी देश के निर्माण हेतु यह तीनों आधारभूत बातें आवश्यक है।

नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास को पूर्व प्राथमिक शिक्षा से ही संज्ञान में लिया गया है। छात्र खेल-खेल में एवं गतिविधियों द्वारा सीखें जिससे उन छात्रों में सृजनात्मकता, रचनात्मकता एवं नवाचार की दृष्टि का विकास हो सके, इस प्रकार के प्रविधान किए गए हैं। चरित्र-निर्माण हेतु भारतीय मूल्यों, संवैधानिक मूल्यों एवं सामुदायिक सेवा आदि का समावेश किया गया है। छात्रों के समग्र विकास हेतु सैद्धांतिक ज्ञान के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास का विद्यालयी शिक्षा से ही पाठ्यक्रमों में समावेश की बातें हैं। इस प्रकार छात्रों को रोजगारपरक शिक्षा प्रदान कर उन्हें रोजगार की याचना करने वाले से रोजगार देने वाला बनाने की संकल्पना पूरी होगी। इससे देश आत्मनिर्भरता की दिशा में भी आगे बढ़ेगा।

किसी भी देश के विकास में शोध कार्य का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है, इस हेतु शिक्षा नीति में 'राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान' के गठन का प्रविधान किया गया है। छात्रों के समग्र विकास से ही देश एवं समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी एवं राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों के समाधान हेतु छात्र सक्षम बनेंगे। किसी भी देश का निर्माण अतीत को विस्मृत करके नहीं किया जा सकता। इस शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेश के साथ-साथ ई-लर्निंग, आनलाइन शिक्षा आदि के प्रविधान द्वारा प्राचीन एवं आधुनिकता के समन्वय की बात कही गई है। इसी प्रकार विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के साथ आध्यात्मिकता को जोड़ने की बात भी है। इस संबंध में डा राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, 'समय आ गया है जब अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय ही हमें आण्विक युग में सुरक्षा प्रदान कर विकास की ओर उन्मुख कर सकेगा।' वास्तव में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस दिशा में एक सार्थक पहल कही जाएगी।

किसी भी देश का निर्माण मात्र कुछ वर्गों के विकास से संभव नहीं हो सकता। लिहाजा समावेशी शिक्षा अर्थात दलित, पिछड़े-वंचित वर्ग, महिला, शारीरिक दृष्टि से अक्षम तथा गांव-कस्बों, पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्रों के छात्रों के विकास हेतु भी अनेक कदम उठाने होते हैं, जो इस नई नीति में सुस्पष्ट हैं। स्वतंत्रता पश्चात पहली बार ऐसा हुआ है कि सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विशेष शिक्षा क्षेत्र की संकल्पना रखी गयी है। साथ ही छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु एक विशेष 'जेंडर समावेशी कोष' की भी अवधारणा है। देश के विकास में भाषा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मातृभाषा में शिक्षा पूर्ण रूप से वैज्ञानिक दृष्टि है। इस नीति में मातृभाषा अथवा स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक से लेकर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा प्रदान करने की केवल बात नहीं गई है, बल्कि शिक्षा नीति के एक वर्ष निमित्त आयोजित कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री ने इंजीनियरिंग की शिक्षा इसी वर्ष से आठ भारतीय भाषाओं में प्रारंभ करने की घोषणा भी की है।

विद्या ददाति विनयम्... ततः सुखम्

किसी देश की शिक्षा और उस देश की आर्थिकी का संबंध हमारे मनीषियों के एक श्लोक से समझा जा सकता है। विद्या ददाति विनयम्, विनयाद् याति पात्रताम्, पात्रत्वात् धनमाप्नोति। धनाद् धर्मः, ततः सुखम्। यानी विद्या से विनय आती है, विनय हमें हर चीज के लायक बनाती है। जब हम निपुण बनते हैं तो धन की प्राप्ति होती है और फिर हमारे कल्याण स्तर में इजाफा होता है। आधुनिक युग की अर्थव्यवस्था में शिक्षा की अहमियत पर आइए डालते हैं एक नजर:

मजबूत बुनियाद

किसी देश की शिक्षा नीति और वहां के आर्थिक विकास के बीच का संबंध बहुत व्यापक विमर्श का प्रश्न रहा है। समय-समय पर कई एजेंसियों ने इस संबंध में शोध किए हैं। इस मामले में भले ही सीधे आंकड़ों के आधार पर कोई नतीजा देना संभव नहीं है, लेकिन इस बात पर तमाम जानकार एकमत रहे हैं कि किसी देश में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था जितनी सुदृढ़ होती है, वहां की अर्थव्यवस्था को उतनी ही मजबूत बुनियाद मिलती है।

अहम निष्कर्ष

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) शिक्षा और उससे जुड़े सामाजिक-आर्थिक लाभ पर कई अलग-अलग रिपोर्ट निष्कर्ष दिए हैं। ओईसीडी के कुछ अहम निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :

- उच्च शिक्षा से व्यक्ति को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ओईसीडी और इसके सदस्य देशों में उच्च डिग्री वाले लोगों की कमाई अन्य की तुलना में ज्यादा पाई गई है।
- ओईसीडी के सदस्य देशों में उत्तर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त पुरुष से सार्वजनिक संपत्ति में 1,37,700 डालर और महिला से 67,900 डालर का रिटर्न मिलता है। शिक्षा की इस श्रेणी में विश्वविद्यालयों, मैनेजमेंट स्कूल-कालेजों आदि को शामिल किया जाता है।
- छोटी अवधि की विभिन्न उत्तर माध्यमिक डिग्री के मुकाबले ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डाक्टरेट या इसके समकक्ष किसी डिग्री से समाज को ज्यादा रिटर्न मिलता है।
- बच्चों की शुरुआती शिक्षा पर किया गया खर्च व्यक्तिगत रूप से और समाज के स्तर पर बेहतर रिटर्न देता है।

उच्च शिक्षा बनाम सबको प्राथमिक शिक्षा

यह बड़ा प्रश्न है कि ज्यादा से ज्यादा उच्च शिक्षा वाले लोगों पर जोर देना समाज के लिए जरूरी है या सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। अमेरिका के कुछ शोधकर्ताओं ने इसे जानने के लिए अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर विभिन्न देशों का अध्ययन किया। इसमें पाया गया कि किसी देश के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है कि वहां हर नागरिक को प्राथमिक स्तर की शिक्षा मिले और उनमें से बड़ी संख्या उच्च शिक्षा हासिल करे। इन दोनों के योग से ही समाज का संपूर्ण विकास होता है।

गुणवत्ता का सवाल

यूनेस्को की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कम आय वाले देशों में बड़ी आबादी साक्षर हुए बिना ही प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लेती है। निश्चित तौर पर यह शिक्षा की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल है।

केस स्टडी

2008 में घाना में एक अध्ययन में पाया गया था कि 15 से 29 की उम्र की आधी लड़कियां और तिहाई लड़के एक वाक्य भी पढ़ने में सक्षम नहीं थे, जबकि उन्होंने कागजी तौर पर छह साल स्कूली शिक्षा ली थी।

बचती हैं जिंदगियां

आर्थिक के साथ-साथ शिक्षा किसी समाज में स्वास्थ्य के स्तर को भी बेहतर करती है। यूनेस्को ने 2011 में एक आकलन किया था। इसके अनुसार, यदि उप-सहारा क्षेत्र में महिलाएं कम से कम माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर पातीं, तो 2008 में 18 लाख बच्चों का जीवन बचाना संभव होता। शिक्षा प्राप्त करने से व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जागरूक होता है।

जरूरतों का दूरदर्शी अभिलेख

प्रो. निरंजन कुमार
प्रख्यात शिक्षाविद

किसी भी शिक्षा नीति के तीन प्रमुख लक्ष्य होने चाहिए- छात्र-हित, ज्ञान की प्रगति और राष्ट्र निर्माण। एनईपी 2020 तीनों ही लक्ष्यों का एक साथ संधान करने में सक्षम है। इसमें वर्तमान समय की जरूरतों को समझने और उनके अनुरूप शिक्षा का ढांचा बनाने की विधिवत तैयारी दिखती है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी) की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलकुल ठीक कहा कि राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ में एनईपी की बड़ी भूमिका होगी। निसंदेह भारतीयता की महान विरासत से परिपूर्ण, महात्मा गांधी के विजन से अनुप्राणित और डा आंबेडकर के दिए संविधान से प्रतिबद्ध एनईपी आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम है। इसमें एक ओर हमारी शिक्षा व्यवस्था की वर्तमान कमियों को दूर करने के प्रविधान हैं, तो दूसरी ओर 21वीं सदी के बदलते हुए भारत की आंतरिक और वैश्विक चुनौतियों का सामने करने की तैयारी भी। चरित्र निर्माण या अच्छे व्यक्ति के निर्माण के लिए एनईपी विशेष सजग है।

यही नहीं, विद्यार्थी अपनी संभावनाओं-क्षमताओं को पूर्ण साकार कर सकें, इसके लिए स्कूली शिक्षा, उच्चतर शिक्षा से लेकर प्रोफेशनल शिक्षा तक भारतीय भाषाओं में अध्यापन पर बल दिया गया है। अनेक प्रतिभाएं अभी सिर्फ अंग्रेजी माध्यम के कारण पिछड़ जाती हैं। यूनेस्को की 2008 की एक रिपोर्ट के अनुसार मातृभाषा में सीखना आसान होता है। मातृभाषा में बच्चा चीजों को समझता है जबकि इतर भाषाओं में उसे रटना पड़ता है। यह उत्साहजनक है कि अपने यहां आठ राज्यों में तमिल, तेलुगु, मराठी, बांग्ला और हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई आगामी सत्र से शुरू होने जा रही है।

सबका साथ, सबका विकास के लिए सबको शिक्षा की महत्वाकांक्षी योजना एनईपी का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। वर्तमान में राइट टू एजुकेशन आठवीं कक्षा और 14 साल तक के बच्चों के लिए है। एनईपी में एजुकेशन फार आल का लक्ष्य है, जिसमें माध्यमिक स्तर तक 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य और निशुल्क होगी।

आत्मनिर्भर भारत का संबंध रोजगार से भी है। दुर्भाग्य से मैकाले माडल पर आधारित वर्तमान प्रणाली में किताबी ज्ञान पर जोर है, जो नौकरी ढूंढने वाले बेरोजगारों की फौज तैयार कर रही है। एनईपी में महात्मा गांधी के श्रम-सिद्धांत के अनुरूप स्कूल से लेकर कालेज स्तर पर पाठ्यक्रम से इतर क्रियाकलापों, स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी बल है। युवाओं को यह स्वावलंबन की दिशा में ले जाएगा। इससे रोजगार देने वालों यानी स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

एनईपी में स्ट्रीम की वर्तमान खांचेबंदी के खात्मे से अब साइंस या कामर्स का छात्र आर्ट्स-सोशल साइंस के विषय भी पढ़ सकेगा। इससे छात्रों में एक बहुविषयक दृष्टि विकसित होगी। स्नातक स्तर पर मल्टी-एंट्री और मल्टी-एग्जिट स्कीम अथवा हाल में स्थापित एकेडेमिक बैंक आफ क्रेडिट्स अन्य क्रांतिकारी प्रविधान हैं।

इसके अलावा शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन में टेक्नोलाजी पर बल दिया जाएगा। दीक्षा, स्वयं, ई-पीजी पाठशाला या विद्वान आदि डिजिटल प्लेटफार्म इसमें सहायक होंगे। स्वास्थ्य, कृषि, जल और जलवायु परिवर्तन संबंधी योजना-प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिकतम तकनीक को बढ़ावा देने पर भी जोर है।

एनईपी की चुनौतियां भी हैं। गुणवत्तापरक शिक्षकों के लिए नेट/जेआरएफ परीक्षा और पीएचडी प्रवेश परीक्षा में बदलाव की जरूरत है। पाठ्यक्रम पुनर्रचना और डिजिटल डिवाइड अन्य चुनौतियां हैं। बजट की भी समस्या होगी। शिक्षा पर जीडीपी के छह प्रतिशत के बराबर व्यय का लक्ष्य है। लेकिन यह भी ज्यादा नहीं। अन्य वैकल्पिक संसाधन भी तलाशने पड़ेंगे।

भारत लोकल से ग्लोबल, रोजगार से अनुसंधान और चरित्र निर्माण से भौतिक उपलब्धि तक हर दृष्टि से एनईपी 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने वाला एक दूरदर्शी अभिलेख है। शिक्षण-संस्थानों के स्तर पर इसका क्रियान्वयन एक चुनौती अवश्य है, लेकिन योग्य व सक्षम अकादमिक नेतृत्व लाया जाए तो यह कार्य असंभव नहीं।

थोड़ा निवेश ज्यादा रिटर्न

उच्च शिक्षा पर किया गया खर्च समाज के स्तर पर और व्यक्तिगत रूप से बेहतर रिटर्न देता है। पेश है सैकेरोपोलस एंड पैट्रिनोस की रिपोर्ट का निष्कर्ष :

क्षेत्र (रिटर्न प्रतिशत में)	सामाजिक	व्यक्तिगत
एशिया	11.0	18.2
यूरोप/पश्चिम एशिया/उत्तरी अफ्रीका	9.9	18.8
लैटिन अमेरिका/कैरेबियाई	12.3	19.5
ओईसीडी	8.5	11.6
उप-सहारा अफ्रीका	11.3	27.8
वैश्विक औसत	10.3	19.0

केस स्टडी: कौशल विकास में निवेश का आर्थिक संबंध

दक्षिण कोरिया ने कौशल विकास में निवेश किया, जिसका उसकी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर दिखा। 1970 में अर्थव्यवस्था के मामले में लगभग एक ही स्तर पर रहे पांच देश आज बहुत अलग-अलग स्तर पर खड़े हैं। इसमें वहां माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश के अनुपात की अहम भूमिका रही।

बात पते की : श्रमशील आबादी की शिक्षा और योग्यता किसी भी देश में कारोबारी और आर्थिक विकास की कुंजी होती है। जहां पारंपरिक और व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से कुशल श्रम उपलब्ध होता है, वहां उद्योगों के विकास की राह खुलती है। इसलिए सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि पूरी आबादी को बेहतर शिक्षा मिले।

जनमत

क्या बीते एक साल का अनुभव बताता है कि नई शिक्षा नीति शिक्षा क्षेत्र के तमाम विद्रूप दूर करने में कामयाब रही है?

क्या देश की अर्थव्यस्था आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित बनाने में नई शिक्षा नीति और इसके तमाम सहायक कदम कारगर होंगे?

आपकी आवाज

नई शिक्षा नीति सरकार का सही दिशा में उठाया कदम है। इसके तहत भारतीय भाषाओं में पढ़ाई ने उत्साह का संचार किया है। यह इस नीति का अहम पहलू है।
मुकेश कुमार मनन

नई शिक्षा नीति को लागू हुए एक साल हो गया है। निश्चित तौर पर यह नीति सरकार का सद्प्रयास है। इसके सही क्रियान्वयन से देश को आर्थिक और सामाजिक तौर पर उल्लेखनीय लाभ होगा। नागेंद्र कुमार

डिजिटलीकरण और टेक्नोलाजी के क्षेत्र में नित नए विकास के साथ दुनिया बदल रही है। ऐसे में समय के साथ चलना किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है। नई शिक्षा नीति इसी दिशा में उठाया गया जरूरी कदम है। नई शिक्षा नीति देश में आमूलचूल बदलाव लेकर आएगी। इसे सही सोच के साथ बनाया गया है, जिससे बच्चे किताब रटने वाले नहीं, बल्कि उसे समझने वाले बन सकेंगे। सौरभ

सही क्रियान्वयन से पूरा होगा देश का सपना

प्रो (डा.) गोविन्द सिंह
डीन, एकेडमिक अफेयर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली

शिक्षा-व्यवस्था एक लंबी प्रक्रिया का नतीजा होती है। इसे बदलते-बदलते पीढ़ियां लग जाती हैं। मैकाले ने 1835 में भारत के लिए शिक्षा के जिस ढांचे की कल्पना की थी, आजादी के सात दशक बाद भी उसका असर बढ़ता ही जा रहा है। यही बात नई शिक्षा नीति पर भी लागू होती है। देश-समाज पर उसका प्रभाव दशकों बाद दिखने लगेगा।

नई शिक्षा नीति की सफलता का दारोमदार उसे ईमानदारी से लागू किए जाने पर निर्भर है। आजादी के तुरंत बाद यदि देश अपनी जरूरतों के मुताबिक नई शिक्षा नीति लागू करता तो आज यह हालत न होती। कागजी स्तर पर सुधार तो बहुत हुए, लेकिन उन्हें ठीक से लागू नहीं किया गया जिससे मैकाले की आत्मा अजर-अमर होती गयी। हमारी आज की सबसे बड़ी चुनौती यही है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आत्मा में भारतीयता बसती है। मैकाले की परिकल्पना से अलग इस शिक्षा नीति का मकसद एक भारतीय मनुष्य तैयार करना है, जो एक बेहतर विश्व के निर्माण में योगदान करेगा। इसके लिए स्कूली और उच्च शिक्षा में अनेक परिवर्तन सुझाए गए थे। पिछले एक साल में वास्तव में इन सुधारों पर चर्चाएं ही ज्यादा हुई हैं। एक मुश्किल यह रही कि इस बीच कोविड महामारी के चलते जितनी प्रगति होनी चाहिए थी, उतनी नहीं हो पायी। लेकिन जितना काम हुआ है, वह भी कम नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पिछले दिनों इसकी प्रथम वर्षगांठ पर जो घोषणाएं की गईं, उससे निश्चय ही इसमें गति आएगी।

जहां तक उच्च शिक्षा में सुझाए गए बदलावों की बात है, उसके मूल में बहु-अनुशासनिकता प्रमुख है। यानी अब कला, विज्ञान और वाणिज्य जैसी खांचों में बंटी शिक्षा की बजाय युवक के समग्र विकास पर आधारित उदार और लचीली शिक्षा होगी। अब विज्ञान का विद्यार्थी संगीत भी पढ़ पायेगा। साहित्य का विद्यार्थी भी प्रौद्योगिकी सीख पायेगा। यह काम इतना आसान नहीं है। इसके लिए पहले शिक्षकों को अपने मन के भीतर की जंजीरों को तोड़ना होगा, तभी कुछ कामयाबी मिल पाएगी। कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने अंतर-अनुशासनिक विषय पढ़ाने शुरू किये हैं, लेकिन अभी तक उसका खास फायदा नही मिला है क्योंकि शिक्षकों ने ही इसे खुलकर नहीं अपनाया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों को नई शिक्षा नीति के अनुरूप खुद को बदलने के निर्देश दिये हैं, लेकिन अभी संस्थाएं इस पर चर्चाएं ही कर रही हैं।

शिक्षा को और ज्यादा रोजगारोन्मुखी और कौशल केंद्रित बनाने के लिए कालेज शिक्षा के अलग-अलग चरणों से बाहर निकलने और पुनः प्रविष्ट होने की छूट देने को कहा गया है। कुछ विश्वविद्यालयों ने इसकी शुरुआत की है लेकिन अभी वह बेहद अपरिपक्व है, क्योंकि उसके लिए प्रत्येक वर्ष के पाठ्यक्रम को अपने आप में परिपूर्ण बनाना होगा, तभी बाहर निकल कर छात्र को उसके बल पर कोई रोजगार मिल पायेगा। इसी से जुड़ा हुआ बिंदु अकादमिक क्रेडिट बैंक का भी है ताकि बाहर निकलने वाले की पढ़ाई बेकार न जाये और पुनः लौटने पर उसे अपनी पुरानी पढ़ाई का फायदा मिल सके। प्रधानमंत्री ने इसका लोकार्पण तो कर दिया है, लेकिन उसका फायदा तभी हो पायेगा, जब विश्वविद्यालय अपनी स्नातक स्तरीय पढ़ाई की पुनर्रचना करें।

उच्च शिक्षा को टेक्नोलाजी उन्मुख करने की सिफारिश भी महत्वपूर्ण है। अभी तक हमारे उच्च शिक्षा संस्थान, खासकर सरकारी, इस मामले में काफी पिछड़ रहे हैं। संयोग से पिछले एक वर्ष में महामारी ने हमें टेक्नोलाजी अपनाने को मजबूर कर दिया। अब यूजीसी आनलाइन और आफलाइन दोनों ही तरीकों से शिक्षा देने को कह रहा है। इसके लिए मूक और स्वयंप्रभा जैसी सुविधाएं भी हमारे पास हैं। साथ ही इंटरनेट आधारित अध्ययन सामग्री के कोश भी तैयार हो गए हैं। आने वाले वर्षों में इसमें और इजाफा होगा। इससे न सिर्फ शिक्षकों की कमी दूर होगी, बल्कि विद्यार्थियों को भी मनचाहे विषय पढ़ने को मिलेंगे। इसके लिए देश के सुदूर अंचलों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। अर्थात पहले हमें अपनी डिजिटल खाईं को पाटना होगा, तभी इसका सचमुच फायदा होगा।

दुनिया के 100 शीर्ष विश्वविद्यालयों को भारत आने की अनुमति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे निजीकरण में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। साथ ही, बड़ी मात्रा में साल दर साल देश का जो धन बाहर जा रहा है, वह बचेगा। और हम अंतरराष्ट्रीयता की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन असली चुनौती शिक्षा में भारतीय मूल्यों को शामिल करने की है। उच्च शिक्षा में पश्चिम का मोह इतना गहरा है कि उसे निकलते निकलते सदियां लग जायेंगी। ऐसा ही मामला भाषा का भी है। हिंदी और भारतीय भाषाएं आज भी उच्च शिक्षा के मंदिरों में दूसरी पंगत में बैठने को विवश हैं। जब तक गंभीरता से इन्हें लागू नहीं किया जाता, हमारे लिए 'भारतीय नागरिक' तैयार कर पाना एक सपना ही रहेगा।

दैनिक जागरण

दुख के कारण की समझ ही उसका समाधान है

सीमा विवाद का समाधान

सीमा विवाद को लेकर आपस में बुरी तरह उलझे असम और मिजोरम का सुलह की राह पर आना एक राहत की खबर है। इस विवाद ने जिस तरह हिंसक रूप लिया और फिर दोनों राज्य एक-दूसरे पर दोषारोपण करने में जुट गए, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक था। कायदे से तो इस विवाद के हिंसक रूप लेने का कोई औचित्य ही नहीं बनता था, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों ही पक्षों ने आवश्यक संयम और सतर्कता का परिचय नहीं दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि मिजोरम की ओर से की गई गोलीबारी में असम पुलिस के छह जवान और एक नागरिक की जान चली गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था-इसलिए और भी नहीं, क्योंकि दोनों ही राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार है। समझना कठिन है कि सीमा विवाद को लेकर जो तनाव उत्पन्न हो गया था, उसे समय रहते आपसी बातचीत के जरिये हल करने की कोई कोशिश क्यों नहीं की गई? ऐसा न किए जाने के जैसे घातक नतीजे सामने आए, उनसे दोनों ही राज्यों को सबक लेना चाहिए। बीते कुछ दिनों में दोनों राज्य ऐसा व्यवहार करते नजर आए, जैसे वे पड़ोसी राज्य नहीं, बल्कि दो देश हों।

यह ठीक है कि केंद्र सरकार के प्रयासों से असम और मिजोरम आपसी कटुता को दूर करने के लिए सहमत हो गए और इस क्रम में मिजोरम सरकार असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ दर्ज की गई एफआइआर को वापस लेगी, लेकिन केंद्र को भी सबक सीखने की आवश्यकता है। उसे राज्यों के सीमा विवाद को हल करने के लिए कोई ठोस पहल करनी चाहिए। उचित यह होगा कि राज्यों के सीमा विवादों को हल करने के लिए किसी आयोग का गठन किया जाए। इस आयोग को ऐसे सभी विवादों को एक समय सीमा के अंदर हल करने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। इस काम में देर इसलिए नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जैसा सीमा विवाद असम और मिजोरम के बीच है, वैसा ही अन्य अनेक राज्यों के बीच है। असम की बात करें तो शायद ही कोई ऐसा पड़ोसी राज्य हो जिसके साथ उसका सीमा संबंधी विवाद न हो। ऐसे विवाद संबंधित राज्यों के प्रशासन के बीच ही टकराव का कारण नहीं बनते। कई बार वे नागरिकों के बीच भी वैमनस्य पैदा करने का काम करते हैं। जब ऐसा होता है तो उससे राष्ट्रीय सद्भाव को भी क्षति पहुंचती है और राज्यों के बीच असहयोग भाव भी पनपता है। कुछ राज्यों के बीच के सीमा विवाद तो दशकों से चले आ रहे हैं। यदि वे आपसी बातचीत से नहीं सुलझ पा रहे हैं तो फिर केंद्र सरकार को दखल देना ही चाहिए।

डिजिटल लेन-देन

एक समय ऐसा था जब उत्तर प्रदेश में भी पैसा जमा करने या भुगतान लेने के लिए बैंकों में लंबी लाइन लगती थी, लेकिन एटीएम ने इस समस्या का काफी हद तक समाधान कर दिया। इसके बाद तमाम कारणों से जरूरत महसूस होने लगी कि सीधे नकद लेन देन को भी कम किया जा सकता है। इसका समाधान डिजिटल भुगतान के रूप में सामने आया। हालांकि शुरुआत में लोगों के मन में एक डर था और लोग इससे बचते थे, लेकिन कोरोना काल में जिस तरह से लेन-देन की गति बढ़ी है, उससे उम्मीद है कि ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट और ग्राहक सेवा केंद्रों (सीएससी) के बढ़ने पर इसका और भी तेजी से प्रसार होगा। इससे पहले वर्ष 2016 में विमुद्रीकरण हुआ था, तब एक तरह से इसकी ठोस नींव पड़ी थी और आज बहुत कम ही लोग ऐसे मिलेंगे जो किसी न किसी रूप में डिजिटल लेन देन न करते हों। सही मायने में डिजिटल इंडिया का सपना साकार होने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं हम। यह न केवल वक्त की जरूरत थी, बल्कि इससे अपनाना समझदारी भी थी। यही कारण है कि 2020 से मार्च 2021 के बीच देश में डिजिटल भुगतान 30 फीसद बढ़ गया है। खुद रिजर्व बैंक ने यह जानकारी साझा की है। वैसे भी देश में तमाम पेमेंट बैंक या गेटवे इस समय काम कर रहे हैं, तो सभी सरकारी और निजी बैंक भी यह सुविधा दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही अब एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है साइबर ठगी की। क्योंकि यूपीआइ या इंटरनेट पेमेंट की सुविधा लेने के लिए तमाम निजी जानकारियां देनी पड़ती हैं। ये जानकारियां कहीं न कहीं से लीक भी हो रही हैं, जिसका लाभ साइबर ठग उठा रहे हैं। ठगी को रोकने के लिए बैंकों या गेटवे को न केवल ठोस और सुरक्षित तरीका अपनाना पड़ेगा, बल्कि ग्राहकों को यह विश्वास भी दिलाना पड़ेगा कि डिजिटल लेन-देन पूरी तरह सुरक्षित है और उनकी रकम नहीं डूबेगी। ऐसा होने पर आने वाले दिनों में डिजिटल लेन-देन निश्चित रूप से एक नई ऊंचाई छुएगा।

> ग्राहकों को यह विश्वास भी दिलाना पड़ेगा कि डिजिटल लेन-देन पूरी तरह सुरक्षित है और उनकी रकम नहीं डूबेगी। ऐसा होने पर डिजिटल लेन-देन नई ऊंचाई छुएगा

मर्यादा में रहें संसदीय विशेषाधिकार

हृदयनारायण दीक्षित

> विशेषाधिकारों का उद्देश्य संसदीय स्वतंत्रता, प्राधिकार और गरिमा की रक्षा रहा है। इसकी आड़ में आपराधिक कृत्य स्वीकार्य नहीं

संसद को सर्वोच्च विधायी अधिकार प्राप्त हैं। उच्चतम न्यायालय ने भी संसदीय व्यवस्था को संविधान का आधारिक ढांचा बताया है। संसद के अपने विशेषाधिकार हैं। विशेषाधिकार संसद सदस्यों को भी प्राप्त हैं। संविधान के अनुच्छेद 105(1) में कहा गया है कि 'संविधान के उपबंधों, संसद की प्रक्रिया के नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन संसद में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है।' आगे इसी अनुच्छेद के खंड (2) में उल्लिखित है, 'संसद या संसद की समिति में सांसद द्वारा कही गई किसी बात या मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।' संप्रति विपक्ष के कुछ सांसद विचार स्वातंत्र्य को शोर स्वातंत्र्य मानते हैं। वे हंगामे और व्यवधान को भी संसदीय कार्यवाही का अंग मानते हैं। राष्ट्रीय चुनौतियों और जनहित के मूलभूत प्रश्नों पर चर्चा नहीं होती। संविधान के अनुसार सरकार संसद में जवाबदेह है। सदन में संवाद की ही उपयोगिता है। इसी से सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित होती है, लेकिन कुछ समय से सदन में बाधा डालने, नियमावली को तार-तार करने का चलन बढ़ा है। संसद का चालू मानसून सत्र भी कोई अपवाद नहीं।

सदन और उसके सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार सदन संचालन में सुविधा के लिए हैं, न कि आपराधिक कृत्यों के सुरक्षा कवच। केरल विधानसभा में हुए उपद्रव के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने सही फैसला सुनाया है। केरल सरकार के मंत्री वी शिवनकुट्टी और पांच अन्य सदस्यों ने 13 मार्च, 2015 को बजट में बाधा डाली। विपक्षी सदस्यों के रूप में वे विधानसभा कर्मियों से भिड़ गए थे। उन्होंने सभा की संपदा को क्षति पहुंचाई। इसमें करीब 2.2 लाख रुपये का नुकसान हुआ। मुकदमा दर्ज हुआ। मौजूदा केरल सरकार ने उसे वापस लेने की अर्जी लगाई, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने विशेषाधिकार और सदन के भीतर हुए उपद्रवों को अलग-अलग बताया है। कहा है कि विशेषाधिकार आपराधिक मामलों से छूट प्राप्त करने का रास्ता नहीं है। कोर्ट के फैसले में विशेषाधिकार का उल्लेख विचारणीय है। उड़ीसा हाई कोर्ट ने सुरेंद्र मोहंती बनाम नवकृष्ण मामले में कहा था 'कोई भी न्यायालय विधानमंडल सदस्य के सदन में दिए भाषण के आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकता।' हालांकि यहां भाषण की नहीं, बल्कि हिंसा की बात है।

विशेषाधिकारों का उद्देश्य संसदीय स्वतंत्रता, प्राधिकार और गरिमा की रक्षा रहा है। न्यायालय सभा की कार्यवाही नहीं जांच सकते, लेकिन आपराधिक कार्यों के संरक्षण के उद्देश्य से अपराध कर्म को विशेषाधिकार नहीं माना जा सकता। महाराष्ट्र विधानसभा के एक सदस्य ने अपने माइक को लाउडस्पीकर से जोड़ने के लिए आपरेटर पर झल्लाकर पेपरवेट फेंका। अध्यक्ष के माइक पर झपट्टा मारा। सदस्य को सभा से निष्कासित किया गया। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धाराओं में दोषी पाया गया। सदन बाहुबल प्रदर्शन का स्थान नहीं है। यह संवाद का श्रेष्ठतम मंच है, लेकिन यहां का दलतंत्र ही सदन में बाधा डालने की योजना बनाता है। सांसदों और विधायकों को हुल्लड़ के निर्देश दिए जाते हैं। संसदीय प्रणाली पर संसद द्वारा प्रकाशित 'संसदीय पद्धति और प्रक्रिया' में तत्कालीन प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह का प्राक्कथन पठनीय है। उन्होंने लिखा था 'संसद में अनुशासनहीनता और अव्यवस्था से मर्यादा क्षीण होती है। नागरिकों में लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति सम्मान भाव होना चाहिए। आवश्यक है कि संसद लोगों की नजरों में अपनी अधिकाधिक विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए व्यवस्थित ढंग से काम करे।'

अभी संसद सत्र में योजनाबद्ध व्यवधानों से गतिरोध जारी है। तमाम माननीय पोस्टर प्लेकार्ड लाते हैं। हंगामा करते हैं। अध्यक्ष/सभापति की बात नहीं सुनते। हाल में एक माननीय के विरुद्ध कार्रवाई हो चुकी है। अध्यक्ष या सभापति का निर्णय अंतिम होता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन निलंबन की निंदा भी हो गई। निलंबन अच्छा नहीं होता। पीठासीन अधिकारी इसे अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल करते हैं। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय सरकार ने 63 सदस्यों का निलंबन कराया। तब कांग्रेस ने निलंबन की निंदा भी नहीं की थी। 2014 में भी 16 सांसदों का निलंबन हुआ था। आक्रामक व्यवधान के बीच संसद में व्यवस्था बनाना कठिन है। वेल में आना, मंत्रियों से कागज छीनना पराक्रम हो गया है। ऐसे कृत्य लोकतंत्र के विरुद्ध अपराध हैं। व्यवधानकर्ताओं को दंडित करने के लिए 2001 में लोकसभा की नियमावली में 374(क) जोड़ा गया था। इसके अनुसार अध्यक्षीय आसन के सामने शोर करने वाले सदस्य अध्यक्ष द्वारा नाम लेते ही स्वतः निलंबित हो जाते हैं, मगर इसका उपयोग प्रायः नहीं होता।

अवधेश राजपूत

संसदीय व्यवहार का पराभव खतरे की घंटी है। आमजन अपने जनप्रतिनिधियों को शोर मचाते देखकर निराश हैं। दुनिया के अनेक देशों में संसदीय व्यवस्था है। ब्रेक्जिट मामले को छोड़कर ब्रिटिश संसद में प्रायः व्यवधान नहीं हुए। अमेरिकी कांग्रेस में व्यवधान नहीं होते। जापानी संसद डायट भी खूबसूरत ढंग से चलती है। ऐसे देशों ने अपनी संसदीय व्यवस्था का सही विकास किया। भारत की संविधान सभा की कार्यवाही 165 दिन चली थी। 17 सत्र हुए थे। बहस तीखी थीं, लेकिन व्यवधान नहीं थे। पहली लोकसभा में पं. जवाहरलाल नेहरू और डा. श्यामा प्रसाद जैसे महानुभाव थे। पहली दफा 1952 में प्रिवेंटिव डिटेंशन संशोधन विधेयक पर व्यवधान हुआ। 1963 में आधिकारिक भाषा विधेयक पर भी तनातनी थी, मगर ऐसे व्यवधान अपवाद थे। 1968 तक व्यवधान नहीं थे, मगर अब वे आम हो गए हैं।

संसद में सदन संचालन की सुस्पष्ट नियमावली है। फिर भी हंगामा है। आखिर संसदीय कार्यवाही के मुख्य घटक क्या हैं? कुछ समय पहले राहुल गांधी ने सदन में आंख मारने का विचित्र कौशल दिखाया था। लोकसभा नियमावली में संसदीय दीर्घा का संज्ञान लेने पर रोक है। राहुल जी ने दर्शक दीर्घा में बैठे युवकों का ध्यान आकर्षित किया था। कागज छीनने-फाड़ने की घटना ताजी है। क्या ऐसे कृत्य भी सदन के विशेषाधिकार हैं। केरल विधानसभा मामले में सर्वोच्च न्यायपीठ ने ऐसे कृत्यों को विशेषाधिकार से अलग आपराधिक कृत्य माना है। भारत की विश्व प्रतिष्ठा बढ़ रही है, पर संसद और विधानमंडलों का काम उत्पादक नहीं है। सदनों का व्यवधान राष्ट्रीय चिंता है। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलनों में इस पर चर्चा हुई है, पर परिणाम शून्य हैं। संसद ही अपनी प्रक्रिया की विधाता है। आत्मचिंतन ही उपाय है।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

महिलाओं को कमतर दिखाने की कोशिश

ऋतु सारस्वत

> महिलाएं कितनी भी शिक्षित क्यों न हों उन्हें पुरुषों के अपेक्षाकृत नौकरी का कम हकदार माना जाता है

देशकाल की सीमाओं से परे दुनिया भर में आपदा अपने चाहे किसी भी स्वरूप में क्यों न आए, उसके सर्वाधिक दुष्परिणाम आधी आबादी यानी महिलाओं के हिस्से में आते हैं। इसकी पुष्टि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आइएलओ) की हालिया रिपोर्ट से होती है। आइएलओ की रिपोर्ट बताती है कि कोविड-19 ने पुरुषों की तुलना में महिलाओं की नौकरी को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। एक ओर वे महिलाएं हैं जिन्हें उनके नियोक्ताओं ने आर्थिक मंदी के चलते काम से बाहर कर दिया और दूसरी ओर वे जिन्होंने बीते डेढ़ साल में पारिवारिक जिम्मेदारियों के निरंतर बढ़ते दबाव के कारण स्वयं रोजगार छोड़ दिए। अमूमन यह तर्क दिया जाता है कि जब महिलाएं काम से बाहर हो रही थीं तभी पुरुषों के भी रोजगार छीने गए इसलिए सिर्फ महिलाओं की बात करने का कोई औचित्य नहीं बनता है, परंतु क्या वास्तविकता इतनी भर है या इससे इतर कुछ सत्य ऐसे भी हैं, जिनकी चर्चा हम जानबूझकर नहीं करना चाहते? क्या यह सच नहीं है कि महिलाएं कितनी भी प्रतिभाशाली और शिक्षित क्यों न हों उन्हें पुरुषों के मुकाबले नौकरी का अपेक्षाकृत कम हकदार माना जाता है? क्या यह सच नहीं है कि महिलाओं की पहली प्राथमिकता समाज द्वारा परिवार की देखभाल निश्चित की गई है। अगर पेशेवर जिम्मेदारियां किसी भी रूप में पारिवारिक जिम्मेदारियों के आगे अड़चन बनती हैं तो महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे त्वरित रूप से अपनी पेशेवर जिंदगी का त्याग करें। समाज महिलाओं के प्रति इससे भी कहीं अधिक निष्ठुरता बरतता है और उन्हें विकल्प के रूप में देखता है। एक ऐसा विकल्प जिसे आवश्यकता होने पर कार्यबल की मुख्यधारा में सम्मिलित किया जाता है और जब जरूरत समाप्त हो जाए तो पुनः हाशिये पर धकेल दिया जाता है।

इस तथ्य की तह प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध खोलते हैं। 18वीं सदी तक स्त्री को घरेलू दायरों तक सीमित करने वाली वैश्विक सोच यकायक प्रथम विश्व युद्ध के समय तब परिवर्तित हो गई जब सभी स्वस्थ पुरुष सेना में शामिल होने के लिए चले गए। पुरुषों द्वारा खाली जगह की भरपाई महिलाओं द्वारा करने के लिए मुहिम चलाई गई। महिलाओं को राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्य और उनकी विपुल क्षमताओं को याद दिलाया गया। महिलाओं से श्रमबल का हिस्सा बनने के लिए आह्वान किया गया। जिन महिलाओं में मारक क्षमता, आक्रामकता और हिंसक प्रवृत्ति के अभाव का उलाहना देकर उन्हें कमजोर और डरपोक कहा जाता रहा था वे महिलाएं उन सारी धारणाओं को गलत सिद्ध करते हुए उन फैक्ट्रियों में काम करने लगीं, जहां खतरनाक विस्फोटक सामग्री बनती थी। यहां काम करते हुए उनकी त्वचा पीली पड़ गई जिससे उन्हें 'कैनरी' उपनाम दिया गया। परिवहन, अस्पताल और वे तमाम क्षेत्र, जो पुरुषों के एकाधिकार माने जाते थे महिलाओं की उपस्थिति दर्ज करवा रहे थे। यहां तक कि छह हजार रूसी महिलाएं 'बटालियन आफ डेथ' का हिस्सा बनीं, परंतु जैसे ही युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ा 'द रेस्टोरेशन आफ प्री-वार प्रैक्टिस एक्ट-1919' ने महिलाओं पर दबाव बनाया कि वे अपने पद छोड़ दें जिससे विश्व युद्ध से लौटे सैनिक पुनः अपना कार्यभार ग्रहण कर सकें और ऐसा हुआ भी। वे महिलाएं जिन्होंने पुरुषों के समकक्ष ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया उन्हें सिर्फ इसलिए कार्यबल से हटा दिया गया, क्योंकि इस पर पुरुषों का अधिकार माना गया। द्वितीय विश्व युद्ध में इतिहास पुनः दोहराया गया। इस दौरान 60 लाख महिलाओं ने तमाम ऐसी भूमिकाएं निभाईं, जिन पर पुरुषों का वर्चस्व था, परंतु युद्ध समाप्ति के बाद सांस्कृतिक रूढ़िवादियों ने उन पर दबाव बनाया कि वे नौकरी छोड़ दें। यहां तक कि जिन महिलाओं ने ऐसा करने की अनिच्छा जाहिर की, उनको 'फूहड़' कहा गया।

कामकाजी आबादी में बढ़े महिलाओं की हिस्सेदारी। फाइल

एक सदी बीत जाने के बाद भी रूढ़िगत मानसिकता की जकड़बंदी आज भी यथावत कायम है। इस सोच का केंद्र बिंदु वर्चस्व के उस भाव से है, जिसकी उत्पत्ति का स्रोत आर्थिक स्वावलंबन है। यह सर्वविदित सत्य है कि वित्तीय स्वतंत्रता एक ऐसी आवाज देती है जिसे परिवार, समुदाय और देशव्यापी रूप से सुना जाता है। सत्ता और प्रभाव के इस सुख को पुरुषसत्तात्मक व्यवस्था किसी भी स्थिति में बनाए रखना चाहती है। पुरुषसत्तात्मक व्यवस्था में बुद्धिजीवी वर्ग की उपस्थिति महिलाओं के मानसिक और भावनात्मक बल को न केवल क्षीण करती है, अपितु उन्हें यह विश्वास भी दिलाती है कि तथाकथित रूप से आर्थिक संसाधनों पर पुरुषों का ही एकाधिकार सामाजिक संतुलन के लिए आवश्यक है। 1972 में लियोनेल टाइगर और राबिन फाक्स ने अपनी किताब 'द इंपीरियल एनिमल' में जैविक सिद्धांत की व्याख्या की और कहा कि 'लैंगिक श्रम विभाजन जैविक या वंशानुगत होता है। स्त्री पर पुरुष का आधिपत्य लैंगिक जैविक विशेषता है।' दरअसल मानव सभ्यता को जन्मना बताकर यथार्थ को तोड़-मरोड़कर पेश करने की चेष्टा पहली बार नहीं की गई है। 1971 में चार्ल्स डार्विन ने भी कहा था कि स्त्रियां पुरुषों के मुकाबले जैविक रूप से कमजोर होती हैं।

ये तमाम बातें किसी भी वैज्ञानिक शोध से आज तक सिद्ध नहीं हो सकी हैं। अलबत्ता विज्ञानियों ने दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला में नौ हजार साल पुराने एक ऐसे स्थान का पता लगाया जहां महिला शिकारियों को दफनाया जाता था। इस खोज ने उन सभी दावों को एक सिरे से खारिज कर दिया, जो महिलाओं की भूमिका को आदिम काल से ही परिवार और बच्चों की देखभाल तक सीमित कर रहे थे। यह अकाट्य सत्य है कि एक सामाजिक प्रक्रिया के बतौर श्रम के लैंगिक विभाजन के फलस्वरूप महिलाएं भी सामाजिक लिंग रचनाओं को अपने मन मस्तिष्क पर बैठा चुकी हैं, परंतु क्या यह सभ्यता के विकास की अधूरी और अमानवीय परिभाषा नहीं है?

(लेखिका समाजशास्त्र की प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

मित्रता का महत्व

ईश्वर, माता-पिता और गुरु के बाद सबसे महत्वपूर्ण संबंध मित्रता में निहित होता है। भाई-बहन एवं अन्य सगे-संबंधियों से भी बढ़कर मित्रता का यह महत्वपूर्ण संबंध देखा और सुना गया है। वस्तुतः मित्रता का भाव अत्यंत व्यापक है। यही एक मात्र ऐसी भावना है, जो सभी संबंधों में अंतर्निहित होती है। ईश्वर के साथ मित्रता का अनुभव सर्वाधिक चर्चित एवं मुखरित हुआ, जिसकी व्याख्या पुराणों में भरी पड़ी है। उपनिषदों में यह प्रेम की मीमांसा के मूलाधार के रूप में वर्णित है। रामायण और महाभारत में मित्रता के भिन्न रूपों का निरूपण है। राधा-कृष्ण का प्रेम हो या गोपियों संग रास हो, सबमें मित्रता की बात निहित है। कृष्ण-सुदामा का प्रसंग तो मित्रता की सीमाओं को भी लांघता है, जो पटरानी रुक्मिणी तक को असहज करने वाला है। देवलोक में मित्रता का मापदंड है, जिससे सभी देवता बंधे हैं।

धरती पर मानव के लिए पड़ोस, मुहल्ला, गांव, बाजार या नगर-सर्वत्र दोस्ती की पगडंडियां विद्यमान हैं। सामाजिक एवं आर्थिक संबंधों में भी मित्रता की अमर बेल जीवन यात्रा की दिशा तय करती है। भाई-भाई और पति-पत्नी के संबंध भी मित्रता की नींव पर ही सुदृढ़ हो सकते हैं। यही नहीं, मानव तो जानवरों से भी मित्रता का अवसर ढूंढता है। मानवता का मूल्य मित्रता के विभिन्न भावों में अंकित होता है। व्यक्तियों की तरह देशों में भी मित्रता होती है, परस्पर मधुर संबंध होते हैं। दो राष्ट्रों के बीच मित्रता ने शांति का मार्ग प्रशस्त किया है।

मानव की मित्रता उसके जीवन को आयाम देती है, नया संसार रचती है। मित्रता, जिसे संगति के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है, हर मनुष्य की वैचारिक पूंजी की तरह है। यह मानव की मानसिक यात्रा भी है, जो सपनों को साकार करती है। एक बौद्धिक यात्रा है, जो चरित्र का निर्माण करती है। मित्रता पथप्रदर्शन है, हित चिंतन है, सहयोग है, समर्थन है, प्रेम है, समर्पण है। यह अटूट बंधन है। वास्तव में यह जीवन की एक अनमोल कड़ी है।

डा. राघवेंद्र शुक्ल

मां के दूध पर बच्चे का अधिकार

डा. महेश परिमल

> माताएं यह न भूलें कि वे अपने बच्चे को एक वर्ष तक अपना दूध पिलाकर उनका भविष्य संवार रही हैं

आज देश में कुपोषण से मासूमों की मौतें हो रही हैं। विश्व में कुपोषण से जितनी मौतें हो रही हैं, उसका 40 प्रतिशत हिस्सा केवल भारत के पाले में आता है। इस दिशा में जिस तरह के जागरूकता की आवश्यकता है, उतनी अभी तक आम नागरिकों में नहीं पहुंच पाई है। दूसरी ओर आज की कुछ आधुनिक माताएं बेबी फूड के जाल में ऐसे उलझ गई हैं कि अपने ही बच्चे को अपना दूध पिलाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। यह एक मासूम को उसके अधिकार से वंचित करने का षड्यंत्र है, जिसका शिकार आज की माताएं हो रही हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जाल हमें इस तरह से भ्रमित कर रहा है कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यह विकट स्थिति है। हमें इस मायाजाल से बचकर निकलना ही होगा।

हालांकि कई माताएं कामकाजी होती हैं। इन माताओं के लिए अपने बच्चे को दूध पिलाना सचमुच एक गंभीर समस्या है। अभी इसे भारतीय परिवेश में नहीं देखा गया है। किंतु अमेरिका में अब माताओं के लिए उनकी आफिस में यह व्यवस्था की जाने लगी है, जहां वे इत्मीनान से अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं। अमेरिकी महिलाएं इसके लिए कोर्ट जा रही हैं और आंदोलन कर रही हैं। अभी कुछ महीने पूर्व अमेरिका में एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें कई महिलाएं एक डिपार्टमेंटल स्टोर की सीढ़ियों पर अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं। यह उस आंदोलन का एक छोटा सा हिस्सा था, जिसमें माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए स्थान की मांग कर रही हैं।

आखिर कुछ भारतीय माताएं ऐसा क्यों सोचती हैं कि वे यदि अपने बच्चे को दूध पिलाएंगी तो उसका शरीर बेडौल हो जाएगा। क्या शरीर का आकर्षक बच्चे के भविष्य में अधिक आवश्यक है? इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत के गरीब बच्चे अधिक खुशकिस्मत हैं। उन्हें मां के दूध के सिवाय और कुछ नहीं मिलता। इसलिए बच्चा कम से कम एक साल तक तो मां के दूध से वंचित नहीं रहता। बच्चे को दूध न पिलाने की प्रवृत्ति कुछ शिक्षित महिलाओं में ही अधिक देखी जाती है।

अभी हमारे देश में ऐसी व्यवस्था कम ही हो पाई है, जहां मां का दूध फ्रिज करके रखा जाता है। ऐसी माताएं भी नहीं हैं, जो अपने दूध को मिल्क बैंक में देती हों। हां दूसरों के बच्चों को अपना दूध पिलाने की परंपरा अवश्य है। पर यह परंपरा केवल उन माताओं तक ही सीमित है जो गरीबी से त्रस्त होकर केवल धन कमाने के लिए ऐसा कर रही हैं। माताएं यह न भूलें कि वे अपनी संतान को एक वर्ष तक अपना दूध पिलाकर उसका भविष्य संवार रही हैं, उसके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को विकसित कर रही हैं और उसे सबल बना रही हैं, भविष्य में विषमताओं से जूझने के लिए। अंत में उन माताओं को प्रणाम, जो आज भी अपने दूध पर संतान का अधिकार समझती हैं, उसे दूध पिलाती हैं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

न्यायपालिका की भूमिका

'नए मिजाज वाली न्यायपालिका' शीर्षक से लिखे अपने आलेख में ए. सूर्यप्रकाश ने लिखा है कि जो देश की न्यायपालिका के मिजाज को भांपने में नाकाम रहेगा उसे उसकी तपिश झेलनी पड़ेगी। लेखक ने अमेरिकन बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम का हवाला दिया है जिसमें न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने देश के नागरिकों की सुरक्षा में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और दायित्व पर प्रकाश डाला था और कहा था कि जहां कार्यकारी और विधायी कदमों से नागरिकों के मूल मानव अधिकारों का उल्लंघन हो वहां संविधान के संरक्षक के रूप में सुप्रीम कोर्ट को आगे आना होगा। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ किसान संगठनों की धरनेबाजी से आजिज आम लोगों को राहत और न्याय देने की जरूरत क्यों नहीं समझ रहा है? शाहीन बाग मामले में देर से लिए सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का क्या मूल्य-महत्व, जो यह कहता है कि धरना-प्रदर्शन के नाम पर सार्वजनिक स्थलों पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं किया जा सकता है। क्या सात माह की अवधि अनिश्चितकाल के दायरे में नहीं आती? अगर नहीं आती तो यह अंधेर के अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा बंगाल चुनाव बाद टीएमसी द्वारा प्रायोजित हिंसा में उसे वोट न देने वालों को चुन-चुनकर प्रताड़ित किया गया। कुछ की हत्या की गई, कुछ के घर-दुकान में तोड़फोड़ तथा आगजनी की गई। साथ ही तमाम लोगों का बहिष्कार किया गया जो आज तक जारी है। तमाम लोगों को टीएमसी के कार्यकर्ताओं के डर से पलायन करना पड़ा। देश के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। कायदे से सुप्रीम कोर्ट को उस भयावह हिंसा का स्वतः ज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बाद में जब इस हिंसा की जांच कराने के लिए याचिका दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट की एक न्यायाधीश ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। दूसरी तारीख में एक और न्यायाधीश ने भी ऐसा किया। ऐसा करने का कारण भी नहीं बताया गया। क्या लेखक अब भी यह कह सकते हैं कि जब चीजें गलत होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट लोगों के साथ खड़ा होता है? ऐसे में क्यों मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में लोगों के साथ खड़ा है।

saraswat.anil14@gmail.com

संसद में संयम वरते विपक्ष

संसद में जो अभी हो रहा है, वह कतई उचित नहीं है। संसद नहीं चलने देना लोकतंत्र की मर्यादाओं का उल्लंघन है। एक समय था जब पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बोलने के लिए हाथ खड़ा नहीं करते थे। जब उन्हें हस्तक्षेप करना जरूरी लगता था तो वे खड़े हो जाते थे। लोकसभा अध्यक्ष उन्हें नियम नहीं सिखाते थे। चंद्रशेखर को सुनने के लिए सभी सदस्य उत्सुक रहते थे। जरूरी नहीं था कि वे विपक्ष की ओर से बोलें। कई वार तो दोनों को लताड़ लगाकर बैठ जाते थे। सांसद का दायित्व है कि संसद को वाद विवाद और संवाद का मंच बनाए। संसद बनी ही इसीलिए है कि वह अपना काम करे। उसका काम है-विधान बनाना, जनहित के मसलों पर बहस करना और लोक महत्व के विषयों पर तत्काल ध्यान देना। इस प्रक्रिया में विपक्ष की भूमिका निर्धारित होती है। वह संसदीय प्रक्रियाओं से सरकार को जवाबदेह बना सकता है, लेकिन वह हल्ला बोल और हंगामे पर उतारू है। हर बात पर वाकआउट करना गलत है। यह संसदीय परंपरा का अपमान है।

कांतिलाल मांडोत सूरत, दिल्ली

प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना होगा

'पहाड़ों से छेड़छाड़ के घातक नतीजे' नामक आलेख में इनकी हिफाजत रखने पर विशेष बल दिया गया है। बढ़ती मानवीय दखलंदाजी ने आज पहाड़ों को इतना खोखला बना दिया है कि प्रकृति की यह अनूठी रचना टूटकर आसपास की बस्तियों गांवों पर बिखर रही है। ऊंची चट्टानें आज कमजोर होकर बदला लेती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसे हम भूस्खलन या पहाड़ों के खिसकने का नाम दे सकते हैं। आज हमें अपनी और आने वाली पीढ़ियों के सुखद भविष्य के लिए ऐसे सामूहिक प्रयासों की जरूरत है जो इन पहाड़ों को टूटने और खिसकने से बचा सके।

पवन कुमार मुरली, गुरुग्राम

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHI/2017/74721

164.6 किमी सीमा असम के कछार, करीमगंज और हैलाकांडी जिलों से लगती है मिजोरम के तीन जिलों आइजोल, कोलासिब और मामित से। मिजोरम का आरोप है कि असम ने उसके कोलासिब जिले के कुछ हिस्से पर कब्जा जमा लिया है।

आजकल

राज्यों में फिर से उभरी सीमा विवाद की चुनौती

हमारा देश बाहरी सीमाओं की सुरक्षा की चुनौतियों से जूझ रहा है। चीन सीमा पर लद्दाख में पिछले एक साल से भी अधिक समय से तनाव जारी है। पाकिस्तान सीमा पर स्थिति हमेशा संघर्ष वाली बनी रहती है। इन दिनों इस सीमा पर ड्रोन हमलों ने स्थिति को चुनौतीपूर्ण बना रखा है। ऐसे समय में यदि देश की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां उत्पन्न हो जाएं तो यह स्थिति चिंतनीय होगी। असम-मिजोरम के हालिया सीमा विवाद ने चिंतनीय स्थिति उत्पन्न कर दी है। भारत सरकार को इसे शीघ्र सुलझाना चाहिए, अन्यथा देश को नुकसान पहुंचाने वाली ताकतें इसका फायदा उठा सकती हैं

डा. लक्ष्मी शंकर यादव
पूर्व प्राध्यापक, सैन्य विज्ञान विषय

बीते माह की 26 तारीख को हुई हिंसक झड़प के बाद असम-मिजोरम के बीच का सीमा विवाद शांत पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। असम सरकार ने दावा किया है कि उनके नागरिकों को मिजोरम के लोग धमका रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए नागरिकों को पड़ोसी राज्य में न जाने की सलाह दी गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा का कहना है कि उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, तब तक वे मिजोरम की यात्रा न करें। उन्होंने कहा कि मिजोरम के लोगों के पास एके-47 और स्नाइपर राइफलें हैं। मिजोरम सरकार को अपने नागरिकों से इन हथियारों को जब्त करना चाहिए।

दूसरी तरफ सीमा विवाद के चलते मिजोरम पुलिस ने असम के चार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और दो प्रशासनिक अधिकारियों समेत करीब 200 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोलासिब जिले के वैरेंगटे पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है। इस तरह के मामलों से स्थिति सुधरने की उम्मीद का आकलन किया जा सकता है। मिजोरम के पुलिस महानिरीक्षक जान नेहलिया का कहना है कि इन सभी पर हत्या की कोशिश और आपराधिक साजिश समेत कई आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है। जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है उनमें असम पुलिस के आइजी अनुराग अग्रवाल, डीआइजी देवज्योति मुखर्जी, कछार के एसपी चंद्रकांत निंबालकर, कछार उपायुक्त कीर्ति जल्ली आदि प्रमुख हैं। मिजोरम में असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने से दोनों राज्यों के बीच एक बार विवाद फिर बढ़ गया है।

असम और मिजोरम के मध्य सीमा पर बीते 26 जुलाई को अचानक हुआ विवाद उग्र होकर खूनी खेल में बदल गया था। इस खूनी खेल में दोनों राज्यों की पुलिस और नागरिकों के बीच लाठी-डंडे चले और गोलीबारी भी हुई। यह घटना असम के कछार जिले की सीमा पर हुई। इस तनावपूर्ण स्थिति से पहले असम राइफल्स ने 22 जून को दो व्यक्तियों को पकड़ा और म्यांमार से तस्करी कर लाए जा रहे युद्ध संबंधी सामग्री का एक बड़ा जखीरा बरामद किया। 26 जुलाई की घटना के बाद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए तथा एक-दूसरे के पुलिस बल को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। इतना किए जाने के बाद दोनों मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार से अविलंब हस्तक्षेप का अनुरोध किया। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने असम की पुलिस पर लाठीचार्ज करने तथा आंसू गैस के गोले छोड़े जाने के आरोप लगाए। वहीं असम की पुलिस ने यह बताया कि मिजोरम की तरफ से भारी संख्या में आए बदमाशों ने पथराव करते हुए अधिकारियों पर भी हमले किए।

दरअसल असम और मिजोरम की सीमा का विवाद काफी पुराना मसला है। इसे सुलझाने के लिए अनेक बार प्रयास किए गए, लेकिन सारे प्रयास असफल ही साबित हुए। मालूम हो कि मिजोरम के तीन जिले आइजोल, कोलासिब और मामित की 164.6 किमी की सीमा असम के कछार, करीमगंज और हैलाकांडी जिलों से लगती है। मिजोरम का आरोप है कि असम ने उसके कोलासिब जिले के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया है। वहीं असम के लोगों का कहना है कि मिजोरम ने उसके हैलाकांडी जिले में 10 किमी अंदर तक निर्माण कार्य कर लिया है और वहां केले आदि की खेती करते हैं।

असम तथा मिजोरम का सीमा विवाद ब्रिटिश शासन के समय से चला आ रहा है। उस समय मिजोरम को असम का लुशाई हिल्स कहा जाता था। वर्ष 1950 में असम राज्य बन गया। उस समय असम में आज के अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नगालैंड आते थे। बाद में असम से ये अलग हो गए, लेकिन कुछ बातों को लेकर इनके सीमा विवाद जारी रहे। नार्थ ईस्टर्न एरिया री-आर्गनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत असम से अलग कर त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को राज्यों का दर्जा प्रदान कर दिया गया। वर्ष 1987 में मिजोरम को भी अलग राज्य बना दिया गया। यह निर्णय मिजो आदिवासियों और केंद्र सरकार के बीच हुए समझौते के तहत था और इसका आधार 1933 का नोटिफिकेशन था, लेकिन मिजो आदिवासियों का कहना है कि उन्होंने 1875 वाले नोटिफिकेशन को स्वीकार किया है। इसके बाद से विवाद बढ़ता गया।

30 जून 1986 को मिजोरम के नेताओं ने मिजो समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें ही सीमा तय की गई है। परंतु इस मसले पर विवाद अभी भी बना हुआ है। ताजा हिंसा से पहले गत वर्ष अक्टूबर माह में भी दो बार इन राज्यों की सीमा पर आगजनी तथा हिंसा की घटनाएं हुईं थीं। नौ अक्टूबर 2020 को मिजोरम के दो लोगों को आग लगाई गई थी। इसके अलावा कुछ झोपड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि असम और मिजोरम की सीमा आज भी काल्पनिक है और नदियों, पहाड़ों, घाटियों एवं जंगलों के कारण बदलती रहती है। पिछले कुछ वर्षों में यह समस्या और बढ़ गई है। इसके अलावा असम के सीमावर्ती इलाकों के अधिकांश निवासी बंगाली या मुस्लिम हैं।

अब सवाल यह है कि वर्तमान में हमारा देश कई बाहरी सुरक्षा चुनौतियों से लड़ रहा है, ऐसे में यदि उसे आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से जूझना पड़ा तो यह एक नई समस्या होगी। इसलिए ऐसी समस्याओं का स्थायी समाधान खोजना होगा। असम-मिजोरम सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है। वर्ष 1995 में इस इलाके में एक निर्जन पट्टी बनाने का सुझाव दिया गया था, तब भी मिजोरम के लोगों ने इसे मानने से इन्कार कर दिया था। उम्मीद की जानी चाहिए कि केंद्र सरकार की पहल पर उचित तालमेल बिठाकर इस समस्या का हल निकाल लिया जाएगा, अन्यथा आंतरिक सुरक्षा की ये समस्याएं देश के लिए नई चुनौतियां प्रस्तुत कर सकती हैं।

असम-मिजोरम की सीमा पर हाल में हुई हिंसक झड़प के बाद भारी संख्या में वहां पुलिस बलों की तैनाती की गई है। फाइल

केंद्र के हस्तक्षेप से जल्द हो समाधान

शाहिद ए चौधरी

भारत में जब सैकड़ों रियासतें थीं तो भूमि-विस्तार या अन्य कारणों से उनके बीच आपस में हिंसक झड़पें होती रहती थीं। वर्ष 1947 में देश की आजादी के बाद भूमि-विवाद अंतरराष्ट्रीय सीमाओं या एलएसी (वास्तविक नियंत्रण रेखा) तक सिमटकर रह गए। हां, स्वतंत्र भारत में दो राज्यों के बीच जल-विवाद व भूमि-विवाद अवश्य हुए हैं (अब भी काफी जगह पर हैं) जिन्हें आयोग, ट्रिब्यूनल, आपसी विचार-विमर्श, अदालत आदि के माध्यम से सुलझा लिया गया या सुलझाने का प्रयास जारी है। अगर कभी किसी भूमि-विवाद (जैसे बेलगाम को लेकर महाराष्ट्र व कर्नाटक के बीच) या जल-विवाद (जैसे कावेरी के जल को लेकर कर्नाटक व तमिलनाडु के बीच) के संबंध में जनता में तनाव व्याप्त हुआ भी तो उसे राज्यों ने अपने-अपने स्तर पर नियंत्रित कर लिया। दो राज्यों के बीच जनता या पुलिस के स्तर पर हिंसक टकराव नहीं होने दिया। इसलिए असम व मिजोरम के पुलिस बलों के बीच जो पिछले दिनों गोलियां चलीं, जिसमें छह पुलिसकर्मी मारे गए, वह अप्रत्याशित और बेहद चिंताजनक है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना अति आवश्यक है कि भविष्य में देश की एकता और अखंडता को कमजोर करने वाली इस प्रकार की घटना फिर कभी न हो।

फिलहाल स्थिति यह है कि घटनास्थल के दायरे से दोनों राज्यों की पुलिस लगभग 100 मीटर पीछे हट गई है और वहां केंद्रीय पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। असम पुलिस ने जो स्थान खाली किया है वहां पर सीआरपीएफ की निगरानी है। दोनों तरफ की बंदूकें भले ही शांत हो गई हैं, लेकिन उस इलाके में स्थिति पूरी तरह से शांत नहीं हुई है।

इस हालिया घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में जाने पर यह पता चलता है कि यह विवाद काफी पुराना है। पिछले लंबे अरसे से जारी संघर्ष के बीच साल 2018 के मुख्य टकराव के बाद यह विवाद अगस्त 2020 में एक बार फिर उभरा, जिसके चलते असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने गृहमंत्री अमित शाह से हस्तक्षेप के लिए आग्रह किया था। इसके बाद स्थिति कुछ हद तक शांत और नियंत्रण में आ गई थी, लेकिन दोनों राज्य एक-दूसरे की सीमा का उल्लंघन करने का आरोप लगाते रहे। इस साल फरवरी में एक बार फिर स्थिति विस्फोटक हो गई थी, जिसने कुछ दिन पहले हिंसक रूप धारण कर लिया। हालांकि उससे दो दिन पहले ही गृहमंत्री अमित शाह ने इस विषय पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वार्ता की थी। ध्यान रहे कि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट और बीजेपी गठबंधन में हैं। दो राज्यों के पुलिस बलों के बीच जो असाधारण व भयावह गोलीबारी हुई है उससे केंद्र को यह अंदाजा हो जाना चाहिए कि अंतरराज्यीय विवादों पर 'बस यूं ही चलता रहे' दृष्टिकोण खतरनाक है। असम और मिजोरम विवाद के कुछ तत्वों की आक्रामकता बीते दिनों दो देशों की सीमा पर होने वाले विवाद की तरह दिखी। चूंकि उत्तर-पूर्व अति संवेदनशील क्षेत्र है, इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि वह भड़की चिंगारियों को शोला न बनने दे, विशेषकर इसलिए कि इस विवाद को चीन भूखी बिल्ली की तरह देख रहा होगा।

इस विवाद के केंद्र में सिर्फ अनुमानित ऐतिहासिक सीमा और संविधान द्वारा निर्धारित सीमा के बीच असहमति ही नहीं है, बल्कि भूमि के लिए आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी है, जो उत्तर-पूर्व में गैर-कृषि रोजगार के कारण उत्पन्न हुई है। मिजो शताब्दियों से उन क्षेत्रों का प्रयोग कर रहे हैं जो असम के संवैधानिक सीमा में समझे जाते हैं, जबकि असम का इन क्षेत्रों पर दावा बढ़ती आबादी के कारण है। इस इलाके में उत्तर-पूर्व केंद्रित अनेक केंद्रीय योजनाएं चल रही हैं। इनकी सफलता का एक पैमाना इनकी रोजगार केंद्रित निवेश आकर्षित करने की क्षमता होनी चाहिए।

बहरहाल, हाल की हिंसा बताती है कि उत्तर-पूर्व में इस प्रकार के सीमा विवाद कितने घातक हो सकते हैं। इसलिए केंद्र को चाहिए कि जल्द कोई राजनीतिक समाधान निकाले। (ईआरसी)

खरी-खरी

गुरु ढूंढन मैं चला...

डा. साधना बलवटे

गुरु के दर्शन करने एक दिन उनकी पहाड़ी पर चला गया। पहाड़ी मतलब शहर के बीच पाश लोकेशन वाली पहाड़ी, जिस पर बने शानदार बंगले में रहते थे वे। मन तड़पत गुरु दरसन को आज... गाते हुए दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाजा खुला तो सामने खिचड़ी दाढ़ी, लंबा-ढीला कुर्ता, अधफटी जींस और पिज्जा के एक्स्ट्रा चीज से सनी अंगुलियों वाले एक प्राणी के दर्शन हुए। लगा कि मैंने उन्हें खाते समय डिस्टर्ब कर दिया, सो तुरंत कहा- क्षमा गुरुजी, आप भोजन कर लीजिए, हम थोड़ी देर में आते हैं।

वे बोले- पहले तो ये गुरुजी बोलना बंद करो, बहुत ओल्ड फैशन्ड, राष्ट्रवादी टाइप का सांप्रदायिक शब्द लगता है। तुम मुझे टीचरजी या सर कह सकते हो। उस्ताद भी कह सकते हो। ये सारे शब्द सेक्युलर लगते हैं।

वे हाथ धोकर आए और बोले, कहो, कैसे आना हुआ।

बस आप जैसे वरिष्ठ से कविता सीख लें तो धन्य हो जाएं।

वरिष्ठ शब्द ने सुनकर उनकी गर्दन तनकर और गरिष्ठ हो गई। वे बोले- कुछ लिखा हो तो पहले वह सुनाओ।

आज ही लिखा है सर, देखिए...

पाहुन आए बदरा, धरती का रूप है निखरा।

यह सुन वे हत्थे से उखड़ गए। तेज स्वर में बोले- 16वीं सदी के माडल हो क्या। ये पाहुन बदरा, बकवास है, कल्पना है। कौन सुनेगा इसे? कविता में कुछ अट्रैक्शन होना चाहिए।

जी, समझ गया सर।

बदरा आए, भीगा मन, भीग गया यौवन।

अब ठीक है सर?

ये क्या फीका-फीका लिख रहे हो। कवि हो, थोड़ा बोल्ड लिखो। ड्राइंग रूम में बैठे रहोगे तो कविता औपचारिक रहेगी। जरा बेडरूम तक जाओ, भाव पैदा होगा। भाव के अभाव में कोई भाव नहीं देगा।

बरखा टूट गई, मिट गई, चू रही है आसमान से टप टपक टप। भीग रहा यौवन टपक, टपक..। इतना कहकर उन्होंने वाह-वाह सुनना चाहा, मगर अपन ने प्रश्न दाग दिया- लेकिन इससे समाज में क्या संदेश जाएगा?

तुम कवि हो या समाज सुधारक? व्यक्ति की स्वतंत्रता भी कोई चीज होती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की तलवार उठाओ, शब्दों से मारकाट मचाओ और कुछ ऊटपटांग सा लिखो, तभी तुम चल निकलोगे।

ट्वीट-ट्वीट

अमेरिका में जहां 24 वैश्विक धरोहर हैं, वहीं करीब 8,000 साल पुरानी भारतीय सभ्यता में उनकी संख्या 40 है। हमारे पास जिस किस्म की समृद्ध विरासत है, उसे देखते हुए विरासत स्थलों की सूची 400 होनी चाहिए।
आनंद रंगनाथन@ARanganathan72

यह समय है जब पूर्वोत्तर के लड़के-लड़कियां ओलिंपिक के लिए महत्वाकांक्षा पालें, इस समय विभाजनकारी भावनाएं पलना बेहद खतरनाक है। फिलहाल असम और मिजोरम के लोगों को यही समझना चाहिए कि पूर्वोत्तर एक क्षेत्र है और हर कोई भारतीय है।
हर्ष वर्धन त्रिपाठी@MediaHarshVT

गुलाम कश्मीर में आयोजित होने वाली क्रिकेट लीग को लेकर बीसीसीआइ ने जो कड़ा रुख अपनाया है वह एकदम सही है। इसे राजनीतिक एजेंडा बताने वाले जान लें कि यही सही एजेंडा है।
प्रियंका चतुर्वेदी@priyankac19

पीवी सिंधू ने चीनी खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक जीता। चाहे सीमा हो या खेल का मैदान चीन के खिलाफ भारतीय हर मोर्चे पर इक्कीस हैं। दो ओलिंपिक पदक अपने नाम करने वाली सिंधू वास्तव में गोल्डन गर्ल हैं।
हर्ष गोयनका@hvgoenka

इस ओलिंपिक में भारत के लिए अभी तक जो भी पदक सुनिश्चित हुए हैं वे सभी महिला खिलाड़ियों की मेहरबानी से आए हैं।
विक्रम चंद्रा@vikramchandra

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या तालिबान के अफगानिस्तान में काबिज होने से कश्मीर के लिए खतरा बढ़ेगा?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या पुलिस सुधार किए बिना पुलिस की छवि में सकारात्मक परिवर्तन आना मुश्किल है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

रहा सुदामा झंखता श्री कृष्णा के द्वार,
जो द्वापर में थी दशा वही पुन: इक बार।
वही पुन: इक बार न मिलती उनको थाली,
रहकर भूखे पेट खा रहे सबकी गाली!
युग बदले पर आज तलक ना बदला ड्रामा,
उम्मीदों में सिर्फ वोट दे रहा सुदामा!!
– ओमप्रकाश तिवारी

प्रतिरोध बनाम प्रतिरोधक क्षमता की राजनीति

राजू मिश्र
वरिष्ठ समाचार संपादक, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश डायरी

उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल धीरे-धीरे तेजी पकड़ती जा रही है। समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनावी यात्रा पर निकल पड़े हैं तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के बहाने ब्राह्मणों को उनकी उपेक्षा याद दिलाने निकले हैं। कांग्रेस की प्रभारी महासचिव प्रियंका वाड्रा भी प्रदेश में संगठन को निचले स्तर पर खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। लक्ष्य यही है कि अगले विधानसभा चुनाव में सत्ता पक्ष के प्रतिरोध की राजनीति के समीकरणों को अपने पक्ष में साधा जाए। प्रतिरोध के वह मुद्दे तलाश कर उछाले जाएं जो उसे अगले चुनाव में जाने का आत्मविश्वास दे सकें।

वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष प्रतिरोध की इस राजनीति को ध्वस्त करने के लिए सारा ध्यान लोगों में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में लगा रही है। प्रत्यक्ष में यह प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने का उपक्रम कोरोना संक्रमण के खिलाफ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता है कि कोरोना के खिलाफ यदि चुनाव से पहले वह प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने का लक्ष्य हासिल कर लेती है तो यह सियासी लड़ाई लड़ने में बड़ी कारगर साबित होगी। जुलाई महीने के टीकाकरण के आंकड़े और सीरो सर्वे के नतीजे सत्ता पक्ष को उत्साहित करने वाले हैं।

प्रदेश में सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के वह हर उपाय कर रही है, जो उसे दूसरी लहर में सबक के रूप में मिले हैं। चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र का बुनियादी ढांचा दुरुस्त करने की बात हो या इस वर्ष के खत्म होने से पहले शत प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने का। इस बीच सीरो सर्वे के आए नतीजे उत्तर प्रदेश के लिए काफी राहत भरे हैं। 14 जून से लेकर 16 जुलाई के बीच कराए गए सीरो सर्वे में लगभग 71 फीसद लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबाडी मिली है। यह एंटीबाडी दो तरह से बनी है। एक तो उन लोगों में जो दूसरी लहर में अपनी प्रतिरोधक क्षमता से जाने-अनजाने इस महामारी की चपेट में आकर उबर गए। इसमें बड़ी तादाद 18 वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों की भी है, जिन्हें संभावित तीसरी लहर के लिहाज से अब तक महामारी का आसान शिकार माना जा रहा था। यह आशंका पूरी तरह निर्मूल तो नहीं हुई, लेकिन जिस अनुपात में बच्चों में एंटीबाडी मिली उसी निश्चिंतता के कारण ही उत्तर प्रदेश सरकार अब स्कूल-कालेजों को खोलने और पढ़ाई-लिखाई का सामान्य माहौल बनाने में जुटी है।

लखनऊ के एक नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना रोधी टीका लगवाती लाभार्थी। पंकज ओझा

जिन लोगों में एंटी बाडी मिली है, उसका सीधा अर्थ है कि यदि तीसरी लहर व्यापक होती भी है तो इतनी आबादी के बावजूद कम से लोगों के अस्पताल पहुंचने की आशंका रहेगी और मौजूदा स्वास्थ्य ढांचा आसानी से उन्हें उपचारित कर घर भेजने के लिए सक्षम है। यानी सिर्फ 29 फीसद आबादी ही ऐसी बची है, जिसे जल्द से जल्द टीकाकरण कर कम से कम हर्ड इम्युनिटी के स्तर तक पहुंचा जा सकता है। इसीलिए सीरो सर्वे में मिली एंटी बाडी के दूसरे तरीके पर भी पूरा जोर है। उत्तर प्रदेश में टीकाकरण की रफ्तार देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में काफी तेज है। संख्या की बात करें तो राज्य में अब तक 4.75 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। इसमें भी खास तौर पर जुलाई में डेढ़ करोड़ टीके लगे। खुद केंद्र ने योगी सरकार द्वारा अपनाए गए क्लस्टर एप्रोच और पिंक वैक्सीनेशन बूथ की रणनीति को काफी कारगर माना है।

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार जानती है कि यदि वह प्रदेश की आबादी को कोरोना के खतरे के खिलाफ टीके की ढाल (प्रतिरोधक क्षमता) मुहैया करा देती है तो बंटे और अपेक्षाकृत निष्क्रिय विपक्ष के प्रतिरोध को चुनाव में आसानी से पराजित कर सकती है।

हाई कोर्ट की जरूरी नसीहत : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शनिवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान जो नसीहत दी है, वह जरूरी और मौजूदा दौर में बेहद प्रासंगिक है। हाई कोर्ट ने कहा है कि संविधान प्रत्येक बालिग नागरिक को अपनी मर्जी से धर्म अपनाने और पसंद का विवाह करने की स्वतंत्रता देता है। इस पर कोई वैधानिक रोक नहीं है। कोर्ट ने यह नसीहत दी कि विवाह के लिए धर्म बदलना शून्य व स्वीकार्य नहीं हो सकता। कोर्ट ने याद दिलाया कि बहुसंख्यकों (बहुल नागरिकों) के धर्म बदलने से देश कमजोर होता है। साथ ही इससे विघटनकारी शक्तियों को लाभ मिलता है। इतिहास गवाह है कि हम बंटे, देश पर आक्रमण हुआ और हम गुलाम हुए।

कोर्ट ने धर्म परिवर्तन को वैधानिक मानते हुए भी जिस खतरे की ओर इशारा किया वह महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने कहा कि घर में उपेक्षा से लोग घर छोड़ देते हैं। धर्म में सम्मान न मिलने से धर्म बदल देते हैं। लोग डर, भय, लालच में धर्म नहीं बदलते, बल्कि उपेक्षा, अपमान के कारण स्वतः धर्म परिवर्तन करते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरे धर्म में उन्हें सम्मान मिलेगा। इसलिए धर्म के ठेकेदार जो जातीय अपमान करते हैं, अपने अंदर सुधार लाएं। कोर्ट ने एक तरह से बहुसंख्यक समाज में व्याप्त उन कुरीतियों की ओर इशारा किया है, जो दीर्घावधि में धर्म परिवर्तन का कारण बनते हैं। इतिहास का उदाहरण देकर इसमें सुधार लाने के प्रति सचेत किया है।

अपनी बात

सबक सीखने को तैयार नहीं हैं कम्युनिस्ट

वामपंथी दलों के नेताओं द्वारा चीनी दूतावास के कार्यक्रम में शामिल होना यह दर्शाता है कि चीन की भारत विरोधी हरकतों से वे लोग कुछ भी सबक सीखने को तैयार नहीं हैं

ब्रजविहारी
brij.choube@nda.jagran.com

यह दिनोंदिन स्पष्ट होता जा रहा है कि देश की कम्युनिस्ट पार्टियों को अपने राजनीतिक भविष्य की कोई चिंता नहीं है। इसलिए एक-एक कर दो राज्य उनके हाथ से फिसल गए। इसके बावजूद उनके पास आने वाले दिनों का कोई खाका नहीं है। अगर ऐसा होता तो इन पार्टियों के शीर्ष प्रतिनिधि हाल में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के 100वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में चीनी दूतावास के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए होते। जिस देश के साथ सीमा पर तनाव चल रहा है और जो हमारी जमीन से पीछे हटने को तैयार नहीं है, उसके देश की पार्टी के कार्यक्रम में जाने से उसे भारत में राजनीतिक रूप से क्या लाभ मिला, यह कोई कामरेड आपको नहीं बता पाएगा। इस बारे में सवाल किए जाने पर वही अहंकार भरा जवाब, आप हमें क्या बताएंगे। हमने तो 35 साल बंगाल में और 25 साल त्रिपुरा में शासन किया है। लगातार दूसरी बार केरल में सत्ता में आए हैं। कहना न होगा कि जो पार्टी भविष्य के बजाय भूत में जीने लगे, उसका तो पतन निश्चित है।

कम्युनिस्ट पार्टियों को अपनी फिक्र होती तो केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) के नेतृत्व वाली वामपंथी सरकार ने लव जिहाद, मतांतरण और आतंकवाद जैसी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के खिलाफ कोई ठोस रणनीति बनाई और लागू की होती। ऐसा नहीं हुआ है। इसके ठीक उलट केरल इस्लामिक कट्टरपंथ का गढ़ बनता जा रहा है। इसमें इतनी ज्यादा संभावना पैदा हो गई है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ अफगानिस्तान में अपना बर्बर शासन स्थापित करने की ओर बढ़ रहे तालिबान के साथ मिलकर कश्मीर के अलावा केरल को भी निशाना बनाने की साजिश रच रही है।

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के 100वें स्थापना दिवस पर दिल्ली में चीनी दूतावास के कार्यक्रम में शामिल वामपंथी दलों के नेता सीताराम येचुरी (ऊपर, दाएं) व डी राजा (नीचे, बाएं)। इंटरनेट मीडिया

ब्रिटेन में रह रहे गुलाम कश्मीर के पत्रकार अमजद अयूब मिर्जा के अनुसार केरल पर पाकिस्तान की नजर अचानक नहीं पड़ी है, बल्कि वह काफी समय से इस पर काम कर रहा है। उल्लेखनीय है कि केरल में हाल ही में अफगानिस्तान में बनी हाई क्वालिटी की ड्रग्स की बरामदगी के मामलों में बढ़ोतरी से स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि राज्य में तालिबान का असर बढ़ रहा है। दो दशक तक अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी के बावजूद पोश्त और उससे निकलने वाली अफीम की खेती-व्यापार पर तालिबान का ही कब्जा है। उसके लिए धन का बड़ा स्रोत अफीम से बनने वाले ड्रग्स की तस्करी है।

इस संबंध में अयूब का पूरा लेख पढ़कर केरल की कम्युनिस्ट सरकार की आंखें खुल जानी चाहिए, लेकिन वह तो कुछ देखना ही नहीं चाहती है। भारत को अस्थिर करने के लिए कश्मीर में पिछले कई दशकों से छद्म युद्ध लड़ रहा पाकिस्तान किसी भी सूरत में तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता पर बिठाना चाहता है। उसके नापाक इरादों को पूरा करने के लिए यह जरूरी है। इसलिए उसने भारत के साथ दिखावे के लिए संघर्ष विराम की घोषणा की है और वहां से सेना हटाकर उन्हें उत्तरी सीमा पर तालिबानियों की मदद में तैनात कर दिया है और भारत में लगातार ड्रोन भेज-भेजकर उसे उलझाए हुए है।

केरल सरकार राज्य में इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं करती है, क्योंकि वही उसके वोटर हैं। वोट की राजनीति के कारण राज्य देश विरोधी तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है। देश के अंदर आतंक की जड़ें मजबूत करने वाला यासीन भटकल केरल का ही रहने वाला है। इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद इस आतंकी की इंडियन मुजाहिदीन की स्थापना में अहम भूमिका थी। देश भर में इस्लामी कट्टरता को बढ़ावा दे रहा पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआइ) का ठिकाना भी केरल ही है।

कश्मीर के बाद केरल में पाकिस्तान के नापाक मंसूबे अगर सच साबित होते हैं तो भारत की खुफिया एजेंसियों और सैन्य बलों के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती होती। यह छद्म युद्ध का एक और मोर्चा खुलने जैसा होगा। जाहिर है जब तक केरल में कम्युनिस्ट सरकार है, तब तक तो इसकी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वह राष्ट्रविरोधी तत्वों के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाएगी और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। यह चिंताजनक है।

राष्ट्रीय संस्करण

सोमवार 2 अगस्त, 2021

दैनिक जागरण

बिजनेस

www.jagran.com

सरकारी बैंकों ने जुटाए 58,700 करोड़ रुपये

नई दिल्ली : सरकारी बैंकों ने बीते वित्त वर्ष के दौरान बाजार से रिकार्ड 58,700 करोड़ रुपये जुटाए। बैंकों ने अपना पूंजी आधार बढ़ाने के लिए यह राशि कर्ज और इक्विटी के रूप में जुटाई है। इसमें से सबसे ज्यादा 4,500 करोड़ रुपये की रकम बैंक आफ बड़ौदा ने क्यूआइपी से जुटाई। वहीं, पीएनबी ने 3,788 करोड़ और केनरा बैंक ने 2,000 करोड़ रुपये जुटाए। (प्रेट्र)

ईंधन के दामों की वजह से महंगाई बढ़ी है, जो जल्द काबू में आ जाएगी। ऐसे में आरबीआइ द्वारा मौद्रिक नीति में यथास्थिति बनाए रखने की उम्मीद है।

– उमेश रेवांकर, एमडी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस

एक नजर में

अब सीएसआर से किसी का भी टीकाकरण

नई दिल्ली : कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने स्पष्टीकरण में कहा है कि कंपनियों द्वारा किसी के भी टीकाकरण पर किया जाने वाला खर्च अब कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) में गिना जाएगा। मंत्रालय ने मार्च, 2020 में कहा था कि कंपनियों का कोविड से जुड़ा कोई भी खर्च सीएसआर गतिविधि का हिस्सा माना जाएगा। (प्रेट्र)

वोडाफोन टैक्स विवाद मामले की सुनवाई सितंबर में

नई दिल्ली : वोडाफोन मामले में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के फैसले को भारत सरकार द्वारा चुनौती देने वाली अपील को सिंगापुर की उच्च अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस मामले में भारत सरकार की अपील पर सितंबर में सुनवाई होगी। अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने वोडाफोन ग्रुप पर पिछली तारीख से 22,100 करोड़ रुपये की भारत सरकार की टैक्स मांग खारिज कर दी थी। (प्रेट्र)

चार महीनों में निवेशकों ने कमाए 31 लाख करोड़ रुपये

नई दिल्ली, प्रेट्र: कोरोना संकट के बीच भी चालू वित्त वर्ष में निवेशकों ने शेयर बाजार से भरपूर कमाई की है। वित्त वर्ष के महज चार महीनों में निवेशकों की संपत्ति 31,18,934.36 करोड़ रुपये बढ़ चुकी है। चालू वित्त वर्ष की शुरुआत यानी पहली अप्रैल से 30 जुलाई तक बीएसई का 30-शेयरों वाला सेंसेक्स 3,077.69 अंक यानी 6.21 फीसद चढ़ चुका है।

हालांकि निवेशकों के सकारात्मक रुख के दम पर चालू वित्त वर्ष में सेंसेक्स 16 जुलाई को इंट्रा-डे में 53,290.81 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। वहीं, 15 जुलाई को यह 53,158.85 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुआ।

चालू वित्त वर्ष की शुरुआत से 30 जुलाई को बाजार बंद होते वक्त तक बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 31,18,934.36 करोड़ रुपये बढ़कर 2,35,49,748.90 करोड़ रुपये पर जा पहुंचा। यह बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का अब तक का सर्वोच्च बाजार पूंजीकरण है।

दूसरी तरफ, पिछले पूरे वित्त वर्ष यानी पहली अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 90,82,057.95 करोड़ रुपये बढ़कर 2,04,30,814.54 करोड़ रुपये पर पहुंचा था। कोरोना संकट की सभी चुनौतियों को धता बताते हुए पिछले पूरे वित्त वर्ष के दौरान बीएसई-सेंसेक्स ने 20,040.66 अंकों यानी 68 फीसद की छलांग लगाई थी।

इक्विटी99 के सह-संस्थापक राहुल शर्मा ने कहा कि बाजार में पूंजी की उपलब्धता और तरलता शेयर बाजार के इस उछाल के प्रमुख कारण हैं। पिछले वर्ष की बिकवाली के बाद से शेयर बाजार का यह बेहतरीन प्रदर्शन है।

मार्च, 2020 के निचले स्तर के मुकाबले शेयर बाजार अभी दोगुना से अधिक के स्तर पर हैं। वहीं, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वीके विजयकुमार के अनुसार यह देखना महत्वपूर्ण है कि ईरान और मिस्र जैसे चुनिंदा बाजारों को छोड़कर इस वक्त दुनियाभर के बाजारों में उछाल दर्ज किया जा रहा है। इसकी मुख्य वजह यह है कि भारत समेत दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों ने बाजार में खूब पूंजी डाली है। इस समय ब्याज दरें ऐतिहासिक रूप से नीचे हैं और खुदरा निवेशकों की भागीदारी जबर्दस्त है।

जानकारों के मुताबिक कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान में तेजी से भी बाजारों का रुख सकारात्मक हुआ है।

छोटे स्टाक्स कर रहे बड़ा कमाल

नई दिल्ली, प्रेट्र : चालू वित्त वर्ष में अब तक छोटे स्टाक्स ने भी बड़ा कमाल किया है। पहली अप्रैल से 30 जुलाई तक स्मालकैप इंडेक्स 29.72 फीसद का उछाल ले चुका है। छोटे स्टाक्स के प्रदर्शन के अध्ययन से पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष में अब तक मिडकैप इंडेक्स में 2,905.91 अंकों यानी 14.39 फीसद की बढ़ोतरी देखी जा चुकी है। इसके मुकाबले 30-शेयरों वाले सेंसेक्स में 6.21 फीसद का उछाल देखा गया है। एलकेपी सिक्युरिटीज के रिसर्च प्रमुख एस. रंगनाथन ने कहा कि छोटे शेयरों में निवेशकों को वैराइटी और सेक्टर के कई विकल्प मिल जाते हैं। इस वजह से निवेशकों के लिए छोटे स्टाक्स निवेश के लिए पसंदीदा विकल्प बने हैं। बीते वित्त वर्ष के दौरान भी बीएसई का स्मालकैप इंडेक्स 114.89 फीसद और मिडकैप 90.93 फीसद बढ़ा था। हालांकि सेंसेक्स में बीते वित्त वर्ष के दौरान 68 फीसद की विकास दर रही थी।

शेयर समीक्षा

- अप्रैल से जुलाई तक छह फीसद से अधिक चढ़ चुका बीएसई सेंसेक्स, छोटे स्टाक्स और मजबूत
- 53,290.81 के सर्वकालिक उच्च स्तर को इंट्रा-डे में छूकर लौटा सेंसेक्स इन चार महीनों के दौरान

बड़े आंकड़े निर्धारित करेंगे बाजार की दिशा

नई दिल्ली, प्रेट्र : इस सप्ताह शेयर बाजारों की दिशा मुख्य रूप से बड़े आर्थिक आंकड़ों, प्रमुख कंपनियों के तिमाही नतीजों तथा आरबीआइ की समीक्षा बैठक के नतीजों पर निर्भर करेगी। जानकारों के अनुसार वैश्विक रुख तथा टीकाकरण से भी बाजार को दिशा मिलेगी। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे सप्ताह के दौरान आरबीआइ अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक करेगा। इसके साथ ही मैन्यूफैक्चरिंग व सर्विस सेक्टर के पीएमआइ आंकड़े भी आने हैं, जो बाजार को राह दिखाएंगे। इस सप्ताह एचडीएफसी, पीएनबी, अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनामिक जोन, बैंक आफ इंडिया, भारती एयरटेल, एसबीआइ और महिंद्रा एंड महिंद्रा के तिमाही नतीजे आने हैं। इन सभी नतीजों का असर शेयर बाजार पर दिखेगा। सैमको सिक्युरिटीज की इक्विटी रिसर्च प्रमुख निराली शाह ने कहा कि इन सबके अलावा आटो सेक्टर की मासिक बिक्री आंकड़ों पर भी निवेशकों की नजर रहेगी और सेक्टर व स्टाक-केंद्रित गतिविधियां दिखेंगी।

शीर्ष 10 में से छह कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 96,642 करोड़ रुपये घटा

नई दिल्ली, प्रेट्र : पिछले सप्ताह बीएसई की शीर्ष 10 में से छह कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में संयुक्त रूप से 96,642.51 करोड़ की गिरावट देखी गई। इनमें सबसे ज्यादा कमी आरआइएल के पूंजीकरण में हुई। टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, एचडीएफसी कोटक महिंद्रा बैंक का भी पूंजीकरण घटा। इन्फोसिस, आइसीआइसीआइ बैंक, एसबीआइ और बजाज फाइनेंस अपना पूंजीकरण बढ़ाने में कामयाब रहे। पिछले सप्ताह आरआइएल का बाजार पूंजीकरण 44,249.32 करोड़ गिरकर 12,90,330.25 करोड़ रह गया। टीसीएस के पूंजीकरण में 16,479.28 करोड़ की गिरावट आई और सप्ताह के आखिर में यह 11,71,674.52 करोड़ रह गया। कोटक महिंद्रा बैंक में 13,511.93 करोड़, एचडीएफसी बैंक में 8,653.09 करोड़ रुपये की गिरावट आई।

बीमा कंपनियों ने की कोरोना उत्पादों के प्रीमियम बढ़ाने की मांग

नई दिल्ली, प्रेट्र : बीमा कंपनियों के लिए कोरोना कवच और कोरोना रक्षक जैसे उत्पाद घाटे का सौदा साबित हो रहे हैं। ऐसे में कंपनियों ने बीमा नियामक इरडा से ऐसे उत्पादों के प्रीमियम बढ़ाने की इजाजत मांगी है। एक साधारण बीमा कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि ज्यादातर बीमा कंपनियों को कोरोना रक्षा और कोरोना कवच नीतियों घाटा हो रहा है। कंपनियों ने पिछले वर्ष जुलाई में इन नीतियों को बाजार में उतारा था।

अधिकारी ने कहा कि इस वर्ष जून तक के आंकड़ों के अनुसार अन्य देशों की तुलना में भारत में महामारी का प्रकोप बहुत अधिक था। ऐसे में अधिकांश बीमाकर्ताओं ने इरडा से इन दोनों नीतियों के मूल्य को फिर से तय करने का आग्रह किया है। उल्लेखनीय है कि कोरोना कवच के तहत 50,000 रुपये से पांच लाख रुपये तक और कोरोना रक्षक के तहत 50,000 रुपये से ढाई लाख रुपये तक का कोरोना बीमा लिया जा सकता है।

जीएसटी संग्रह फिर एक लाख करोड़ के ऊपर

1.16 लाख करोड़ रुपये रहा जुलाई में, 33 फीसद अधिक है पिछले वर्ष समान महीने के मुकाबले

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : देश की इकोनामी में उम्मीद से बेहतर सुधार के संकेत साफ दिख रहे हैं। रविवार को वित्त मंत्रालय ने बताया कि जुलाई में जीएसटी मद में 1.16 लाख करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। यह पिछले वर्ष जुलाई के मुकाबले 33 फीसद ज्यादा है। इस वर्ष जून में जीएसटी संग्रह की राशि 92,849 करोड़ की थी।

पिछले नौ महीनों के दौरान जून को छोड़कर मासिक जीएसटी संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा है जो बताता है कि कोरोना महामारी के बावजूद अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र मजबूत व गतिशील बने हुए हैं। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जीएसटी संग्रह की 1,16,393 करोड़ रुपये की राशि में से 22,197 करोड़ रुपये केंद्रीय जीएसटी के तौर पर, 28,541 करोड़ रुपये राज्य जीएसटी के तौर पर, 57,884 करोड़ रुपये इंटिग्रेटेड जीएसटी के तौर पर और 7,790 करोड़ रुपये सेस के तौर पर प्राप्त हुए हैं। इंटिग्रेटेड जीएसटी में 27,900 करोड़ रुपये की राशि आयातित उत्पादों से वसूला गया टैक्स है। इसमें 36 फीसद की वृद्धि हुई है। इससे पता चलता है कि कच्चे और तैयार उत्पादों का आयात बढ़ रहा है। घरेलू लेनदेन से होने वाले जीएसटी संग्रह में 32 फीसद की वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष मई में अधिकतर राज्यों में आंशिक या पूर्ण लाकडाउन लगा हुआ था और जून में भी कई राज्यों के कुछ हिस्सों में लाकडाउन था। इसका असर जून के संग्रह पर दिखाई दिया था। लेकिन जुलाई में अधिकांश आर्थिक गतिविधियों के लगभग सामान्य हो जाने की सूचना है। देश के बड़े औद्योगिक राज्यों जैसे हरियाणा में जीएसटी संग्रह में 53 फीसद, तमिलनाडु में 36, महाराष्ट्र में 51, गुजरात में 36, और तेलंगाना में 26 फीसद का इजाफा हुआ है।

जून में जीएसटी संग्रह के एक लाख करोड़ रुपये से नीचे रहने के बावजूद जुलाई के संग्रह से सकल राजस्व की स्थिति सरकार की उम्मीदों से बेहतर नजर आ रही है। इसमें पेट्रोलियम उत्पादों से आने वाले राजस्व की बड़ी भूमिका है। वित्त मंत्रालय को भरोसा है कि जीएसटी संग्रह यह तेजी बरकरार रहेगी। अगर सब कुछ सामान्य रहे तो त्योहारी सीजन के दौरान इस बार जीएसटी संग्रह रिकार्ड स्तर पर पहुंचा जा सकता है।

92,849 करोड़ रुपये की थी इस वर्ष जून में जीएसटी संग्रह की राशि

जीएसटी करदाताओं को मिली स्व-प्रमाणन सुविधा

नई दिल्ली, प्रेट्र : अब पांच करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले जीएसटी करदाता अपने वार्षिक रिटर्न का स्व-प्रमाणन कर सकेंगे। अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) के नए निर्देश के अनुसार उन्हें अपने रिटर्न को चार्टर्ड अकाउंटेंट से अनिवार्य आडिट सत्यापन कराने की जरूरत नहीं होगी। जीएसटी कानून के तहत वित्त वर्ष 2020-21 के लिए दो करोड़ रुपये तक के सालाना कारोबार वालों को छोड़कर अन्य सभी इकाइयों के लिए वार्षिक रिर्टन-जीएसटीआर-9/9ए दाखिल करना अनिवार्य है। इसके अलावा पांच करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले करदाताओं को फार्म जीएसटीआर-9सी के रूप में रिकंसीलिएशन स्टेटमेंट यानी समाधान विवरण जमा कराने की जरूरत होती थी। इस विवरण को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सत्यापित किया जाता है। सीबीआइसी ने एक अधिसूचना के जरिये जीएसटी नियमों में संशोधन किया है।

ट्रीटेड और प्योरिफाइड सीवेज वाटर के औद्योगिक उपयोग पर 18 फीसद जीएसटी

नई दिल्ली, प्रेट्र : अथारिटी फार एडवांस्ड रूलिंग (एएआर) ने कहा है कि ट्रीटेड व प्योरिफाइड सीवेज जल को जीएसटी अधिनियम के तहत 'जल' की कैटेगरी में रखा गया है। इसका मतलब यह है कि इसके औद्योगिक उपयोग की सूरत में कंपनी को 18 फीसद जीएसटी देना होगा। नागपुर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने एएआर की महाराष्ट्र पीठ में याचिका दायर कर पूछा था कि क्या महाराष्ट्र राज्य बिजली उत्पादन कंपनी लिमिटेड (महाजेनको) को आपूर्ति किया गया ट्रीटेड वाटर जीएसटी कानून के तहत टैक्स के दायरे में आता है।

बंजर भूमि पर खिलने लगे किसानों की कमाई के फूल

सुरेंद्र प्रसाद सिंह • नई दिल्ली

बढ़ती आबादी की खाद्य सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए सरकार की बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने की परियोजना परवान चढ़ने लगी है। लगभग तीन करोड़ हेक्टेयर भूमि को उर्वरा बनाने से वहां फसलें लहलहाने लगी हैं। वर्ष 2030 तक देश में बंजर, परती व अनुपजाऊ पड़ी जमीन में से 5.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि को खेती लायक बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ ही देश में प्रति व्यक्ति खेती वाली जमीन डेढ़ गुना हो जाएगी।

बंजर से उपजाऊ बनाने की इस योजना से 35 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। योजना की पूर्ण सफलता के बाद खाद्यान्न की पैदावार दोगुना हो जाने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप देश की बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने को लेकर ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग ने परियोजना को रफ्तार दी है। देश की बंजर व परती जमीन को चिन्हित कर 8,213 क्लस्टर में बांट दिया गया है। प्रत्येक क्लस्टर में औसतन 5,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए पांच करोड़ रुपये आवंटन का प्रविधान है।

इस बारे में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि खेती योग्य भूमि संसाधन को बढ़ाने की इस परियोजना से एक लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित हो रहा है। स्थानीय स्तर पर जहां लोगों को काम मिलता है, वहीं किसानों की आमदनी में 25 फीसद की बढ़त दर्ज की गई है। इस वर्ष सितंबर तक कुल 2.9 करोड़ हेक्टेयर जमीन उपजाऊ बन जाएगी।

2.9 करोड़ हेक्टेयर बंजर भूमि बनाई खेती योग्य

राष्ट्रीय फलक

न्यूज गैलरी

चार लाख का इनामी माओवादी सुरजन ने किया आत्मसमर्पण

संबलपुर: करीब दस वर्षों से प्रतिबंधित भाकपा माओवादी में सक्रिय ऐतु कोरसा उर्फ सुरजन उर्फ अमित ने को बलांगीर जिला पुलिस कार्यालय में आत्मसमर्पण किया। सुरजन पर चार लाख रुपये का इनाम घोषित था। (जासं)

कैलिफोर्निया से मंगवाते थे गांजा, गिरोह का भंडाफोड़

कोलकाता : एनसीबी टीम ने अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर से विश्व के सबसे महंगे गांजे की कोलकाता में तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। कोलकाता एयरपोर्ट के पार्सल यूनिट से 42 पार्सल में छिपाकर लाया गया 20 किलोग्राम गांजा जब्त किया। इसमें श्रद्धा सुराणा, तरीना भटनागर और करण कुमार गुप्ता है। (राब्यू)

वाट्सएप ग्रुप पर हो रही थी हथियारों की खरीद-फरोख्त

कोलकाता : इंटरनेट मीडिया को माध्यम बनाकर कोराबार करने और सफल होने की कई कहानियां हैं, लेकिन कोलकाता में रविवार को पुलिस ने वाट्सएप के जरिये हथियार बेचने के मामले में किशन जायसवारा को गिरफ्तार किया है। (राब्यू)

उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के सड़क दुर्घटना में नहीं था सेंगर का हाथ

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

चर्चित उन्नाव कांड मामले में दुष्कर्म पीड़िता के स्वजन के साथ वर्ष 2019 में हुई सड़क दुर्घटना मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का हाथ नहीं होने की केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) की जांच को तीस हजारी कोर्ट ने बरकरार रखा है। मामले में किसी भी गड़बड़ी से इन्कार करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने कहा कि शिकायतकर्ता पक्ष की आपत्तियां एक रोमांचकारी कहानी की तरह लगती हैं जोकि अनुमानों पर आधारित थी।

अदालत ने कहा कि सीबीआइ की जांच की निष्ठा, सटीकता एवं ईमानदारी पर संदेह का आधार नहीं है। विशेष तौर पर एजेंसी ने जांच में निष्कर्ष निकाला है कि आपराधिक साजिश की धारा के तहत कुलदीप सेंगर, ट्रक चालक, क्लीनर या मालिक के खिलाफ दर्ज मामले में कोई सुबूत नहीं है। 31 जुलाई को दिए आदेश में अदालत ने कहा कि मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सीबीआइ द्वारा आरोप पत्र में निकाले गए निष्कर्षों के तहत आरोपितों के खिलाफ कोई मामला नहीं है जिस पर संज्ञान लेकर भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास), 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोष तय करने की कार्रवाई शुरू की जा सके।

हालांकि, अदालत ने सेंगर और उसके सहयोगियों के खिलाफ आपराधिक धमकी के आरोप तय करने के साथ ही लापरवाही से मौत का कारण बनने और मानव जीवन को खतरे में डालने के लिए ट्रक चालक के खिलाफ भी आरोप तय किए।

वर्ष 2019 में चाची व अधिवक्ता के साथ जा रही पीड़िता की कार में रायबरेली में एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी थी। इस घटना में पीड़िता की चाची की मौत हो गई थी, जबकि अधिवक्ता के साथ पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ हत्या समेत अन्य धारा में मामला दर्ज किया गया था। वर्ष 2017 में पीड़िता से दुष्कर्म मामले में तीस हजारी अदालत ने सेंगर समेत अन्य दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। चार मार्च 2020 को अदालत ने सेंगर, उसके भाई और पांच अन्य लोगों को भी पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में मौत के लिए दोषी ठहराते हुए दस साल की सजा सुनाई थी।

पीलीभीत में तस्कर बताकर वसूली, सिपाहियों पर मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, पीलीभीत : उप्र के पीलीभीत में ढाबा मालिक को तस्कर बताकर जेल भेजने की धमकी देने व एक लाख, 10 हजार रुपये घूस लेने वाले सिपाहियों को इस बार खूब सबक मिला। चारों पर शनिवार देर रात भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोपों की पुष्टि में एक पुराने मामले की फोन रिकार्डिंग भी अहम साबित हुई, जिसमें सिपाही घूस मांगते सुनाई दे रहे थे।

पीड़ित अहमद हुसैन का खुटार रोड पर वीरजी नाम से ढाबा है, जिसे भाई हामिद हुसैन चलाते हैं। 14 जुलाई को सिपाही सुरेंद्र सिंह पटेल, विक्की व दो अन्य पुलिसकर्मी वहां पहुंचे। ढाबे पर अहमद हुसैन नहीं मिले तो फोन कर बुला लिया। बातचीत के दौरान ही सिपाहियों ने प्लास्टिक के थैले से दो किलो डोडा (मादक पदार्थ) निकालते हुए कहा कि यह तुम्हारी बाइक से बरामद हुआ है। अहमद व हामिद हुसैन इससे इन्कार करते रहे, इसके बावजूद सिपाही उन्हें कोतवाली ले गए। आरोप है कि मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की धमकी देते हुए दो लाख रुपये मांगे। बाद में एक लाख दस हजार रुपये लेकर छोड़ दिया। 23 जुलाई को अहमद हुसैन ने एसपी किरीट कुमार राठौर को पूरा मामला बताया।

सभ्य समाज में अपराधी को भी मिलना चाहिए सुधार का मौका

नई दिल्ली, प्रेट्र : सभ्य समाज की जिम्मेदारी होती है कि वह अपराधी को अपने कृत्यों में सुधार का हर संभव मौका दे। यह बात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यूयू ललित ने एक साल चलने वाले लिए सभी के लिए न्याय कार्यक्रम की लांचिंग के मौके पर कही। इस कार्यक्रम का आयोजन हरियाणा न्यायिक सेवा अधिकरण ने गुरुग्राम में किया था।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा, विधि सम्मत समाज में अपराधी को उसके किए अपराध के लिए गिरफ्तार कर दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन उस अपराधी को उतने ही मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं जितने सामान्य व्यक्ति को। सभ्य समाज की जिम्मेदारी है कि वह अपराधी को सुधार का हर संभव मौका दे। जस्टिस ललित ने कहा, बीते डेढ़ साल से जब संपूर्ण मानवता कोविड-19 महामारी से जूझ रही है, ऐसे में वर्चुअल प्लेटफार्म कई तरह की समस्याओं का समाधान बनकर उभरा है। इसके चलते महामारी के दौर में सभी तरह का संवाद, मनोरंजन और अन्य गतिविधियां वर्चुअल माध्यम से पूरी की गईं। यहां तक कि अदालतें भी अपना काम वर्चुअल प्लेटफार्म पर कर रही हैं। इस स्थिति ने हमें नई तरह से सोचने के लिए तैयार किया। जस्टिस ललित ने 22 जिला न्यायिक सेवा अधिकरण के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा का भी उद्घाटन किया। इससे अधिवक्ता और मुवक्किल के बीच संपर्क में सुविधा होगी। उन्होंने 18 जिलों के लिए किड्स जोन का भी उद्घाटन किया। इसमें उन युवा जोड़ों के बच्चों को सुविधाएं मिलेंगी जिनके पारिवारिक मामले काउंसलिंग के दौर से गुजर रहे हैं।

केदारपुरी के भैरवनाथ मंदिर की 103 घंटियां गौरीकुंड में बरामद

जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग

- घोड़े पर केदारनाथ से गौरीकुंड लाई जा रही थी तांबे व कांसे की ये छोटी-बड़ी घंटियां

गौरीकुंड पुलिस ने केदारनाथ से घोड़े पर लादकर लाई जा रही तांबे व कांसे की 103 छोटी-बड़ी घंटियां कब्जे में ली हैं। बताया गया कि केदारपुरी स्थित भैरवनाथ मंदिर से ये घंटियां लाई जा रही थीं। पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग आयुष अग्रवाल ने बताया कि इस संबंध में घोड़ा संचालक से जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं, पंच पंडा रुद्रपुर श्री केदारनाथ के सचिव पंकज शुक्ला ने पुलिस से इस मामले में जांच की मांग की है।

पुलिस ने बताया कि केदारनाथ से घोड़े पर लादकर घंटियां लाने का पता तब चला, जब स्थानीय व्यक्तियों ने गड़बड़ी की आशंका होने पर घोड़े को रोका। पूछताछ में घोड़ा संचालक ने पुलिस को बताया कि केदारपुरी स्थित भैरवनाथ मंदिर के निकट रहने वाले शनि महाराज नाम के साधू ने यह घंटियां भेजी हैं। शनि महाराज कई वर्षों से केदारनाथ में रह रहे हैं।

वहीं, पंच पंडा रुद्रपुर श्री केदारनाथ के सचिव पंकज शुक्ला ने पुलिस को दिए पत्र में कहा कि साधु भक्तों की चढ़ाई इन घंटियों को अपनी कुटिया में रखते थे। उन्हें अंदेशा है कि पूर्व में भी ऐसा किया गया होगा। कहा कि बिना सूचना के घंटियों को गौरीकुंड भेजा जाना गंभीर मामला है। इसमें चोरी की आशंका से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है।

खेल जागरण

कश्मीर प्रीमियर लीग को लेकर बोला बीसीसीआइ, राष्ट्र हित में समझौता नहीं

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) ने चार अगस्त से शुरू होने वाली कश्मीर प्रीमियर लीग को लेकर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हर्शल गिब्स के द्वारा लगाए गए आरोपों पर जवाब दिया है। बीसीसीआइ ने राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए यह साफ कर दिया है कि दुनिया का कोई भी खिलाड़ी अगर पाकिस्तान के हिस्से वाले कश्मीर में आयोजित की जाने वाली कश्मीर प्रीमियर लीग में खेलेगा तो उसे आइपीएल में खेलने से हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। साथ ही वह भविष्य में भारत में क्रिकेट की किसी भी गतिविधि का हिस्सा नहीं बनेगा।

बीसीसीआइ ने साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को भी साफ-साफ कह दिया है कि उसे इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। बीसीसीआइ ने सभी देशों के क्रिकेट बोर्ड को अनौपचारिक रूप से यह साफ तौर पर बोल दिया है कि अगर उनके खिलाड़ी पाकिस्तान की विवादित लीग में खेलते हुए नजर आए तो वह उनके साथ सभी व्यवसायिक संबंधों को खत्म कर देगा। उसके बाद वे खिलाड़ी भारत में किसी भी क्रिकेट गतिविधि का हिस्सा नहीं बन पाएंगे।

बीसीसीआइ ने यह भी कहा कि अगर दूसरे बोर्ड का कोई भी खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग में खेलता है तो इससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कश्मीर को लेकर बीसीसीआइ की सोच एकदम साफ है। राष्ट्र हित के मामले में बीसीसीआइ कोई भी समझौता नहीं करेगा। कश्मीर के मामले में हम भारत सरकार की लाइन पर चलते हुए ही आगे काम करेंगे। बीसीसीआइ के एक अधिकारी ने तो यहां तक कहा कि गिब्स पहले ही मैच फिक्सिंग मामले में सीबीआइ जांच में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में उनके बयान की सत्यता को पुष्टि नहीं की जा सकती। वहीं, बीसीसीआइ ने पीसीबी से कहा कि उसे यह समझना चाहिए कि भले ही गिब्स के बयान को सच मान लिया जाए, लेकिन बीसीसीआइ को पता है कि भारतीय क्रिकेट पारिस्थितिकी तंत्र के अपने अधिकारों के भीतर उसे क्या करना है।

यह मामला उस वक्त सामने आया जब गिब्स ने बीसीसीआइ पर यह आरोप लगाया था कि वह अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत क्रिकेटरों को कश्मीर प्रीमियर लीग में खेलने से रोक रहे हैं।

विवाद

- गिब्स के आरोपों पर भारतीय बोर्ड ने किया रुख साफ
- पीसीबी से भी कहा, इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए

भारत के खिलाफ सीरीज से हमारे स्तर का पता चलेगा : जैक लीच

क्रिकेट डायरी

लंदन, प्रेट्र : इंग्लैंड के स्पिनर जैक लीच का मानना है कि भारत के खिलाफ आगामी पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में उनकी टीम का प्रदर्शन यह निर्धारित करेगा कि वह अपने खेल के विकास के मामले में किस स्तर पर पहुंचे हैं।

लीच इस साल की शुरुआत में भारत में टेस्ट सीरीज में खेल चुके हैं और वह आगामी घरेलू सीरीज में व्यक्तिगत रूप से अच्छा प्रदर्शन करने को लेकर आश्वस्त हैं। बायें हाथ के इस स्पिनर ने फरवरी-मार्च में इंग्लैंड के भारत दौरे पर खेली गई चार मैचों की सीरीज में 18 विकेट झटके थे। लीच ने कहा कि भारत में उनकी सफलता ने उन्हें बुधवार से नाटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में शुरू होने वाली आगामी सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उनका आत्मविश्वास बढ़ाया है। लीच ने कहा, 'मुझे विश्वास है कि मैं इन खिलाड़ियों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूं। अगर विकेट बेहतर है तो यह सिर्फ अपने कौशल के मुताबिक थोड़ा ढलने के बारे में है। मुझे इंग्लैंड में स्पिन गेंदबाजी करने में मजा आता है। विकेट आमतौर पर इस समय काफी सूखे होते हैं और निश्चित रूप से इसमें स्पिनरों की भूमिका होगी। भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज से हमें पता चलेगा कि हमारा स्तर क्या है।' लीच इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक हैं, ताकि वह एशेज सीरीज के लिए टीम में अपनी जगह पक्की कर सकें। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि मैं अब भी नियमित तौर पर अच्छा प्रदर्शन कर टीम में जगह पक्की करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे यह सुनिश्चित करना कि मेरा खेल अच्छा रहे, ताकि मैं लगातार बेहतर प्रदर्शन करूं और टीम में जगह बरकरार रखूं।'

अफगानिस्तान के मुख्य चयनकर्ता ने त्यागपत्र दिया

कराची, प्रेट्र : अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता असादुल्लाह खान ने बोर्ड में गैर क्रिकेटरों के हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है।

अफगानिस्तान को अगले महीने श्रीलंका में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी पहली द्विपक्षीय वनडे सीरीज खेलनी है और खान ने कहा कि इसके लिए 17 सदस्यीय टीम उनकी मंजूरी के बिना ही घोषित कर दी गई। रिपोर्टों के अनुसार अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) ने खान का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है। एसीबी ने हाल में घोषणा की थी कि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में हशमतुल्लाह शाहिदी टीम की अगुआई करेंगे। टीम में पांच नए खिलाड़ियों को भी जगह दी गई थी। खान ने अपने त्यागपत्र में कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए टीम घोषित करने को लेकर उन्हें अंधेरे में रखा गया। उन्होंने बोर्ड में गैर क्रिकेटरों के बहुत अधिक हस्तक्षेप का भी जिक्र किया, जिनको खिलाड़ियों और चयन को लेकर कोई ज्ञान नहीं है। उन्होंने इसको अपने इस्तीफे का मुख्य कारण बताया।

भारत की कुछ आर्थिक नीतियों से अमेरिका चिंतित

- ब्लिंकन ने ई-कामर्स नीति को लेकर अपने देश की आपत्तियों को दर्ज कराया
- अमेरिकी निवेश की राह की अड़चनों को हटाने का भी किया आग्रह

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पिछले हफ्ते भारत के दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की यात्रा के दौरान अफगानिस्तान, हिंद प्रशांत, कोरोना महामारी से जुड़े मुद्दों पर हुई बातचीत ही मीडिया में सुर्खियों में छाई रही। लेकिन ब्लिंकन और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच हुई वार्ता में दोनों देशों के मौजूदा कारोबारी रिश्तों को लेकर कुछ तल्ख मुद्दे भी उठे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत सरकार की तरफ हाल ही में प्रस्तावित ई-कामर्स नीति को लेकर अपने देश की आपत्तियों को दर्ज कराया। भारत की तरफ से उन्हें आश्वस्त किया गया है कि कारोबार व निवेश से जुड़े मुद्दों का आगामी ट्रेड समझौते में समाधान निकाला जाएगा। हालांकि, दोनों देशों के बीच ट्रेड समझौते को लेकर वार्ता शुरू करने की तिथि अभी तय नहीं हुई है।

ब्लिंकन ने संयुक्त प्रेस वार्ता में ही अपने देश की बात सामने रख दी थी। उन्होंने कहा था कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद अपने कारोबारी रिश्तों को आगे बढ़ाने को लेकर भी सोचना होगा। हमें द्विपक्षीय निवेश व कारोबार को और बढ़ाने की राह में आने वाली अड़चनों को दूर करने पर लगातार काम करना होगा। इस बारे में हमारी बातचीत हुई है।

एंटनी ब्लिंकन। फाइल/इंटरनेट मीडिया

अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से सार्वजनिक तौर पर यह मुद्दा उठाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय विदेश मंत्री की तरफ से जारी बयान में द्विपक्षीय कारोबारी रिश्तों पर पूरी तरह से चुप्पी थी। बाद में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से इस बारे में साफ तौर पर प्रश्न पूछने पर भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला।

ब्लिंकन के भारत आने से पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2021 के निवेश माहौल पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें भारत में निवेश के माहौल को बहुत ही चुनौतीपूर्ण बताया गया था। इसमें मोदी सरकार से यह आग्रह भी किया गया था कि वह निवेश की राह की ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर होने वाली अड़चनों को खत्म करे। सूत्रों की मानें तो अमेरिका को जून, 2021 में भारत सरकार की तरफ से प्रस्तावित ई-कामर्स नीतियों को लेकर काफी परेशानी हो रही है।

वैसे भी देखा जाए तो बाइडन के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा और कूटनीतिक स्तर पर लगातार विमर्श का दौर चल रहा है। लेकिन कारोबारी रिश्तों को वार्ता में खास अहमियत नहीं मिल रही है। अक्टूबर 2020 तक दोनों देशों की सरकारों के बीच एक कारोबारी समझौतों को लेकर लगातार बातें होती रही थीं और एक समय यहां तक कहा गया था कि एक मिनी ट्रेड डील पर जल्द ही दोनों देश हस्ताक्षर करेंगे।

20 अक्टूबर को चीन के खिलाफ विरोध दिवस मनाएंगे तिब्बती

ईटानगर, प्रेट्र : भारत-तिब्बत सहयोग मंच (आइटीसीएफ) ने 1962 में अरुणाचल प्रदेश व 2020 में लद्दाख में चीन की आक्रामकता के खिलाफ 20 अक्टूबर को विरोध दिवस मनाने का फैसला किया है। यह भारतीयों का संगठन है, जो तिब्बत की आजादी का समर्थन करता है।

आइटीसीएफ के पदाधिकारी रिंचेन खांडू ख्रिमे ने गुवाहाटी में बैठक के दौरान कहा, इस आयोजन में धर्मशाला स्थित केंद्रीय तिब्बत प्रशासन के नवनियुक्त अध्यक्ष (सिक्योंग) पेंपा शेरिंग भी शामिल हो सकते हैं। शेरिंग दुनियाभर के निर्वासित तिब्बतियों के सर्वोच्च राजनेता हैं। ख्रिमे ने कहा, 'भारत व चीन के संबंधों में प्रगति तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि तिब्बत मुद्दे का समाधान न हो जाए और 14वें दलाई लामा ल्हासा स्थित पोटाला पैलेस में फिर से ससम्मान स्थापित न कर दिए जाएं।' उन्होंने कहा कि आइटीसीएफ व भारत-तिब्बत समर्थक 20 अक्टूबर को ताइवान में भी समारोह आयोजित करेंगे।

गुलाम कश्मीर में कानून संशोधन की फिराक में पाकिस्तान

- गिलगिट-बाल्टिस्तान को देना चाहता है अस्थायी प्रांत का दर्जा
- भारत की चेतावनी बाद भी तैयार किया 26 वां संविधान संशोधन विधेयक

इस्लामाबाद, प्रेट्र : गुलाम कश्मीर को लेकर भारत की सख्त चेतावनी के बाद भी पाकिस्तान गिलगिट-बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत का दर्जा देने पर आमादा है। इसके लिए, उसने एक कानूनी मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। यह जानकारी पाकिस्तानी मीडिया में दी गई है।

भारत ने पहले ही पाकिस्तान को साफ तौर पर बेहद सख्त लहजे में चेतावनी दे दी है कि जम्मू-कश्मीर का पूरा क्षेत्र और लद्दाख भारत का पूरी तरह कानूनी और अविभाज्य अंग है। इसमें गिलगिट-बाल्टिस्तान का भी क्षेत्र है। पाकिस्तान और उसकी न्याय पालिका का अवैध रूप से और जबरन कब्जे वाले क्षेत्र पर कोई अधिकार नहीं है।

डान अखबार के मुताबिक, कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित इस कानून में सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय को समाप्त किया जा सकता है। इस क्षेत्र के चुनाव आयोग का पाकिस्तान के चुनाव आयोग में विलय हो सकता है। गिलगिट-बाल्टिस्तान के इस कानून को 26 वां संविधान संशोधन विधेयक नाम दिया गया है। इसका मसौदा तैयार कर प्रधानमंत्री इमरान खान को भेज दिया गया है।

इमरान खान। फाइल/इंटरनेट मीडिया

उल्लेखनीय है कि चीन के कर्ज में दबा पाकिस्तान गिलगिट-बाल्टिस्तान क्षेत्र में भी बलूचिस्तान की तरह चीन की परियोजनाओं के अनुकूल कानून में परिवर्तन करना चाहता है।

इससे पूर्व पाकिस्तान का दमनकारी चेहरा यहां चुनाव कराने में भी सामने आ चुका है, जब हाल में इमरान सरकार ने चुनाव के दौरान अराजकता और हिंसा कराई। सैकड़ों नागरिक इस हिंसा का शिकार हुए। इसको लेकर विपक्षी नेताओं के साथ ही जनता ने सेना के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विरोधी नेताओं में से कुछ ने तो भारत से सहायता लेने की भी इमरान सरकार को धमकी दे दी।

नाजी शिविर के सौ साल के पूर्व गार्ड के खिलाफ होगी सुनवाई

फ्रैंकफर्ट, रायटर : द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के 76 साल बाद जर्मनी में बर्लिन के पास स्थित नाजियों के सचेनस्यूजन बंदी शिविर में तैनात रहे पूर्व गार्ड के खिलाफ सुनवाई शुरू होगी। इस पूर्व गार्ड की आयु अब सौ साल है।

जर्मनी की साप्ताहिक पत्रिका वेल्ट एम सोनटैग की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूरुपिन की जिला अदालत ने आरोप लगाया है कि इस पूर्व गार्ड ने इस नाजी कैंप में 3500 हत्या के मामलों में सहयोग किया था। इन मामलों की सुनवाई अक्टूबर में शुरू होगी। अदालत के प्रवक्ता ने बताया कि आरोपित को अपने बचाव के लिए सुनवाई के दौरान दो से ढाई महीने का वक्त मिलेगा।

जर्मनी के मीडिया के कानूनी प्रविधानों के अनुसार आरोपित का नाम उजागर नहीं किया गया है। आरोपित सचेनस्यूजन नाजी शिविर में वर्ष 1942 से लेकर 1945 तक तैनात था। जर्मन मीडिया के मुताबिक द्वितीय विश्व युद्ध के समय इस शिविर में दो लाख लोगों को कैद करके रखा गया था। इनमें से 20 हजार लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी।

हालांकि नाजी अपराधियों की कुल संख्या अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन अभियोजन अभी भी आरोपितों के खिलाफ न्याय करने की बात कह रहा है। 2011 में एक अहम फैसला आया था जिसमें कहा गया था कि किसी नाजी कैंप में गार्ड के रूप में काम करने को ही अपराध माना जाएगा अगर किसी अपराध के कोई स्पष्ट सुबूत नहीं हैं।

अफगान सेना ने मारे 254 तालिबान आतंकी

अफगानिस्तान में जंग ▶ आतंकवादियों ने कंधार एयरपोर्ट पर किया राकेट हमला, उड़ानें बंद

हवाई हमलों को रोकने के लिए तालिबान का निशाना बना एयरपोर्ट

काबुल, रायटर : अफगानिस्तान के कई सूबों में जंग तेज हो गई है। आतंकियों के हमलों के बीच अफगान सेना ने पिछले 24 घंटे में कई प्रांतों में तालिबान के ठिकानों पर हमले किए और 254 आतंकियों को ढेर कर दिया। इधर आतंकियों ने कंधार एयरपोर्ट पर राकेट हमला किया। यहां पर तीन राकेट दागे गए। एयरपोर्ट पर हमले के बाद वहां से उड़ाने बंद कर दी गई हैं।

अफगान रक्षा मंत्रालय के अनुसार, सेना ने जंग को तेज करते हुए गजनी, कंधार, हेरात, काबुल, बल्ख और कपिसा आदि राज्यों में आतंकियों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू कर दिया है। सेना ने एक दिन में ही 254 आतंकियों को मार गिराया। 97 आतंकी घायल हुए हैं। आतंकियों के गोला-बारूद को भी नष्ट कर दिया है। इधर अफगान सेना कंधार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए कड़ा संघर्ष कर रही है। आतंकियों ने सेना पर दबाव बनाने के लिए कंधार एयर पोर्ट पर राकेट हमले किए। हमले के बाद सभी उड़ानें बंद कर दी गई हैं।

तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि अफगान सेना के विमान तालिबान पर हमले के लिए लगातार कंधार से ही उड़ान भर रहे थे, इसीलिए एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। अफगान सरकार के अधिकारी ने बताया कि हमले में रनवे का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। इन हमलों में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। यहां से पांच प्रांतों में तालिबान के ठिकानों पर हवाई हमले किए जा रहे हैं। आइएएनएस के अनुसार, जौजान प्रांत में हवाई हमलों में 37 आतंकी मारे गए। एएनआइ के अनुसार, कपिसा प्रांत में निजरब जिले में तालिबान आतंकियों ने चार नागरिकों की हत्या कर दी।

तालिबान से छिड़ी लड़ाई के बीच हेरात प्रांत के एंजिल जिले में तैनात अफगान नेशनल आर्मी का कमांडो। एएफपी

छह महत्वपूर्ण चौकियों पर दो महीनों से टैक्स वसूल रहे हैं तालिबान आतंकी

एएनआइ के अनुसार तालिबान ने छह ऐसी सीमावर्ती चौकियों पर कब्जा कर लिया है, जिनसे अफगान सरकार का राजस्व घट गया है। अफगान सरकार के वित्त मंत्रालय ने कहा है कि पिछले दो महीनों से टैक्स वसूली किए जाने वाली इन सीमावर्ती चौकियों पर तालिबान का कब्जा है। तालिबान के द्वारा ही अब यहां टैक्स वसूला जा रहा है।

शरणार्थियों के मामले में पाक ने हाथ खड़े किए

आइएएनएस के अनुसार पाकिस्तान ने अफगान युद्ध के कारण उसकी सीमा में भाग कर आने वाले नागरिकों को शरण देने से इन्कार कर दिया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) मोईद युसूफ ने कहा है कि पाक अब और ज्यादा अफगान नागरिकों को शरण नहीं दे सकता है। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को अफगानिस्तान की सीमा में ही शरणार्थी कैंप खोलने चाहिए। पाक एनएसए ने यह बात अमेरिका में पत्रकार वार्ता के दौरान कही।

हेरात के यूएन मिशन परिसर में आतंकियों के हमले की हो जांच

आइएएनएस के अनुसार, अफगानिस्तान स्थित संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने हेरात शहर के अपने परिसर में आतंकी हमले की जांच की मांग की है। इस हमले में एक गार्ड की मौत हो गई थी। यह हमला तालिबान आतंकियों ने उस समय किया, जब वे हेरात में कब्जे के लिए घुस रहे थे।

तालिबान अपने आलोचकों को बना रहा है निशाना

आइएएनएस के अनुसार ह्यूमन राइट्स वाच ने कहा है कि तालिबान अपने आलोचकों को निशाना बना रहा है। नागरिकों की हत्या की जा रही है। यहां जांच कर रहे अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आइसीसी) को ऐसे मामलों को देखना चाहिए।

अमेरिका ने अफगानिस्तान से हवाई निर्यात को बढ़ावा देने की योजना बनाई

एएनआइ के अनुसार, अमेरिका ने अफगानिस्तान से हवाई निर्यात बढ़ाने के लिए चार साल की एक योजना बनाई है। इसके अनुसार यहां के काबुल, कंधार, मजार-ए-शरीफ और जलालाबाद एयरपोर्ट से हवाई निर्यात को बढ़ावा जाएगा। इससे बीस हजार नौकरियों के साथ निर्यात में तीस फीसद का इजाफा होगा।

नेपाल में मंत्रिमंडल विस्तार आज

काठमांडू, प्रेट्र : नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और सीपीएन-माओइस्ट सेंटर के प्रमुख पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' सोमवार को मंत्रिमंडल का विस्तार करने पर सहमत हो गए हैं।

माई रिपब्लिका अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया, 'सत्तारूढ़ पार्टियां अपने-अपने नेताओं को सरकार में शामिल करने के लिए होमवर्क कर रही हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार सोमवार को होगा।' अखबार के मुताबिक, पीएम के बालुवतार स्थित आवास में दोनों नेताओं की बैठक हुई, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार में सीपीएन-यूएमएल नेता माधव कुमार नेपाल की पार्टी के सदस्यों को सरकार में यथासंभव शामिल करने पर सहमति बनी। इस समय देउबा सरकार में चार कैबिनेट और एक राज्य मंत्री है। हालांकि, सीपीएन-यूएमएल नेता माधव नेपाल पार्टी के भीतर चल रहे संघर्ष के चलते इस समय सरकार में शामिल होने को लेकर अनिच्छुक हैं। अखबार ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में विस्तार के बाद नेपाली कांग्रेस के आठ मंत्री, माओइस्ट सेंटर और जनता समाजवादी पार्टी के सात-सात मंत्री मंत्रिमंडल में होंगे। सूत्रों के हवाले से अखबार ने कहा कि बाकी बचे तीन मंत्री पद माधव कुमार नेपाल के करीबियों को बतौर निर्दलीय मिलेंगे। नेपाली संविधान के अनुसार, अधिकतम 25 कैबिनेट मंत्री ही हो सकते हैं। नेपाली कांग्रेस नेता पुष्पा भूसल, नारायण खड़का, मान बहादुर बोके, किशोर सिंह राठौड़ और बहादुर सिंह लामा के मंत्रिमंडल में शामिल होने की उम्मीद है।

अमेरिका में कोरोना संकट गहराया, फ्लोरिडा में हालात बेकाबू

- टोक्यो ओलिंपिक से जुड़े 259 लोग अब तक कोरोना का शिकार
- डेल्टा वैरिएंट ने बढ़ाई चीन की चिंता, तेजी से बढ़ रहे मरीज

आरलैंडो, एपी : अमेरिका में डेल्टा वैरिएंट के कारण मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। फ्लोरिडा राज्य में हालात बेकाबू हो रहे हैं।

राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार एक सप्ताह में संक्रमित मरीजों की संख्या में पचास फीसद बढ़ोतरी हुई है। अमेरिका के हर पांच मरीजों में एक मरीज फ्लोरिडा का है। मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण यहां मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। फ्लोरिडा में एक सप्ताह में 409 लोगों की मौत हो गई। यह संख्या 29 मार्च के बाद सबसे ज्यादा है। इसी तरह 7 जनवरी को यहां संक्रमण के 19334 केस आए थे। अब पिछले 24 घंटे में 21683 नए मामले मिले हैं। पूरे अमेरिका में पिछले 24 घंटे में रिकार्ड 101171 मरीज मिले हैं। 30 जुलाई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या है।

इधर रायटर के अनुसार, जापान की राजधानी टोक्यो में चल रहे ओलिंपिक खेलों के दौरान कोरोना संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। यहां संक्रमित मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है। ओलिंपिक से जुड़े लोगों में भी संक्रमण हो रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान खेल से जुड़े 18 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इनमें एक एथलीट भी शामिल है। अब तक खेलों से जुड़े 259 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। टोक्यो में रविवार को 3058 कोरोना के नए मामले मिले हैं।

वहीं, चीन में जुलाई माह में 328 नए मरीज मिले हैं। ये सभी मामले स्थानीय स्तर पर संक्रमण के हैं। पिछले पांच महीने में इतने मरीज चीन में नहीं मिले थे।

चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सभी मरीज डेल्टा वैरिएंट के हैं। एएनआइ के अनुसार, मध्य चीन के झांगजियाजी शहर में मरीजों के बढ़ने पर विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। झांगजियाजी हुनान प्रांत का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है।

आस्ट्रेलिया में लाकडाउन : कोरोना के मामलों में वृद्धि होने पर आस्ट्रेलिया में सख्त लाकडाउन किया गया है। देश के तीसरे सबसे बड़े शहर ब्रिस्बेन में लाकडाउन की वजह से सुनसान पड़ी सड़क। क्वींसलैंड राज्य के कई अन्य शहरों में भी कोरोना का प्रसार रोकने के लिए सख्त पाबंदियां लगाई गई है। एएफपी

तुर्की : एएनआइ के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान 22 हजार से ज्यादा लोग मिले हैं।

थाईलैंड : आइएएनएस के अनुसार, हर रोज 18 हजार से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। यहां कई स्थानों पर लाकडाउन और पाबंदी लगी हुई है।

ब्राजील : एएनआइ के अनुसार, पिछले 24 घंटे के दौरान 910 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई।

पाकिस्तान : प्रेट्र के अनुसार, तीन महीने में सबसे ज्यादा 5 हजार मरीज मिले हैं।

पीएम ने मांगी माफी

'डान रेड्स' के लिए न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने प्रशांत द्वीप समूह के लोगों से करीब 54 साल बाद माफी मांगी है। आकलैंड में स्थित टाउनहाल में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि 'डान रेड्स के लिए सरकार को दुख, पछतावा और खेद है'। दरअसल, देश में कठोर आव्रजन नीतियों पर अमल करते हुए वर्ष 1974 और 1976 के बीच इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के परिवारों को लक्ष्य बनाकर छापेमारी की गई। कहा गया कि उन्हें नस्लीय आधार पर आव्रजन अधिकारियों ने निशाना बनाया। इस कार्रवाई को डान रेड्स कहा जाता है। पीएम ने कहा कि यह ऐतिहासिक भूल थी और आव्रजन कानून भेदभावपूर्ण थे। एएफपी

ट्रंप ने साल की शुरुआत में खूब डालर कमाया, थोड़ा ही खर्चा

वाशिंगटन, रायटर : अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संचालित एक धन उगाहने वाले समूह ने इस साल की पहली छमाही में 6.2 करोड़ डालर (करीब 4.61 अरब रुपये) जुटाए, लेकिन केवल तीस लाख डालर (करीब 22.31 करोड़ रुपये) खर्च किए, जिसमें सबसे अधिक धन ट्रंप समर्थक अनुसंधान केंद्र और 65 हजार डालर (करीब 48.34 लाख रुपये) से अधिक ट्रंप के अपने होटलों में गया।

शनिवार को प्रकाशित संघीय रिकार्ड के अनुसार, रिपब्लिकन ट्रंप ने डेमोक्रेट जो बाइडन से राष्ट्रपति चुनाव हारने के तुरंत बाद नवंबर में सेव अमेरिका कमेटी की स्थापना की। संघीय चुनाव आयोग (एफईसी) के नियमों के तहत समिति के पास व्यापक अधिकार है कि वह अपने पैसे का उपयोग कैसे कर सकती है।

एफईसी के साथ एक फाइलिंग ने दिखाया कि सेव अमेरिका ने जून में अमेरिका फर्स्ट पालिसी इंस्टीट्यूट में एक लाख डालर का योगदान दिया, जो ट्रंप प्रशासन के दिग्गजों द्वारा संचालित एक गैर-लाभकारी संस्था है। समूह के नेतृत्व में ब्रुक रोलिंस शामिल हैं, जिन्होंने ट्रंप के तहत व्हाइट हाउस की घरेलू नीति परिषद का नेतृत्व किया और लैरी कुडलो, जिन्होंने ट्रंप की राष्ट्रीय आर्थिक परिषद का नेतृत्व किया। सेव अमेरिका की फाइलिंग के अनुसार, ट्रंप होटलों में खर्च किए गए धन को आवास या भोजन को कवर करने के रूप में वर्णित किया गया था।

डोनाल्ड ट्रंप। फाइल/इंटरनेट मीडिया

इंद्र 2021 अभ्यास के लिए रूस पहुंचे भारतीय सैनिक

रोस्तोव-आन-डान, एएनआइ : भारतीय सैनिक वोल्गोग्राद क्षेत्र में होने जा रहे इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए रूस पहुंच गए हैं। दक्षिणी सैन्य जिले के प्रवक्ता ने रविवार को यह जानकारी दी।

वादिम अस्तापोव ने कहा, 'वोल्गोग्राद गुमांक हवाई अड्डे पर भारतीय शस्त्र बल के 250 जवानों का समूह पहुंच गया है। यह समूह इंद्र-2021 अंतरराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लेने के लिए आया है।'

आने के बाद भारतीय सैनिक वोल्गोग्राद क्षेत्र में दक्षिणी सैन्य जिले (एसएमडी) प्रुदबोय ग्राउंड में स्थित फील्ड कैंप में चले गए। इंद्र 2021 एक से 13 अगस्त के बीच आयोजित होगा और इसमें मोटर-रायफल से 250 सैनिक, टैंक, आर्टिलरी डिवीजन के साथ ही एसएमडी का खुफिया दस्ता और 250 भारतीय सैनिक भाग लेंगे। अभ्यास में सैन्य हार्डवेयर की 100 से ज्यादा इकाई का भी इस्तेमाल किया जाएगा। यह अभ्यास आतंकवाद से मुकाबले पर केंद्रित रहेगा।

म्यांमार के सैन्य शासक का दो साल में आम चुनाव कराने का वादा

बैंकाक, रायटर : म्यांमार के सैन्य शासक मिन आंग लाइंग ने नवगठित कार्यवाहक सरकार में प्रधानमंत्री की भूमिका अपना ली है। साथ ही दो सालों के अंदर बहुदलीय आम चुनाव कराने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आसियान की ओर से नामित किसी भी विशेष दूत के साथ काम करने को तैयार है और म्यांमार के राजनीतिक समाधान के लिए, वह एशियाई देशों के साथ सहयोग करेंगे।

म्यांमार में निर्वाचित सरकार का तख्तापलट करके सैन्य शासन लाने के छह माह बाद एक टीवी प्रसारण में सैन्य शासक और सीनियर जनरल मिन आंग लाइंग ने रविवार को कहा कि म्यांमार आसियान (एसोसिएशन आफ साउथईस्ट एशियन नेशंस) के साथ उसके तय दायरे में काम करने को तैयार है। इसमें म्यांमार की आसियान के विशेष दूत से बातचीत भी शामिल है। ज्ञात हो, सैन्य शासक मिन आंग लाइंग ने नोबेल पुरस्कार विजेता आन सांग सू की सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार को गिराते हुए सू की को कट्टरपंथी और हिंसा को भड़काने वाली करार दिया था।

सैन्य शासक मिन आंग लाइंग। (फाइल) रायटर

लाइंग ने कहा- दो वर्ष में कराएंगे चुनाव, आसियान देशों से सहयोग करके निकालेंगे सियासी हल

आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक सोमवार को होने वाली है, जिसमें राजनयिकों का कहना है कि वह एक विशेष दूत नियुक्त कर देंगे जो म्यांमार में हिंसा खत्म करने और जुंटा (राजा) और उनके विरोधियों के बीच बातचीत कराने का प्रयास करेगा। सैन्य शासक मिन आंग लाइंग ने म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली का पहले भी आश्वासन दिया है और कहा कि वह संघीय सरकार चाहते हैं।

'जहाज पर हमला ईरान की बड़ी गलती, इजरायल सबक सिखाएगा'

- ईरान ने हमले में हाथ होने के आरोप को बेबुनियाद बताया

यरुशलम, प्रेट्र : इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने ओमान की सीमा पर इजरायली के तेल टैंकरों पर ईरान के घातक ड्रोन हमले का आरोप लगाते हुए कहा कि तेहरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इजरायल इसका सबक अपने तरीके से सिखाएगा।

इजरायली पीएम बेनेट ने रविवार को यह चेतावनी तब दी जब ओमान के तट पर गुरुवार की रात को हुई वमबारी में ईरान ने अपना हाथ होने से इन्कार कर दिया। ओमान के तट पर वमबारी का शिकार हुआ तेल का यह जहाज मरसर स्ट्रीट लंदन की एक कंपनी जोडियक मैरीटाइम की है जिसके मालिक इजरायली शिपिंग कारोबारी एयाल ओफर हैं। अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। इजरायल का आरोप है कि जहाज को तहस-नहस करने के लिए हमला आत्मघाती ड्रोनों से कराया गया है।

रविवार को अपनी साप्ताहिक कैबिनेट बैठक में इजरायली प्रधानमंत्री बेनेट ने कहा कि उन्होंने सुना है कि ईरान अपनी इस कायराना हरकत की जिम्मेदारी लेने से बचना चाह रहा है। वह मना कर रहे हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से इस बात की पुष्टि कर रहा हूं कि जहाज पर हमला ईरान ने ही किया है। हमारे पास इसके खुफिया एजेंसियों से मिले सुबूत हैं। हमें पता है कि ईरान को अब अपने तरीके से संदेश कैसे देना है। ईरान का यह शातिराना बर्ताव ना सिर्फ इजरायल के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए घातक है। इधर, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खातिबजेदह ने इस हमले में ईरान के शामिल होने के आरोपों को निराधार बताया है।

दिखाई सख्ती : नफ्ताली बेनेट। रायटर

टोक्यो ओलिंपिक

खेल महाकुंभ

बड़े मंच की बड़ी खिलाड़ी

ओलिंपिक में दो पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बनीं पीवी सिंधु

2 ओलिंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी और कुल दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं पीवी सिंधु, जबकि भारतीय पुरुष खिलाड़ियों में पहलवान सुशील कुमार ने दो ओलिंपिक पदक अपने नाम किए हैं। उन्होंने 2008 बीजिंग ओलिंपिक में कांस्य पदक और 2012 लंदन ओलिंपिक में रजत पदक जीता था

3 ओलिंपिक पदक हो गए हैं भारत के अब बैडमिंटन में। भारत ने लगातार तीसरे ओलिंपिक में बैडमिंटन में पदक जीता और इस तरह बैडमिंटन में ओलिंपिक पदक की हैट्रिक पूरी की

कांस्य पदक के साथ पीवी सिंधु • प्रेट्र

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : वह बड़े मैच में तनाव में आ जाती है, वह लगातार फाइनल हार रही है, वह फाइनल में हार की पहेली को सुलझा नहीं पा रही है, वह चोकर है...भले ही लोग इस समय पीवी सिंधु का गुणगान कर रहे हों लेकिन कुछ दिनों पहले तक उन्हें यह सब सुनना पड़ रहा था लेकिन वह चुनौतियों का सामना करती रहीं, कोर्ट पर डटी रहीं और जीतने के लिए जी जान लगा दी। इसका नतीजा है कि सिंधु ओलिंपिक में दो पदक जीतने वाली देश की दूसरी खिलाड़ी बन गईं। अब वह बड़े मंच की सबसे बड़ी खिलाड़ी हैं।

एक समय था जब साइना नेहवाल की जीत का शोर था। 2012 लंदन ओलिंपिक में कांस्य पदक जीतकर उन्होंने बैडमिंटन में नई जान फूंक दी थी। उस समय सिंधु इस खेल की नई सनसनी बन रही थीं। सिंधु जहां जाती वहां पदक जीत लेती। देश को उनसे बड़े टूर्नामेंटों में पदक की आस होने लगी। वह भी किसी को निराश नहीं करतीं। उन्होंने 2013 और 2014 में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता और फिर 2017 और 2018 में रजत पदक अपने नाम किया। हालांकि बीच में एक खराब दौर आया जिससे उनका हौसला नहीं टूटा।

2009 में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय सर्किट पर पदार्पण किया था। उन्होंने हाल ही में स्वीकार भी किया था कि समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। उनकी लंबाई को देखते हुए उन्हें इस खेल में आने के लिए प्रेरित किया गया। उनकी सबसे ज्यादा प्रतिद्वंद्विता स्पेन की कैरोलिना मारिन से है। हालांकि दोनों दोस्त भी हैं। रियो ओलिंपिक के फाइनल में वह मारिन से स्वर्ण पदक का मुकाबला गंवा बैठी थी और इस बार मारिन के नहीं होने से उनकी राह कुछ आसान मानी जा रही थी।

सिंधु को लेकर पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन अपर्णा पोपट ने कहा कि उनकी लंबाई अच्छी है और वह इसका फायदा उठाते हुए अच्छे स्मैश मारती हैं। वह शारीरिक तौर भी मजबूत हैं। उनके साथ कोच गोपीचंद भी रहे जिसका फायदा उन्हें मिला लेकिन उनके खेलने का तरीका काफी अच्छा है। नेहवाल का जूनियर स्तर पर प्रदर्शन शानदार रहा है तो सिंधु का खास अच्छा नहीं रहा। नेहवाल ने 2006 में विश्व जूनियर में रजत और 2008 में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं, सिंधु का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2010 में क्वार्टर फाइनल तक रहा था लेकिन जैसे ही सिंधु 2011 में सीनियर स्तर पर आईं तो उनका ग्राफ बढ़ता चला गया। 2011 में उनकी रैंकिंग शीर्ष 150 के आसपास थी लेकिन 2012 में वह 25वें स्थान पर आईं।

पहला गेम : सिंधु ने मुकाबले की अच्छी शुरुआत की। उन्होंने बिंग जियाओ की धीमी शुरुआत का फायदा उठाकर पहले गेम में 4-0 की बढ़त बनाई। फिर उन्होंने तीन शाट नेट पर उलझाए। जियाओ ने शानदार रिटर्न शाट की बदौलत अगले सात में से छह अंक जीतकर 6-5 से बढ़त बना ली। सिंधु ने लंबी रैली के बाद क्रास कोर्ट स्मैश से अंक जुटाया और फिर चीन की खिलाड़ी के रिटर्न लौटाने में नाकाम रहने पर ब्रेक तक 11-8 की बढ़त बना ली। सिंधु ने ब्रेक के बाद अपनी बढ़त को 14-8 और फिर 18-11 तक पहुंचाया। सिंधु ने नेट के पास रिटर्न से अंक जुटाकर 20-12 के स्कोर पर आठ गेम प्वाइंट हासिल किए। बिंग जियाओ ने एक गेम प्वाइंट बचाया, लेकिन इसके बाद क्रास कोर्ट रिटर्न बाहर मार गईं, जिससे सिंधु ने पहला गेम 23 मिनट में 21-13 से जीत लिया।

दूसरा गेम : सिंधु ने दूसरे गेम में भी 4-1 की बढ़त बनाई, लेकिन इसके बाद चीन की खिलाड़ी को वापसी का मौका दे दिया। बिंग जियाओ ने स्कोर 7-8 किया। सिंधु हालांकि क्रास कोर्ट स्मैश के साथ ब्रेक तक तीन अंक की बढ़त बनाने में सफल रहीं। ब्रेक के बाद सिंधु ने कुछ सहज गलतियां कीं। वह बिंग जियाओ के रिटर्न को लंबा समझकर छोड़ बैठीं, जबकि खुद लंबा रिटर्न किया, जिससे बिंग जियाओ वापसी करते हुए स्कोर 11-11 से बराबर करने में सफल रहीं। भारतीय खिलाड़ी ने इसके बाद लगातार चार अंक के साथ 15-11 की बढ़त बना ली। सिंधु ने इसके बाद बिंग जियाओ को वापसी का मौका नहीं दिया। सिंधु ने क्रास कोर्ट स्मैश के साथ 20-15 के स्कोर पर पांच मैच प्वाइंट हासिल किए और फिर एक और क्रास कोर्ट स्मैश के साथ मैच जीत लिया।

'मैं सिंधु के पदक जीतने की वजह से काफी खुश हूं। आमतौर पर होता है कि जब आप तीसरे या फिर चौथे नंबर के लिए खेल रहे होते हैं तो काफी कष्टदायक होता है। इस वजह से मैंने शनिवार को उससे बात करके उसका उत्साह बढ़ाया। मैं खुश हूं कि वह पहली भारतीय महिला हैं, जिसने दो ओलिंपिक पदक जीते हैं। सिंधु से मैंने कहा था कि तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। -**पीवी रमना, सिंधु के पिता**

सिंधु के बड़े टूर्नामेंटों में पदक

पदक	टूर्नामेंट	वर्ष	जगह
कांस्य	ओलिंपिक	2020	टोक्यो
रजत	ओलिंपिक	2016	रियो
स्वर्ण	विश्व चैंपियनशिप	2019	बासेल
रजत	विश्व चैंपियनशिप	2017	ग्लास्गो
रजत	विश्व चैंपियनशिप	2018	नानजिंग
कांस्य	विश्व चैंपियनशिप	2013	कोपेनहेगन
कांस्य	विश्व चैंपियनशिप	2014	ग्वांग्झू
रजत	एशियन गेम्स	2018	जकार्ता
कांस्य	एशियन गेम्स	2014	इंचियोन
स्वर्ण	कामनवेल्थ गेम्स	2018	गोल्ड कोस्ट
रजत	कामनवेल्थ गेम्स	2018	गोल्ड कोस्ट
कांस्य	कामनवेल्थ गेम्स	2014	ग्लास्गो
कांस्य	एशियन चैंपियनशिप	2014	गिंचियोन

नोट : 2018 कामनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण मिस्क्ड टीम में मिला था। अन्य पदक सिंगल्स में मिले हैं।

भारतीय महिला खिलाड़ियों के ओलिंपिक पदक

खिलाड़ी	खेल	ओलिंपिक	पदक
कर्णम मल्लेश्वरी	भारोत्तोलन	सिडनी 2000	कांस्य
साइना नेहवाल	बैडमिंटन	लंदन 2012	कांस्य
एमसी मेरी कोम	मुक्केबाजी	लंदन 2012	कांस्य
पीवी सिंधु	बैडमिंटन	रियो 2016	रजत
साक्षी मलिक	कुश्ती	रियो 2016	कांस्य
मीराबाई चानू	भारोत्तोलन	टोक्यो 2020	रजत
पीवी सिंधु	बैडमिंटन	टोक्यो 2020	कांस्य

नोट : टोक्यो ओलिंपिक में भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाई भी पदक पक्का कर चुकी हैं लेकिन अभी उन्होंने पदक जीता नहीं है।

बैडमिंटन में भारत के ओलिंपिक पदक

खिलाड़ी	ओलिंपिक	पदक
साइना नेहवाल	2012 लंदन	कांस्य
पीवी सिंधु	2016 रियो	रजत
पीवी सिंधु	2020 टोक्यो	कांस्य

सिंधु के रक्षण पर काफी काम किया था : पार्क

नई दिल्ली : भारत के विदेशी बैडमिंटन कोच पार्क ताइ सांग को बहुत खुशी है कि ओलिंपिक से पहले सिंधु के रक्षात्मक कौशल पर कई सत्र तक काम करने का फायदा टोक्यो में मिला। पार्क ने सिंधु के रक्षण पर काफी काम किया था और उन्होंने कहा कि इसका अब फायदा मिला। उन्होंने कहा, 'हम नेट पर उसके खेल और रक्षण पर काम कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि इसका फायदा मिला।' पार्क ने कहा कि सिंधु सेमीफाइनल में ताई जु यिंग के खिलाफ हार के बाद आंसू नहीं रोक पाई थी।

बधाई हो पीवी सिंधु। आपने हम सभी को गौरवान्वित किया।
अभिनव बिंद्रा, ओलिंपिक स्वर्ण विजेता निशानेबाज

स्मैशिंग जीत पीवी सिंधु, मैच में आपका दबदबा रहा और आपने इतिहास रच दिया। बेटियों को जहां भी मौका मिलता है, वो कमाल कर देती हैं। भारत को आप पर गर्व है, आपकी स्वदेश वापसी का इंतजार। आपने कर दिखाया।
- अनुराग ठाकुर, केंद्रीय खेल मंत्री

यह जीत बहुत मायने रखती है

- भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को हराया, सेमीफाइनल में
- 41 साल बाद पदक के करीब भारतीय टीम

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: भारतीय पुरुष हाकी टीम ने रविवार को ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से शिकस्त देकर ओलिंपिक के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया और अब उसे फाइनल में पहुंचने के लिए विश्व चैंपियन बेल्जियम से भिड़ना होगा। मनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम के लिए यह जीत काफी मायने रखती है, जो लंबे अंतराल के बाद ओलिंपिक में सेमीफाइनल में पहुंची है और पदक के दावेदारों में आ गई है। 1980 मास्को ओलिंपिक में स्वर्ण जीतने के बाद भारतीय हाकी टीम के हाथ खाली रहे हैं। जब टीम ने क्वार्टर फाइनल में जीत दर्ज की तो हरमनप्रीत मैदान पर ही भावुक हो गए और कोच ग्राहम रीड के गले लग गए। 2008 बीजिंग ओलिंपिक में टीम पहली बार क्वालीफाई नहीं कर सकी और 2016 रियो ओलिंपिक में आखिरी स्थान पर रही। लेकिन, पिछले पांच साल में हालांकि भारतीय हाकी टीम के प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार आया, जिससे वह विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंची। कोच बने आस्ट्रेलिया के ग्राहम रीड के आने के बाद से खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और फिटनेस का स्तर बढ़ा है। पहले दबाव के आगे घुटने टेकने वाली यह टीम अब आखिरी मिनटों तक हार नहीं मानती है।

पुरुष हाकी सेमीफाइनल का कार्यक्रम

मुकाबला	समय
भारत vs बेल्जियम	सुबह 7:00 बजे
आस्ट्रेलिया vs जर्मनी	दोपहर 3:30 बजे

नोट : ये मुकाबले तीन अगस्त को होंगे
प्रसारण : सोनी नेटवर्क पर

यह आत्मविश्वास था। सभी को अपने ऊपर यकीन था और आज यह अहम रहा। सभी ने आज अपना शत-प्रतिशत दिया और मैदान पर उन्हें स्वयं को लगभग मार ही दिया था। हम बेहद खुश हैं क्योंकि लंबे समय के बाद हमने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। हालांकि अब भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है। -**मनप्रीत सिंह,** कप्तान, भारतीय पुरुष हाकी टीम

चोटिल सतीश क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर

मुक्केबाज सतीश कुमार • प्रेट्र

टोक्यो, प्रेट्र : चोटिल भारतीय मुक्केबाज सतीश कुमार (+91 किग्रा) विश्व चैंपियन बखोदिर जालोलोव के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन के बावजूद क्वार्टर में हारकर बाहर हो गए। प्री-क्वार्टर फाइनल में लगी चोटों के कारण माथे और ठोड़ी पर कई टांके लगवाकर उतरे सतीश 0-5 से हारे। उन्हें जमैका के रिकार्डो ब्राउन के खिलाफ प्री-क्वार्टर फाइनल में दो कट लगे थे।

सतीश ने अपने दाहिने हाथ से पंच भी जड़े, लेकिन जालोलोव पूरे मुकाबले में हावी रहे। तीसरे दौर में सतीश के माथे पर लगा घाव खुल गया, लेकिन इसके बावजूद वह लड़ते रहे। फुटबालर से मुक्केबाज बने जालोलोव ने अपना पहला ओलिंपिक पदक सुनिश्चित करने के बाद सतीश की बहादुरी की तारीफ की।

फवाद मिर्जा 22वें स्थान पर

घुड़सवारी करते फवाद मिर्जा • एएफपी

टोक्यो, प्रेट्र : ओलिंपिक में दो दशक से अधिक समय में घुड़सवारी में उतरे एकमात्र भारतीय फवाद मिर्जा रविवार को क्रास कंट्री स्पर्धा के बाद 11.20 पेनाल्टी अंक के साथ 22वें स्थान पर रहे। सोमवार को व्यक्तिगत शो जंपिंग क्वालीफायर में अच्छा प्रदर्शन करने पर वह और उनका घोड़ा सिगनोर मेडिकाट शीर्ष-25 में रह सकते हैं। इससे वह शाम को होने वाली इवेंटिंग जंपिंग के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में जगह बना लेंगे। मिर्जा के कुल 39.20 पेनाल्टी अंक हैं। उन्होंने सिर्फ आठ मिनट में कंट्री रन पूरी की। घुड़दौड़ क्रासकंट्री व्यक्तिगत वर्ग में एक प्रतियोगी को सात मिनट 45 सेकेंड के अंदर कोर्स का पूरा चक्कर लगाना होता है ताकि टाइम पेनाल्टी कम रहे।

मिर्जा और सिगनोर ने तकनीकी दिक्कत के कारण देर से शुरू किया जिसकी वजह से उन्हें 11.20 पेनाल्टी अंक मिल गए।

लाहिड़ी को मिला 42वां स्थान

टोक्यो, प्रेट्र : भारतीय गोल्फर अनिर्बान लाहिड़ी चौथे और अंतिम दौर में एक ओवर 72 के स्कोर के साथ रविवार को यहां ओलिंपिक पुरुष गोल्फ स्पर्धा में संयुक्त 42वें स्थान पर रहे। दूसरी बार ओलिंपिक में हिस्सा ले रहे लाहिड़ी पहले दौर में 67 के स्कोर के बाद शीर्ष 10 में शामिल थे, लेकिन इसके बाद अगले तीन दिन में 72, 68 और 72 के स्कोर से कुल पांच अंडर 283 का ही स्कोर बना पाए। वह 2016 में रियो ओलिंपिक में 57वें स्थान पर रहे थे। स्पर्धा में हिस्सा ले रहे एक अन्य भारतीय उदयन माने भी अंतिम दौर में एक ओवर 72 के स्कोर से कुल तीन ओवर के स्कोर के साथ 56वें स्थान पर रहे। लाहिड़ी ने अंतिम दौर में तीन बर्डी और चार बोगी की जबकि माने से चार बर्डी और पांच बोगी की। शेंडर शाफेले गोल्फ का स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी बने। उन्होंने कुल 18 अंडर 266 के स्कोर के साथ सोना जीता।

« अनिर्बान लाहिड़ी • एएफपी

बोल्ट के बाद इटली के जैकब्स बने फर्राटा किंग

9.80 सेकेंड में 100 मीटर फर्राटा दौड़ पूरी करके इटली के जैकब्स ने बनाया नया यूरोपियन रिकार्ड, इससे पहले सेमीफाइनल में जैकब्स ने ही 9.84 सेकेंड का नया यूरोपियन रिकार्ड बनाया था

9.58 सेकेंड का विश्व रिकार्ड उसेन बोल्ट के नाम दर्ज है जो उन्होंने 2009 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान बनाया था

9.63 सेकेंड का ओलिंपिक रिकार्ड भी उसेन बोल्ट के नाम दर्ज है, जो उन्होंने 2012 लंदन ओलिंपिक में बनाया था

टोक्यो, एपी : टोक्यो ओलिंपिक में रविवार की शाम को इटली के लेमंट मर्सेल जैकब्स दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले वर्तमान एथलीट बने। उन्होंने ओलिंपिक की 100 मीटर फर्राटा दौड़ को महज 9.80 सेकेंड में पूरी करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही वह फर्राटा दौड़ को जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी भी बने। रजत पदक 9.84 सेकेंड के साथ अमेरिका के फ्रेड केरले ने जीता, जो 2004 में जस्टिन गैटलिन के बाद ओलिंपिक पदक जीतने वाले पहले अमेरिकन धावक भी बने। कांस्य पदक 9.89 सेकेंड के साथ कनाडा के आंद्रे दि ग्रासे ने अपने नाम किया। ग्रेट ब्रिटेन के जर्नेल ह्यूजेस को गलत (फाउल) शुरुआत के लिए दौड़ से बाहर कर दिया गया था। 2008 बीजिंग ओलिंपिक से लेकर 2016 रियो ओलिंपिक तक इस स्पर्धा में जमैका के उसेन बोल्ट का कब्जा था।

लेमंट मर्सेल जैकब्स • ट्विटर

तैराकी में ड्रेसेल और मैककान का रहा जलवा

टोक्यो : अमेरिकी तैराक कैलेब ड्रेसेल ने ओलिंपिक तैराकी स्पर्धाओं में अपना चौथा और पांचवां स्वर्ण पदक जीता। आस्ट्रेलिया की महिला तैराक एम्मा मैककान ने भी इस ओलिंपिक में चौथे स्वर्ण सहित सातवां पदक जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। तैराकी की स्पर्धाओं में सबसे ज्यादा 11 स्वर्ण अमेरिका ने जबकि नौ स्वर्ण पदक आस्ट्रेलिया ने हासिल किए। ड्रेसेल ने पुरुष 50 मीटर फ्रीस्टाइल में परचम लहराने के बाद आखिरी स्पर्धा चार गुणा 100 मेडले रिले में टीम को चैंपियन बनने में अहम भूमिका निभाई।

वहीं बाबी फिंके ने 800 मीटर फ्रीस्टाइल में अपना दबदबा बनाए रखने के बाद 1500 मीटर फ्रीस्टाइल में भी स्वर्ण पदक जीता। वह इस स्पर्धा (1500 मीटर फ्रीस्टाइल) में 37 साल के बाद पदक जीतने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी हैं। वहीं, एक ओलिंपिक में पांच स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही ड्रेसेल तैराकों की विशिष्ट श्रेणी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले माइकल फेल्प्स ने 2008 बीजिंग ओलिंपिक में आठ स्वर्ण, मार्क स्पिट्ज ने 1972 में सात स्वर्ण, क्रिस्टिन ओटो ने 1988 में छह स्वर्ण और मैट बियोन्डी ने 1988 ओलिंपिक में पांच स्वर्ण जीते थे।

7 पदक एक ही ओलिंपिक में हासिल करने वाली पहली महिला तैराक बनीं मैककान, इसमें 4 स्वर्ण पदक शामिल हैं

5 स्वर्ण पदक अमेरिका के ड्रेसेल ने अपने नाम किए

एम्मा मैककान • एपी

कैलेब ड्रेसेल • रायटर

विरोध जताते हुए रिंग में बैठा फ्रांसिसी मुक्केबाज

मुराद अलीव • एएफपी

टोक्यो, एपी : फ्रांस के सुपर हेवीवेट मुक्केबाज मुराद अलीव को रविवार को ओलिंपिक के क्वार्टरफाइनल में जानबूझकर हेड बट (सिर से प्रहार) करने के लिए डिस्क्वालीफाई (अयोग्य) करार किया गया, जिसके बाद वह विरोध स्वरूप रिंग में बैठ गए। मुराद अली को दूसरे राउंड के खत्म होने में चार सेकेंड पहले रैफरी एंडी मुस्टाचियो ने डिस्क्वालीफाई कर दिया और इसके बाद यह मुक्केबाज गुस्से में आक्रामक हो गया।

रैफरी को पूरा यकीन था कि अलीव ने जानबूझकर अपने सिर से ब्रिटिश प्रतिद्वंद्वी फ्रेजर क्लार्क पर प्रहार किया। क्लार्क के इससे दोनों आंखों के करीब गहरे कट लग गए। इस मुकाबले का फैसला सुनाए जाने के बाद अलीव रिंग की रस्सियों के बाहर सीढ़ियों के करीब बैठे गए। वहां से उठे नहीं, जिससे फ्रांस टीम के अधिकारी उनसे बात करने आए।

ज्वेरेव ने जीता टेनिस का स्वर्ण पदक

एलेक्जेंडर ज्वेरेव • एपी

टोक्यो: जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपनी लय को बरकरार रखते हुए ओलिंपिक खेलों की टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स में जर्मनी को पहला खिताब जिताया। जर्मनी के पांचवीं वरीयता ज्वेरेव ने फाइनल में रूस ओलिंपिक समिति (आरओसी) के कारेन खचानोव को 6-3, 6-1 से हराया। यह उनके करियर का सबसे बड़ा खिताब है। छह फुट छह इंच के ज्वेरेव ने अपनी दमदार सर्विस और विश्वास से भरे बैकहैंड से मैच पर नियंत्रण बनाए रखा। वहीं इस हार से खचानोव को रजत पदक से संतोष करना पड़ा।

बेंकिक ने फेडरर के नाम किया स्वर्ण पदक

टोक्यो, एपी : बेलिंडा बेंकिक ने ओलिंपिक में स्विटजरलैंड को महिला सिंगल्स टेनिस का स्वर्ण पदक दिलाने के बाद इसे अपने देश के महान खिलाड़ी रोजर फेडरर के नाम किया। फाइनल मुकाबले से पहले फेडरर के भेजे गए संदेश ने बेंकिक को जीत के लिए प्रेरित किया। 20 ग्रैंडस्लैम खिताब के विजेता फेडरर ओलिंपिक में खुद कभी सिंगल्स स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। फेडरर ही नहीं बेंकिक की आदर्श मार्टिना हिंगस भी ओलिंपिक में कभी स्वर्ण पदक जीतने में नाकाम रही है। ओलिंपिक फाइनल में 12वीं वरीयता प्राप्त बेंकिक ने चेक गणराज्य की मर्केटा वोंड्राउसोवा को 7-5, 2- 6, 6-3 हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। बेंकिक ने कहा, 'मुझे लगता है कि मैंने इसे उनके (रोजर फेडरर और मार्टिना हिंगिस) लिए जीता है। उन्होंने करियर में बहुत कुछ हासिल किया है। मुझे यकीन नहीं है कि मैं कभी वैसा कर पाऊंगी। लेकिन हो सकता है कि मैं उन्हें यह ओलिंपिक पदक देकर उनकी मदद कर सकूं। यह मार्टिना (हिंगिस) और रोजर (फेडरर) दोनों के लिए है।'

डोल्गोपयात ने पदक जीता: आर्तेम डोल्गोपयात ने कलात्मक जिम्नास्टिक में इजरायल के लिए पहला ओलिंपिक पदक जीता। डोल्गोपयात ने स्पेन के प्रतिद्वंद्वी रेडर्ली जपाटा को टाईब्रेक में पछाड़कर पुरुष फ्लोर एक्सरसाइज में स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

फाइनल्स में डोल्गोपयात और जपाटा दोनों को 14.933 अंक मिले थे। दोनों के स्कोर समान थे लेकिन डोल्गोपयात को स्वर्ण पदक दिया गया क्योंकि उन्हें जो प्रयास किया वह जपाटा की तुलना में थोड़ा अधिक मुश्किल था। चीन के शियाओ रोटेंग को कांस्य पदक मिला जो टोक्यो खेलों में उनका तीसरा पदक है। इससे पहले रोटेंग पुरुष आलराउंड में रजत और टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत चुके हैं।

पदक तालिका

	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
चीन	24	14	13	51
अमेरिका	20	23	16	59
जापान	17	5	9	31
आस्ट्रेलिया	14	3	14	31
आरओसी	12	19	13	44
ग्रेट ब्रिटेन	10	10	12	32
फ्रांस	5	10	6	21
द. कोरिया	5	4	8	17
इटली	4	8	15	27
नीदरलैंड्स	4	7	6	17
भारत	0	1	1	2

नोट : भारत तालिका में 59वें स्थान पर है। आरओसी (रूसी ओलिंपिक समिति)

देश को एथलेटिक्स में पदक दिला सकती हैं कौर

पीटी ऊषा
उड़नपरी

टोक्यो ओलिंपिक की शुरुआत के बाद से ही भारत को मुस्कुराने के कई मौके मिले हैं। कोविड से प्रभावित समय में भारतीय दल के ऐसे प्रदर्शन ने मुझे काफी संतुष्टि दी है। पहले ही दिन भारत को जबरदस्त शुरुआत मिली जब मीराबाई चानू ने महिला भारोत्तोलन की 49किग्रा भारवर्ग स्पर्धा में देश को रजत पदक दिलाया। इससे ये बात भी पुख्ता हुई कि एक ओलिंपिक के अनुभव के बाद एथलीटों का प्रदर्शन बेहतर रहता है। मैंने खुद भी 1980 के मास्को ओलिंपिक में हिस्सा लिया था, लेकिन मेरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1984 के लास एंजिलिस ओलिंपिक में सामने आया। मिल्खा सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जिन्होंने 1956 मेलबर्न ओलिंपिक में भी हिस्सा लिया, लेकिन 1960 के रोम ओलिंपिक में अपने प्रदर्शन को नया आयाम दिया।

मीराबाई चानू के बाद टोक्यो में भारत का दूसरा पदक महिला मुक्केबाज लवलीना ने पक्का किया और जब मैं ये लेख लिख रही थी तभी पीवी सिंधु ने भी कांस्य पदक अपने नाम कर लिया।

पुरुष और महिला हॉकी ने भी शुरुआती दौर के प्रदर्शन ने दिखा दिया है कि हम इस खेल में भी दुनिया को चौंका सकते हैं। बेशक हमारे निशानेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, लेकिन वे 2024 के पेरिस ओलिंपिक में निश्चित रूप से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इनमें से कई काफी युवा हैं और टोक्यो में अपने पहले ही ओलिंपिक में हिस्सा ले रहे थे।

अब एथलेटिक्स की बात करते हैं। मैं एथलेटिक्स में भारतीयों के प्रदर्शन से काफी खुश हूं। अविनाश साब्ले से शुरुआत करते हैं। पुरुषों की 3000 मीटर बाधा दौड़ में उन्होंने बहादुरी से हिस्सा लिया और राष्ट्रीय रिकार्ड बना डाला। उन्होंने तीन सेकेंड के समय के साथ अपना व्यक्तिगत रिकार्ड सुधारा। महिलाओं के चक्का फेंक क्वालिफिकेशन में कमलप्रीत कौर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरआल दूसरा स्थान हासिल किया। बेशक उन्हें अमेरिका, क्रोएशिया और क्यूबा की एथलीटों से कड़ी टक्कर मिलेगी, लेकिन मैं उनसे पदक जीतने की उम्मीद कर रही हूं। अगर ऐसा होता है तो आजाद भारत के 73 साल के इतिहास में एथलेटिक्स में देश का ये पहला ऐतिहासिक पदक होगा। बेशक पुरुषों की जेवलिन थ्रो स्पर्धा में नीरज चोपड़ा भी भारत को पदक दिला सकते हैं।

कुल मिलाकर मैं ओलिंपिक का भरपूर लुत्फ उठा रही हूं और उम्मीद है कि देश को हमारे एथलीटों के प्रदर्शन पर गर्व होगा। हमारे एथलीट टोक्यो ओलिंपिक में अच्छा कर रहे हैं। बेशक भारतीय दल का समर्थन और सहयोग करने के लिए भारतीय खेल मंत्रालय का भी आभार व्यक्त किया जाना चाहिए, जिनके बिना ये संभव नहीं था। (टीसीएम)

भारत के आज के मैच

पदक का मुकाबला

एथलेटिक्स (चक्का फेंक): खिलाड़ी : कमलप्रीत कौर, फाइनल दौर, शाम : 4:30 बजे

निशानेबाजी (50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन): खिलाड़ी : संजीव राजपूत और ऐश्वर्य प्रताप सिंह, क्वालीफिकेशन, सुबह 8:00 बजे फाइनल, दोपहर 1:20 बजे

घुड़सवारी (व्यक्तिगत जंपिंग): खिलाड़ी : फवाद मिर्जा, क्वालीफिकेशन, दोपहर 1:30 बजे फाइनल, शाम 5:15 बजे

अन्य मुकाबले

एथलेटिक्स (200 मीटर दौड़): खिलाड़ी : दुती चंद, सुबह 7:24 बजे

महिला हाकी (क्वार्टरफाइनल): भारत बनाम आस्ट्रेलिया, सुबह 8:30 बजे

प्रसारण : सोनी नेटवर्क पर

दैनिक जागरण
सप्तरंग
साहित्यिक पुनर्नवा
सोमवार, 2 अगस्त, 2021

पेड़ हंस पड़े

गीत

कृष्ण भारतीय
गुरुग्राम, हरियाणा

बूंदों की झड़ी क्या लगी-
घबराए पेड़ हंस पड़े।

चेहरों पर ताजगी दिखी-
फूलों के रसभरे बगीचों में,
हरियाली खिलखिला पड़ी-
नर्म-नर्म घास के गलीचों में,

पानी में झूम-झूम भीगे-
जामुन के पेड़ हंस पड़े।

लोगों पर आग सी उगलता-
दंभी सा सूर्य डर गया,

गठरी में बांध धूप सारी-
घबराकर भाग घर गया,

घनी छांव की छतरी ताने-
बरगद के पेड़ हंस पड़े।

खूब बदन रगड़कर नहाई-
जख्मों की दवा हो गई,
नींद लिये सड़क के किनारे-
तख्त दिखा हवा सो गई,

भौचक सा गुलमोहर ठिठका-
पीपल के पेड़ हंस पड़े।

kbhasin15@gmail.com

पुतली खारा जल भर लाई

गीत

सुनील बाजपेयी
कानपुर, उत्तर प्रदेश

कितनो के घर दर्पण टूटे,
चूड़ी रंग महावर छूटे,
बतलाना चाहा तो मेरी,
वाणी की आंखें भर आईं।

आंसू के भीतर से दुनिया,
कैसी पड़ती हमें दिखाई,
लगा देखने पता चला तब,
दिल की चोट अधर पे आई।

टिकली सेंदुर बिछुआ रूठे,
सबके सपने निकले झूठे,
समझाना चाहा तो मेरी,
पलकों ने बूंदें बरसाईं।

इन बूंदों को जोड़-जोड़कर,
मैं जो चित्र बनाया करता,
उसमें मेरा दर्द उतरकर,
शबनम सा रह-रहकर झरता।

फूलों पत्तों तिनकों थमके,
रह-रह मेरी पीड़ा चमके,
दिखलाना चाहा तो मेरी,
पुतली खारा जल भर लाई।

जितना याद करूं उतना ही,
मौसम बरसाती होता है,
कभी-कभी लगता है जैसे,
बादल सिसक-सिसक रोता है।

रस्में वादे कसमें धोखे,
बैठा है कोई सब खोके,
भरमाना चाहा तो मेरी,
पीड़ा मुझे देख मुस्काई।

कैसा ये अलगाव जिंदगी,
कैसा ये बदलाव जिंदगी,
कदम-कदम ठहराव जिंदगी,
कैसा ये बिखराव जिंदगी।

बजते-बजते घुंघरू फूटे,
मौसम ही मौसम को लूटे,
झुठलाना चाहा तो मेरी,
यादों ने बिजली चमकाई।

sunilsbajpai01@gmail.com

आमंत्रण

कहानी/ कविता/ व्यंग्य/ अनुभूति/ ललित आलेख/ लघुकथा एवं राष्ट्रीय महत्व के साहित्यिक-वैचारिक कार्यक्रमों से जुड़ी सूचनाएं, चित्र आदि आमंत्रित हैं। इन्हें इस पते पर भेजें...

पुनर्नवा, दैनिक जागरण, 2-सर्वोदय नगर, कानपुर-208005
punarnava@knp.jagran.com

कि याद जो करें सभी

स्मरण

रजनी गुप्त
लखनऊ, उत्तर प्रदेश

राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने विभिन्न विधाओं में भाषिक प्रयोगों की विपुलता और रचनाओं में कथ्य की नवीनता और वैविध्य से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। 3 अगस्त को जन्मे राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त को याद करता आलेख...

ऐसा कौन देशवासी होगा जिसके श्रीमुख से राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त का नाम अपरिचय की श्रेणी में शुमार होगा? ऐसा कोई भी हिंदीभाषी मिलना लगभग असंभव है जिसने उन्हें न पढ़ा हो या जिसने उनकी एकाधिक कविता न सुनी हों। 'नर हो न निराश करो मन को' जैसी कविताएं।

मैथिलीशरण गुप्तजी देशकाल या वातावरण के अनुरूप आने वाले समय की आहट सूंघ लेते थे। उन्होंने 'किसान' जैसा प्रबंध काव्य लिखकर किसानों की दयनीयता, निरीहता और निश्छलता को साकार रूप दिया। एक तरफ साम्राज्यवादी व सामंतशाही व्यवस्था में पिसते मजदूर तो दूसरी तरफ हमारे भोलेभाले किसान जो भारी मुसीबत से घिर जाने पर भूत-प्रेत, जादू-टोने जैसे तमाम अंधविश्वासों पर भरोसा करके अपनी हताशा को दूर करने की असफल कोशिशों में जुटे रहते। किसानों की पारिवारिक व्यवस्था, महाजनों, साहूकारों और जमींदारों के दलदल में फंसकर छिन्न-भिन्न होती जाती। ऐसी नारकीय स्थितियों में प्राकृतिक प्रकोप भी कम नहीं घटते। कितनी मेहनत मशक्कत के बाद खलिहानों में अन्न के दाने देखने को मिल पाते हैं, किंतु क्या लाभ हमारे किसान भाइयों को?

'हो जाए अच्छी भी फसल पर लाभ कृषकों को कहां?

खाते खवाई, बीज ऋण से हैं रंगे रक्खे यहां,

आता महाजन के यहां वह अन्न सारा अंत में,

अधपेट रहकर फिर उन्हें है कांपना हेमंत में।'

किसानों की जीवन व्यथा कहने के लिए वे सीधे गांवों की चौपाल जा पहुंचते जहां वे अपनों के बीच पहुंचकर उन्हीं की जुबान में बतियाने लगते। हाड़ कंपाने वाली ठंड हो या तेज लू फेंकता सूरज, काम पर डटे किसान पूरी तरह खेती पर निर्भर हैं। उनके पास साधन सुविधाएं बिल्कुल नहीं, खास तौर पर छोटी जोत वाले किसानों की आर्थिक हालत तो दिनोंदिन खराब होती जा रही। साल के बारह महीने कितने कष्ट में बिताने पड़ते-

'घनघोर वर्षा हो रही है गगन गर्जन कर रहा / घर से निकलने को कड़ककर वज्र वर्जन कर रहा।

तो भी कृषक मैदान में करते निरंतर काम हैं / किस लोभ से वे आज भी लेते नहीं विश्राम हैं।

बाहर निकलना मौत है, आधी अंधेरी रात है / आह शीत कैसा पड़ रहा है, थरथराता गात है।'

उनकी कविताएं अपनी सादगी और सरलता के चलते आमजन की जुबान पर चढ़ती गईं।

'भारत भारती' रचते हुए मैथिलीशरण अपनी पूर्व परंपराओं के प्रति मोहाविष्ट होकर कह उठे-

'संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है

उसका कि जो ऋषिभूमि है, वह कौन? भारतवर्ष है।'

19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में मैथिलीशरण जी ने खड़ी बोली को नई प्रतिष्ठा और आधुनिक चेतना के युग परिवर्तनकारी मूल्यों से जोड़कर अपने लेखन में सांस्कृतिक पुनरुत्थान और लोकमंगलकारी मूल्यों को बहुत गहराई से पिरोया। भारतीय अस्मिता और राष्ट्रीय चेतना उनके काव्य में सहज ढंग से उभरकर आई। मैथिलीशरण जी ने पंचवटी और साकेत जैसे ग्रंथों में इतिहास, धर्म, दर्शन, भक्ति, कला और नारी सुधार मूल्यों को स्थापित किया।

बीसवीं सदी की शुरुआत में ही अंग्रेजी शिक्षा-दीक्षा का प्रसार तेजी से शुरू हो चुका था। मैथिलीशरण गुप्तजी आजादी के पहले एवं बाद के संधिकाल के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने-माने जाते हैं। यह सांस्कृतिक जागरण का दौर था जिसमें एक तरफ अतीत के गौरव गान द्वारा हीन अवस्था में पड़ी सुप्त जनता को जाग्रत करने का दायित्वबोध कवि महसूस करने लगे थे तो दूसरी तरफ उर्मिला, यशोधरा, द्रौपदी, राधा, लक्ष्मीबाई, दुर्गावती और पन्ना धाय जैसी तेजस्वी स्त्री चरित्रों पर काव्य रचना करके स्त्री शक्ति को उद्बोधित भी किया जा रहा था। समाज में भी आर्य समाज ने बाल विवाह विरोध, पर्दा प्रथा विरोध, सती प्रथा विरोध और विधवाओं के पुनर्विवाह जैसे आंदोलन चला रखे थे।

'कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता' लेख से उत्प्रेरित होकर गुप्तजी ने 'उर्मिला', 'यशोधरा', 'हिडिम्बा' और 'विष्णुप्रिया' जैसी रचनाओं में उपेक्षिताओं पर कलम चलाने की पहल की। गुप्तजी ने स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व को नई गरिमा देते हुए पुरुष की भोगलिप्सा पर तीखे ढंग से प्रहार किया है-

'कामुक चाटुकारिता ही थी / क्या वह गिरा तुम्हारी

एक नहीं दो दो मात्राएं / नर से भारी नारी।'

उनकी स्त्री पात्र सीता, उर्मिला और यशोधरा परंपरागत नायिकाओं से अलग काफी हद तक स्वतंत्र, स्वावलंबी, आत्मसम्मान प्रिय, गंभीर और मध्यवर्गीय संघर्षगत स्त्री का प्रतिनिधित्व करती हैं। स्त्री मनोविज्ञान की सही पकड़ के लिए मैथिलीशरण जी ने उनके अंदर के मनुष्यत्व को निखारते हुए कैकेयी जैसे रूढ़िबद्ध कलंकित स्त्री पात्रों के भीतर उतरते हुए स्त्री के जटिल मनोविज्ञान को बड़ी सहजता से अपनी उदात्त पैनी दृष्टि के सहारे पकड़ते हुए अनुताप प्रसंग में मार्मिक प्रसंग रच दिए-

'करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं / राई भर भी अनुताप न करने पाऊं

थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके / जो कोई जो कह सके, कहे क्यूं चूके।

छीने न मातृपद कोई भरत का मुझसे / हे राम, दुहाई करूं और क्या तुमसे?'

उपनिवेशवाद के दौर में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनैतिक रूप से स्त्री सक्रिय रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थी। सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, सुभद्राकुमारी चौहान, महादेवी वर्मा जैसी महिलाओं के कदमों की धमक अलग-अलग क्षेत्रों में सुनाई पड़ने लगी।

जब 1929-30 की संधि बेला में देश में आजादी आंदोलन की मशालें जलाई जा रही थीं, मैथिलीशरण की लेखनी मातृभूमि के लिए नया रचने को अकुलाने लगी-

'जाति धर्म या संप्रदाय का / नहीं भेद व्यवधान यहां,

सबका स्वागत, सबका आदर / सबका सम सम्मान यहां।'

घरेलू जीवन में बड़ी विपदाएं उनका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। युगल इस पीड़ा से व्यथित रहे कि उनकी एक-एक करके आठ संतानें हुईं, लेकिन काल के कठोर हाथ असमय ही उनसे छीन ले जाते। क्रमशः वह जीवन से विरक्त होते गए। इसी बीच उनकी नौवीं संतान हुई, मगर वह कभी भी भावी जीवन के प्रति आश्वस्त नहीं हो पाए।

पुरस्कार व प्रशंसाओं के बीच एक बातचीत में मैथिलीशरण जी ने स्वीकार भी किया, 'विशेषकर जो घटनाएं जीवन के लिए बाधक हैं, उन्हीं का प्रभाव अधिक पड़ा है। क्रांति सदैव बाधक घटनाओं के कारण ही हुआ करती है।'

रायकृष्णदास, अज्ञेय, जैनेंद्र एवं डा. नगेंद्र के सामीप्य के अलावा मैथिलीशरण जी और महादेवी वर्मा जी का भाई-बहन का अहैतुक स्नेह अविस्मरणीय है। हालांकि वह सक्रिय राजनीति से जुड़े नहीं, मगर आचरण व लेखन से वह गांधीवादी रहे। देश की राजनीति में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो गए।

देश के हिंदी भाषी भूभाग में सुदूर कोनों, गांवों, प्रांतों, कस्बों और शहरों तक उनकी कविताओं की अनुगूंज पहुंच चुकी थी।

1915 से 1921 तक मैथिलीशरण जी की प्रकाशित कृतियों की संख्या बढ़ती रही। 1952 में उनका विशाल ग्रंथ 'जय भारत' और इसी साल 'युद्ध' भी पूरा हुआ। 1956 में 'राजा प्रजा' तो 1957 में 'विष्णु प्रिया' जैसी पुस्तकों का सृजन उनके साहित्यिक नैरंतर्य के अमिट हस्ताक्षर बनते गए।

मैथिलीशरण जी भारतीय ग्राम्य मूल्यों के विशाल फलक पर खड़ी बोली में रचनाएं रचते रहे। उनके काव्य में प्राचीन आख्यानों को युगानुरूप लोकचेतना के रंग में ढालते हुए आमजन की समझ में आने वाली कविताएं युग की आवाज बनकर उभरीं- 'जिस युग में हम हुए, वही तो अपने लिए बड़ा है / अहा, हमारे आगे कितना कर्मक्षेत्र पड़ा है।'

1952 से वह राज्यसभा के सदस्य रूप में 12 साल तक संसद में राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए अपनी निष्ठा व आवाम की आवाज को बुलंद करने की कोशिश करते रहे-

'है राष्ट्रभाषा भी अभी तक देश में कोई नहीं/ हम निज विचार जना सकें, जिनसे परस्पर सब कहीं।

इस योग्य हिंदी है तदपि, अब तक न निज पद पा सकी/ भाषा बिना भावैकता अब तक न हममें आ सकी।'

gupt.rajni@gmail.com

शेष पुरस्कार

कहानी

रवीन्द्रनाथ टैगोर
(पुण्यतिथि 7 अगस्त)

इतिहास अपने को स्वयं दोहराता है, चाहे रूप कोई भी हो। वर्षों पहले एक पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान घटे घटनाक्रम पर केंद्रित कहानी...

उस दिन आई.ए. और मैट्रिक क्लास का पुरस्कार वितरण समारोह था। पुरस्कार आयोजन की तमाम जिम्मेदारी विमला नामक एक छात्रा को दी गई। विमला एक तो देखने में बहुत अधिक सुंदर थी और उस पर पुरस्कार समारोह के दायित्व के चलते जिस तरह उसके चारों ओर छात्र-छात्राओं का जमघट लगा हुआ था उस कारण से उसके भीतर अतिरिक्त अहंकार आ गया था। संकोची स्वभाव का एक लड़का एक कोने पर खड़ा था। बहुत साहस जुटाकर वह थोड़ा नजदीक आया तो सबने देखा उसके पांव में एक घाव था। एक मैले-कुचैले कपड़े से उसने घाव को बांध रखा था। उसे देखकर नाक मुंह सिकोड़ते हुए विमला ने दूसरे छात्र-छात्राओं से कहा, 'वह यहां क्या कर रहा है? उसकी सही जगह तो अस्पताल में है।'

लड़का बुझे मन से धीरे-धीरे वहां से चला गया। घर जाकर अपनी पढ़ाई वाले कमरे में बैठकर रोता रहा। नाश्ता लेकर उसकी दीदी आईं और उससे पूछने लगीं, 'क्या हुआ जगदीश? रो क्यों रहे हो?' जब जगदीश ने बताया तो उसके अपमानित होने वाली घटना से दीदी गुस्से से जल उठीं। बोलीं, 'उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है न? एक दिन अगर उसे तुम्हारे पैरों के नीचे बैठने पर मजबूर नहीं किया तो मेरा नाम मृणालिनी नहीं।'

इतिहास का पहला अध्याय समाप्त हुआ। वही दीदी अब इंस्पेक्टर आफ स्कूल हैं। वहां निरीक्षण करने आई हैं। उन्होंने अपने भाई के साथ घटित वह कहानी सभी लड़कियों को सुनाई। सुनकर सारी लड़कियां एक सुर में 'छी...छी... छी...' कर उठीं और बोलने लगीं कोई भी लड़की कितनी भी सुंदर क्यों न हो इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है?

मृणालिनी मैम बोलीं, 'संसार में कई बार जो सत्य नहीं है वही सत्य बन जाता है। आज फिर पुरस्कार वितरण समारोह है।' समारोह शुरू होने के कुछ देर पहले ही मृणालिनी ने छात्राओं से पूछा, 'अच्छा उस दिन जिस लड़के को अपमानित किया गया था तुम लोग आज उसे किस रूप में देखना चाहोगी?'

किसी ने कहा, 'कवि' तो किसी ने विप्लवी के रूप में देखना चाहा। बाहर से आई हुई एक लड़की ने कहा कि वह उसे हाईकोर्ट के जज के रूप में देखना चाहती है। कालेज का घंटा बजते ही सब लोग आकर उपस्थित हुए। बाद में जिन्हें पुरस्कार देना था वह आकर बैठे। वह थे हाईकोर्ट के जज जगदीश प्रसाद। उनके बैठते ही मुजफ्फरपुर के एक कन्या हाईस्कूल में गणित पढ़ाने वाली जिस महिला को विशेष रूप से आमंत्रित करके बुलाया गया था, वह आई और उसने जज साहब के चरण स्पर्श करके पांवों में फूलों की माला पहनाकर चंदन का टीका भी उन्हीं पांवों में लगा दिया। जगदीश प्रसाद एकदम आश्चर्यचकित होकर बोले, 'यह भला किस तरह का सम्मान है?'

मृणालिनी मैम बोलीं, 'इसमें कुछ नई बात थोड़े ही है। ऐसा तो पहले भी होता रहा है। हमारे देश में देवताओं की पूजा उनके चरणों से शुरू होती थी। आज तुम्हारा भी वैसे ही पदसम्मान किया गया है।'

अब परिचय वाला काम कर लिया जाए। यह महिला कभी बोर्डिंग स्कूल की अत्यंत सुंदर और घमंडी लड़की थी जिसे लोग विमला के नाम से जानते थे। पिता की मृत्यु के बाद फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया है। जिस पांव को एक दिन उसने घृणा की नजर से देखा था उसी पांव का सम्मान करने के लिए उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। मृणालिनी मैम यानी उस वक्त की दीदी और उनका भाई हाईकोर्ट का जज जगदीश प्रसाद। यह सुनने में कहानी जैसा लग रहा है, लेकिन कभी-कभी कहानियां भी सच होती हैं और जो व्यक्ति यह इतिहास लिख रहा है उसका नाम अविनाश है। वह भी उन दिनों तमाम परीक्षाओं में आसानी से उत्तीर्ण हो जाता था। वह भी इस पुरस्कार समारोह में उपस्थित था। इस दिन कई तरह के खेल भी हुए थे। अविनाश ने रवि ठाकुर की कविता 'पंचनदी के तीरे' सुनाई थी। सबसे बड़ा पुरस्कार उसे ही मिला। आज जज साहब की कृपा से उसे बड़े बाबू की नौकरी मिल गई।

(बांग्ला भाषा में लिखी यह कहानी गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी।)

अनुवाद- श्याम सुन्दर चौधरी
ssckanpur9@gmail.com

बादल ने ढोल बजाए

अनुभूति

देवेंद्रराज सुथार
जालोर, राजस्थान

जीवन में रस घोलने वाली बरखा की बूंदें जब आसमान से उतरकर अंतस की देहरी को स्पर्श करती हैं तो कई नव विचारों के अंकुर फूटने लगते हैं...

सावन का महीना तो वर्षा ऋतु का पर्याय माना गया है। इसी कारण ये लेखकों और रचनाकारों के हृदय के बेहद करीब है। कालिदास से लेकर हरिवंशराय बच्चन तक सभी को सावन ने मोहित और प्रेरित किया है तथा उनके लेखन का विषय भी रहा है। कालिदास का वर्षा ऋतु वर्णन तो संस्कृत साहित्य में अद्भुत वैशिष्ट्य लिए हुए हैं। 'मेघदूत' में कालिदास ने मेघ का खूबसूरत वर्णन किया है।

बारिश की ये बूंदें मन को किस प्रकार आशा और उल्लास से भर देती हैं, इसका रोचक वर्णन हिंदी साहित्य में कई जगह मिलता है। चाहे वो हिंदी साहित्य का मध्ययुग हो जिसमें तुलसी, सूर, जायसी आदि कवियों ने पावस ऋतु का सुंदर और सरस चित्रण किया है या आधुनिक हिंदी साहित्य में छायावादी कवियों में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' या महादेवी वर्मा द्वारा लिखी वर्षा संबंधी कविताएं हों या आज के लेखकों की आधुनिक लेखन क्षमता में वर्षा हो, सबने जैसे साक्षात बारिश को जीने के गुर दिए हैं।

हरिवंशराय बच्चन की एक रचना- 'धरती की जलती सांसों ने मेरी सांसों में ताप भरा, सरसी की छाती दरकी तो कर घाव गई मुझ पर गहरा, है नियति-प्रकृति की ऋतुओं में संबंध कहीं कुछ अनजाना, अब दिन बदले, घड़ियां बदलीं, साजन आए, सावन आया।'

प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की दृष्टि से सावन को देखिए- 'ढम ढम ढम ढम ढम ढम, बादल ने फिर ढोल बजाए। छम छम छम छम छम छम, बूंदों ने घुंघरू छनकाए।'

गुलजार साहब के अनुसार, 'बारिश आती है तो मेरे शहर को कुछ हो जाता है।'

गीत गंधर्व गोपालदास 'नीरज' कहते हैं, 'यदि मैं होता घन सावन का, पिया पिया कह मुझको भी पपिहरी बुलाती कोई।'

पहली बारिश के बाद ही खेतों में जुताई का काम शुरू हो जाता है। जुते हुए खेतों की सोंधी मिट्टी से आने वाली खुशबू में जीवन राग छिपा होता है। जल की ये बूंदें जीवन का अनिवार्य तत्व हैं। जल पीना जैविक आवश्यकता है तो दूसरी ओर जलस्नान, आचमन, पवित्रता की प्यास है। ध्यातव्य है कि जल एक प्राकृतिक और असीमित संसाधन है, किंतु पीने योग्य जल की मात्रा सीमित है। भारतीय संदर्भ में बात करें तो यहां विश्व जनसंख्या का 17 से 18 प्रतिशत भाग निवासरत है तथा जल संसाधनों की मात्रा केवल चार प्रतिशत है। लिहाजा हमारे देश में पेयजल संकट एक प्रमुख समस्या है। इस स्थिति में हमें जल की इन बूंदों को सहेजने की आदत डालनी होगी। रेगिस्तानी इलाकों और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से घर के अंदर भूमिगत टैंक बनाकर वर्षा जल संग्रह करने का प्रचलन है, इस परंपरा को अन्य राज्यों में लागू कर जल संकट की गंभीरता को कम कर सकते हैं। वर्षा जल संचयन के द्वारा व्यापक जलराशि को एकत्रित करके पानी की किल्लत से बचा जा सकता है।

devendrakavi1@gmail.com

इतिहास के भीषण रेल हादसे से शोकाकुल हुआ देश

1999 में आज ही बंगाल के गाइसाल स्टेशन के पास ब्रह्मपुत्र मेल और अवध-असम एक्सप्रेस के एक ही पटरी पर आने से भयानक टक्कर हुई। उसमें करीब 300 लोगों की मौत हो गई और 600 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

फादर आफ इंडियन केमेस्ट्री माने जाते हैं प्रफुल्ल चंद्र राय

फादर आफ इंडियन केमेस्ट्री के नाम से मशहूर प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म आज ही 1861 में खुलना जिले में (अब बांग्लादेश में) हुआ था। उनका परिवार 1870 में कलकत्ता आया था। लंदन विश्वविद्यालय की स्कालरशिप मिलने पर 1882 में ब्रिटेन गए। 1888 में भारत लौटे। 1889 में प्रेसीडेंसी कालेज आफ कलकत्ता में प्रोफेसर नियुक्त हुए। 1896 में स्थिर यौगिक मर्क्यूरियस नाइट्राइट की खोज की। 1901 में 800 रुपये से देश की पहली दवा कंपनी बंगाल केमिकल्स एंड फर्मास्यूटिकल्स वर्क्स स्थापित की। 16 जून 1944 में उनका निधन हुआ।

विश्वनाथन आनंद ने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीती

वर्ष 1987 में आज ही विश्वनाथन आनंद ने फिलीपीस में आयोजित विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप में जीत हासिल कर इतिहास रच दिया था। इस खिताब को जीतने वाले वह पहले भारतीय बने थे। विश्वनाथन आनंद शतरंज में भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी बने थे।

आसान होगी खाने-पीने की चीजों में आर्सेनिक की जांच

नई दिल्ली, आइएसडब्ल्यू : कई प्रकार की शारीरिक विकृतियां पैदा करने वाले प्राकृतिक तत्व खाद्य पदार्थों और पानी में सहज ही पाए जाते हैं। इनकी मात्रा थोड़ी सी भी ज्यादा होने पर स्थिति गंभीर हो जाती है और सामुदायिक स्वास्थ्य का संकट पैदा होता है। सबसे मुश्किल यह कि इसकी मौजूदगी का पता देखकर, चखकर या सूंघकर नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन अब एक ऐसा सेंसर विकसित किया गया है, जो केवल 15 मिनट में पानी और खाद्य नमूनों में आर्सेनिक मौजूदगी का पता लगाने में सक्षम है।

यह सेंसर बेहद संवेदनशील और सेलेक्टिव होने के साथ एक ही चरण की प्रक्रिया वाला है। यह विभिन्न तरह के पानी और खाद्य नमूनों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। सेंसर की सतह पर किसी भी खाद्य या द्रव पदार्थ को रखकर उसके रंग में परिवर्तन के आधार पर आर्सेनिक की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। इस सेंसर का कोई भी व्यक्ति आसानी से संचालित कर सकता है। इस सेंसर का विकास राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (एनएबीआइ) मोहाली में कार्यरत डाक्टर वनीश कुमार ने किया है। इस शोध का प्रकाशन केमिकल इंजीनियरिंग जर्नल में हुआ है।

बता दें कि आर्सेनिक, धातु के समान एक प्राकृतिक तत्व है और इसके संपर्क में आने से त्वचा पर घाव, त्वचा का कैंसर, मूत्राशय, फेफड़े एवं हृदय संबंधी रोग, गर्भपात और बच्चों के बौद्धिक विकास बाधित होने जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इस सेंसर द्वारा तीन तरीकों से परीक्षण किया जा सकता है- स्पेक्ट्रोस्कोपिक मापन, कलरमीटर या मोबाइल एप्लिकेशन की सहायता से रंग तीव्रता मापन और खुली आंखों से। यह सेंसर आर्सेनिक की एक विस्तृत शृंखला - 0.05 पीपीबी (पार्ट्स पर बिलियन) से 1000 पीपीएम (पार्ट्स पर मिलियन) तक का पता लगा सकता है। कागज और कलरमीट्रिक सेंसर के मामले में आर्सेनिक के संपर्क में आने के बाद मेटल-आर्गेनिक फ्रेमवर्क (एमओएफ) का रंग बैंगनी से नीले रंग में बदल जाता है। इसमें नीले रंग की तीव्रता आर्सेनिक की सांद्रता में वृद्धि होने के साथ बढ़ती है।

राष्ट्रीय कृषि-खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के डाक्टर वनीश कुमार ने विकसित किया खास सेंसर

आर्सेनिक से त्वचा के कैंसर, गर्भपात और बौद्धिक विकास के बाधित होने जैसी होती है समस्याएं

आर्सेनिक युक्त खाद्य पदार्थों से होगा बचाव। फाइल

सेंसर को विकसित करने वाले डाक्टर वनीश कुमार ने बताया कि आर्सेनिक आयनों के लिए संवेदनशील जांच पद्धति की अनुपलब्धता एक चिंताजनक विषय है। इसे एक चुनौती मानते हुए, हमने आर्सेनिक के लिए एक त्वरित और संवेदनशील पहचान पद्धति के विकास पर काम करना शुरू किया। हमें मोलिब्डेनम और आर्सेनिक के बीच पारस्परिक प्रभाव की जानकारी थी। इसलिए, हमने मोलिब्डेनम और एक उत्प्रेरक से युक्त सामग्री बनाई, जो मोलिब्डेनम और आर्सेनिक की परस्पर क्रिया से उत्पन्न संकेत दे सकती है। कई प्रयासों के बाद हमने आर्सेनिक आयनों की विशिष्ट, एक-चरणीय और संवेदनशील पहचान के लिए मिश्रित धातु मेटल-आर्गेनिक फ्रेमवर्क (एमओएफ) विकसित करने में सक्षम हुए।

इस सेंसर का भू-जल, चावल और आलू बुखारा में आर्सेनिक के परीक्षण के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक के साथ-साथ कागज आधारित परीक्षण में सफलतापूर्वक किया गया। यह सेंसर आर्सेनिक अशुद्धता की जांच के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पारंपरिक परीक्षण मोलिब्डेनम-ब्लू टेस्ट के उन्नत संस्करण की तुलना में 500 गुना अधिक संवेदनशील है। यह आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली मौजूदा तकनीकों की तुलना में किफायती और सरल भी है।

दुनिया का पहला अंडरवाटर म्यूजियम

महज 10 लाख की आबादी वाले देश साइप्रस के आइया नापा के पेरनेरा क्षेत्र में अंडरवाटर स्कल्पचर म्यूजियम 'मुसान' स्थापित किया गया है। 'मुसान' को पानी के नीचे का जंगल कहा जाता है। इसमें आर्टिस्ट जेसन जेकेयर्स टेलर की 93 कलाकृतियां है, जिन्हें गोता लगाकर करीब से देखा जा सकता है। यह अपनी तरह का दुनिया का पहला अंडरवाटर म्यूजियम है। इसे रविवार से आम लोगों के लिए खोल दिया। फोटोग्राफर जार्जेस निकोली ने यह शानदार तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है। ट्विटर से

इधर-उधर की

कैफे में लोगों के साथ उनके पालतू जानवरों को भी ड्रिंक

लंदन, एजेंसी : लोगों को रेस्तरां जाते समय ज्यादातर अपने पालतू जानवरों को घर पर ही छोड़ना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर आपके साथ जाने वाले इन कुत्ते, बिल्ली का भी वहां पूरा ख्याल रखा जाए। लंदन के आफ्टर बार्क बार एंड कैफे में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। यहां ग्राहकों के साथ आए जानवरों का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है, उन्हें उनकी पसंद की डिश परोसी जा रही है। इस रेस्तरां की मालकिन ने कहा, लाकडाउन में ज्यादातर लोगों ने अकेलापन दूर करने के लिए पालतुओं का आसरा लिया है। जानवरों को भी अच्छे जीवन का अधिकार है। यहां लोगों के साथ आने वाले पालतुओं का भी स्वागत किया जाता है। लोगों के बीच यह रेस्तरां खासा पसंद किया जा रहा है।

यहां पालतू जानवरों को भी मिलती है सभी सुविधाएं ● इंटरनेट मीडिया

रेडियो वेव से होगा लिवर कैंसर का इलाज

शोध ▸ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के इलाज में पाया गया प्रभावी और सुरक्षित

अब तक बहुत ही सीमित है इलाज, छह से 20 महीने तक जिंदा रह पाता है रोगी

नार्थ कैरोलिना (अमेरिका), एएनआइ : लिवर कैंसर का इलाज आज भी बहुत कठिन और सीमित है। ऐसे में इसके सुरक्षित इलाज की खोज समय की जरूरत है। इसी दिशा में एक नए अध्ययन में लक्षित नान-थर्मल रेडियो वेव थेरेपी को हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा (कैंसर) के इलाज में काफी सुरक्षित पाया गया है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा (एचसीसी) लिवर कैंसर का सर्वाधिक सामान्य प्रकार है।

वेक फारेस्ट स्कूल आफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं द्वारा इस संबंध में किए अध्ययन का निष्कर्ष 4ओपन आनलाइन जर्नल में प्रकाशित हुआ है। इसमें कहा गया है कि इस थेरेपी से रोगी का जीवनकाल भी बढ़ता है। वेक फारेस्ट बैपटिस्ट्स कंप्रेहेंसिव कैंसर सेंटर के निदेशक बोरिस पाश्चे के मुताबिक, लिवर कैंसर के 90 फीसद मामले एचसीसी के ही होते हैं। इसमें रोगी का औसत जीवनकाल महज छह से 20 सप्ताह का रह जाता है। लेकिन मौजूदा समय में भी एडवांस लिवर कैंसर के इलाज के सीमित विकल्प ही हैं।

अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने पाश्चे और जर्मनी के थेराबायोनिक जीएमबीएच, एटलिंगेन के अलेक्जेंडू बारबाल्ट द्वारा विकसित एक उपकरण थेराबायोनिक पी1 का इस्तेमाल किया। यह उपकरण एचसीसी के लिए खासतौर पर नियोजित किए, कैंसर माड्यूलेटेड रेडियोफ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसमें फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल रोगी के कैंसर के प्रकार के आधार पर किया जाता है। कैंसर की विशिष्टता की पहचान ट्यूमर बायोप्सी या ब्लड वर्क से की जाती है। एक्सपेरिमेंटल एंड क्लिनिकल कैंसर रिसर्च के 2009 में प्रकाशित एक जर्नल के मुताबिक, पाश्चे और बारबाल्ट ने विभिन्न प्रकार के कैंसर के लिए अलग-अलग प्रकार के 15 रेडियो फ्रीक्वेंसी की खोज की थी।

कैसे काम करता है उपकरण : थेराबायोनिक पी1 एक छोटा सा उपकरण है, जो चम्मच के आकार वाले एंटीना के जरिये रेडियो फ्रीक्वेंसी उत्सर्जित करता है। इस एंटीना को थेरेपी के दौरान रोगी की जीभ पर करीब एक घंटा तक रखा जाता है। इससे रोगी के पूरे शरीर में निम्न स्तरीय रेडियोफ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रानिक फील्ड तैयार किया जाता है। यह प्रक्रिया एक दिन में तीन बार की जाती है। पहले के अध्ययन में देखा गया कि यह उपकरण लिवर कैंसर सेल की वृद्धि को रोकता है और स्वस्थ सेल को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। अब मौजूदा अध्ययन में एचसीसी के एडवांस स्टेज के 18 रोगियों का इलाज इस उपकरण से किया गया है।

वैकल्पिक इलाज का उपकरण। फाइल फोटो

30 फीसद से ज्यादा बढ़ा रोगियों का जीवनकाल

पाश्चे ने बताया, 'हमने पाया है कि रोगियों का जीवनकाल 30 फीसद से ज्यादा बढ़ा और उनके लिवर का फंक्शन भी संरक्षित रहा।' शोधकर्ताओं ने इस पद्धति से इलाज के साइड इफेक्ट को लेकर भी पड़ताल की, जिसमें पाया कि किसी भी रोगी ने प्रतिकूल प्रभाव के कारण इलाज नहीं रोका। पाश्चे ने बताया कि हम प्रारंभिक निष्कर्ष से काफी उत्साहित हैं। हमने पाया है कि इससे रोगी का जीवनकाल भी बढ़ा है। इस पद्धति से इलाज का कोई खास साइड इफेक्ट भी नहीं है।

डांस से शरीर में नियंत्रित रह सकती है कोलेस्ट्राल की मात्रा

अनुसंधान

सेहतकारी है डांस। फाइल फोटो

शरीर में कोलेस्ट्राल की मात्रा बढ़ने के साथ ही लोगों को हार्ट अटैक व अन्य कई बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। एक नए अध्ययन में सामने आया है कि डांस से कोलेस्ट्राल को काबू में किया जा सकता है।

नार्थ अमेरिकन जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में इस बात की जानकारी दी गई है कि बढ़ती उम्र में लोगों में तेजी से वजन बढ़ने की आशंका रहती है। मोटापे से होने वाले नुकसान सामने आने लगते हैं। शरीर में खराब कोलेस्ट्राल की मात्रा भी तेजी से बढ़ने लगती है। यही नहीं महिलाओं में मीनोपाज के दौरान मोटापा व अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बढ़ने लगती हैं। ऐसी स्थिति में शरीर को पूरी तरह दुरुस्त बनाए रखना बड़ी चुनौती होती है। इसके लिए, लोग अलग-अलग तरीके से खान-पान पर भी नियंत्रण के प्रयास करते हैं। इस नए अध्ययन में कहा गया है कि डांस से कोलेस्ट्राल, मोटापे को नियंत्रण में करने के साथ ही महिलाओं की मीनोपाज संबंधी समस्याओं से भी काफी हद तक निजात मिलती है। नियमित रूप से डांस शरीर को पूरी तरह स्वस्थ रखने में कारगर है।

इस अध्ययन का नेतृत्व करने वाले डा. स्टेफनी फाबियन ने बताया कि डांस बढ़ती उम्र में कई रोगों से बचाव कर पूरी तरह स्वस्थ रखने में मदद करता है। डांस में शारीरिक श्रम के साथ ही मानसिक रूप से प्रसन्न होने के कारण इसके फायदे बढ़ जाते हैं। -एएनआइ

स्क्रीन शॉट

प्रियंका मुझे कुश्ती में हरा देंगी : परिणीति चोपड़ा

आगामी दिनों में रणबीर कपूर के साथ फिल्म एनिमल में नजर आएंगी परिणीति। इंस्टाग्राम

सिनेमा जगत की कई हस्तियों के भाई-बहन या परिवार में से कोई न कोई इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, प्रशंसक उनके रिश्तों के बारे में जानने को लेकर काफी उत्सुक रहते हैं। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और उनकी बहन परिणीति चोपड़ा के बारे में भी दोनों के प्रशंसकों में कुछ ऐसी ही उत्सुकता रहती है। शनिवार को इंस्टाग्राम पर परिणीति द्वारा अपने प्रशंसकों के साथ सवाल-जवाब सेशन में भी यह उत्सुकता नजर आई। एक यूजर ने परिणीति से पूछा कि क्या आप आर्म रेसलिंग (हाथों से लड़ी जाने वाली कुश्ती) में प्रियंका चोपड़ा को हरा सकती हैं? इसके जवाब में परिणीति ने प्रियंका को टैग करते हुए लिखा, 'मुझे लगता है कि वह मुझे हरा देंगी।' इस सवाल पर प्रियंका भी चुप नहीं रहीं और उन्होंने इस पर परिणीति को टैग करते हुए लिखा, 'जब हम अगली बार घर पर हों, तो क्यों ना इसे आजमाएं।' वहीं अपनी अगली फिल्म की घोषणा के सवाल पर परिणीति ने लिखा, 'मैं सिर्फ इतना कह सकती हूं कि महामारी के दौरान भी शूटिंग कर रही थी (गुपचुप तरीके से)। इसलिए जल्द ही कुछ घोषणाएं होंगी।' शादी कब करोगी? एक अन्य यूजर के इस सवाल पर परिणीति ने सवालिया निगाहों के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'लड़का कब लाओगे?' परिणीति आगामी दिनों में रणबीर कपूर के साथ फिल्म एनिमल में नजर आएंगी।

विश्वास था कि अपनी जीवन नैया को पार लगा लूंगी : साक्षी तंवर

टेलीविजन के बाद फिल्मों और डिजिटल प्लेटफार्म पर 'दंगल' अभिनेत्री साक्षी तंवर काफी काम कर रही हैं। उनकी आगामी फिल्म डायल 100 होगी जो जी5 पर छह अगस्त को रिलीज होगी। फिल्म में साक्षी तंवर एक असहाय महिला के किरदार में नजर आएंगी। उनसे हुई बातचीत के अंश :

पीड़ित का किरदार चुनौतीपूर्ण : साक्षी ● जी5 पीआर टीम

● फिल्म में आप एक असहाय महिला के किरदार में नजर आ रही हैं। इन किरदारों को निभाना मुश्किल होता है, खासकर तब जब आप वास्तविक जीवन में सशक्त महिला हैं?

-एक्टर को जो किरदार दिया जाए उसे वह पूरी ईमानदारी से निभाए। मैं ऐसा कुछ करना चाहती थी, जिसमें मैं विक्टिम (पीड़ित) का किरदार निभाऊं। अब तक ऐसे किरदार ज्यादा किए है, जिसका अपने जीवन पर पूरा नियंत्रण होता है। मेरे लिए यह किरदार चुनौतीपूर्ण था।

● महज 18 दिनों में फिल्म की शूटिंग हुई है। डिजिटल का यह फार्मेट कैसा लग रहा है, खासकर तब जब आपने टीवी के लंबे फार्मेट में काम किया है?

- लाकडाउन के बाद यह सबसे पहला काम था, जो मैंने किया था। मेरा आठ दिनों का ही काम था। हर फार्मेट का अपना तरीका है। मायने यह रखता है कि आपको काम करने में मजा आ रहा है या नहीं। फिल्म में एक रात की कहानी है, तो ज्यादातर शूटिंग रात में हुई है। रात भर जागना मुश्किल होता है, खासकर तब जब घर पर आपकी नींद पूरी नहीं होती है। घर पर नाइट शिफ्ट के लिए कोई सुविधा नहीं है। घर की बेल भी बजती है, किचन में बर्तनों की आवाज होती है, बच्चे की भी अपनी डिमांड्स रहती है। कोई रहम नहीं खाता है कि नाइट शिफ्ट किया है। मुश्किल रहा, लेकिन मैं एक्टिंग करना एंज्वाय करती हूं।

● मनोज बाजपेयी और नीना गुप्ता के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा?

-मैंने तो अपने करियर की शुरुआत ही मनोज सर के साथ की है। दिल्ली में जब कालेज में थी, तो उन्होंने हमारे नाटक का निर्देशन किया था। मैंने उसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। उनकी दी हुई ट्रेनिंग आज तक काम आ रही है। नीना मैम बहुत सहज हैं। हमने रात में कार वाले सीन किए हैं। कार के शीशे बंद रहते थे, एसी भी बंद रखा जाता था, ताकि उसकी आवाज सीन में न आए। इतनी गर्मी होती थी, लेकिन वह बेहतरीन शाट देती थीं। जैसे ही शाट खत्म होता था, हम खिड़कियां खोलकर गाने चला देते थे।

● क्या मनोज सख्त निर्देशक थे, जब उन्होंने नाटक का निर्देशन किया था?

-वह बहुत सख्त थे। बहुत डांटते भी थे। मैं किसी तरह से बची हुई थी, लेकिन बाकी सभी लोगों ने उनसे डांट खाई थी। कालेज के लेक्चर्स खत्म होने के बाद ही उनके आने का वक्त हो जाता था। वह वक्त के पाबंद रहे हैं। टाइम पर आकर बैठ जाते थे। हम लेक्चर के बाद कैंटीन में जाकर पहले चाय पीते थे, फिर आराम से जाते थे, इस चक्कर में डांट पड़ जाती थी। वह कहते थे तुम लोग एक्टिंग के लिए सीरियस नहीं हो। उन्होंने बहुत अच्छी वर्कशाप हमारे साथ की थी। उन्हें भविष्य में निर्देशन करना चाहिए। मैं तो तलाश रही हूं कहीं से उस नाटक की स्क्रिप्ट हमें मिल जाए, ताकि दोबारा उसे पढ़ सकूं।

● आपने कभी अपनी टीवी की प्रसिद्धी को फिल्मों में काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया...

-मेरे जीवन की दुविधा ही यही रही है कि इस करियर के लिए मैंने कोशिश नहीं की। आप अपने आप चीजें मेरे हित में होती चली गईं। इतना विश्वास जरूर था कि मैं कुछ भी करके अपनी जीवन नैया को पार जरूर लगा लूंगी। मेरे मन में कभी यह बात नहीं रही कि काम नहीं रहा तो क्या करूंगी। जीवन के बहाव के साथ आगे बढ़ती चली गई।

● आप टीवी के धारावाहिकों से दूर हैं। क्या वजह है वहां से दूरी की?

-मैंने बहुत लंबे-लंबे शोज टीवी पर किए हैं। कहानी घर घर की, बड़े अच्छे लगते हैं इतने प्रसिद्ध धारावाहिक रहे हैं। 12-15 घंटे तक रोजाना इतने सालों तक काम किया है। एक वक्त के बाद लगता है कि जीवन में ठहराव की जरूरत है। महसूस होता है कि घर और खुद को समय दिया जाए। उस दौर को जी लिया है, अब इस दौर को जी रही हूं। जो बीत गया है, उसके पीछे भागना नहीं चाहिए।

● दर्शक के तौर आप अपने काम को कितना और किस तरह से देखती हैं?

-कभी-कभार अपनी फिल्म देख लेती हूं, लेकिन वेब सीरीज नहीं देख पाती हूं। काम करने के बाद मेरा काम मेरे दिमाग में छपा रहता है। मैं तो शाट के वक्त मानिटर पर भी अपना काम नहीं देखती हूं। निर्देशक ने ओके कर दिया तो मानिटर को देखने की क्या जरूरत है। एक्शन और कट के बीच आपने अपना काम कर दिया, उतना ही काफी है। **(प्रियंका सिंह)**

29वीं जन्मतिथि पर सामने आया अभिनेत्री मृणाल ठाकुर का 'सीता' लुक

रविवार को अभिनेत्री मृणाल ठाकुर की 29वीं जन्मतिथि पर अभिनेता दुलकर सलमान के साथ उनकी नई फिल्म का एलान हुआ। इस मौके पर निर्माताओं ने इस अनाम फिल्म से मृणाल के लुक की पहली झलक भी जारी की। इस फिल्म में दुलकर सलमान राम और मृणाल सीता के किरदार में नजर आएंगी। हनु राघवपुडी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को तमिल, तेलुगु और मलयालम में बनाया जाएगा। इसके अलावा कंगना रनोट, फरहान अख्तर, पुलकित सम्राट, मौनी राय और रैपर बादशाह समेत कई हस्तियों ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से मृणाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। वहीं, एकता कपूर की प्रोडक्शन कंपनी बालाजी टेलीफिल्म्स के बैनर तले बन रही फिल्म फ्रेडी की घोषणा के अगले ही दिन यानी रविवार को अभिनेता कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। शशांक घोष के निर्देशन में बन रही इस डार्क रोमांटिक थ्रिलर फिल्म की शूटिंग लिए कार्तिक मोटरसाइकिल से ही निकल पड़े। वह अपने घर से मुंबई के वर्सोवा इलाके तक मोटरसाइकिल से गए, उसके बाद उन्होंने सेट तक पहुंचने के लिए जेट्टी (मोटर बोट) का सहारा लिया। उन्हें वर्सोवा में पपराजियों (फोटो पत्रकारों) द्वारा देखा गया। हालांकि इस दौरान हेलमेट और मास्क पहने होने की वजह से कार्तिक का लुक नहीं दिखा। कार्तिक पहली बार एकता कपूर के साथ काम कर रहे हैं। इसके साथ ही डार्क रोमांटिक थ्रिलर जानर में भी उनकी यह पहली फिल्म है।

अभिनेता दुलकर सलमान की अनाम फिल्म में सीता के किरदार में नजर आएंगी मृणाल। इंस्टाग्राम

मेरे लिए दूसरों के सुझाव बहुत मायने रखते हैं : जयदीप सरकार

सिनेमा जगत में निर्देशकों का अपनी फिल्म या शो के प्रति स्पष्ट नजरिया होना जरूरी माना जाता है। हालांकि, कुछ निर्देशक अपने नजरिए के साथ दूसरों के भी सुझाव सुनते हैं और पसंद आने पर उसे प्रोजेक्ट का हिस्सा भी बनाते हैं। हालिया रिलीज एंथोलाजी वेब सीरीज फील्स लाइक इश्क में इश्क मस्ताना कहानी का निर्देशन करने वाले जयदीप सरकार के लिए भी लोगों के सुझाव बहुत मायने रखते हैं। दैनिक जागरण से बातचीत में जयदीप ने कहा, 'मेरे लिए हर कहानी में उसकी प्रमाणिकता सबसे ज्यादा जरूरी होती है। मेरी कोशिश होती है कि देखने के बाद दर्शकों को कहीं भी ऐसा न लगे कि कहानी हवा में है या मैंने कुछ गलत बोल दिया है। मेरे लिए दूसरों के सुझाव बहुत मायने रखते हैं। मैं अपनी ही धुन में चलकर कुछ बनाना नहीं पसंद करता हूं। इसके लिए मैं लगातार लोगों से अपनी कहानियों के बारे में चर्चा करता रहता हूं। मेरी यह कहानी युवाओं से संबंधित है, इसलिए मैं सेट पर अपने युवा क्रू सदस्यों के साथ भी लगातार बातचीत करता रहता था ताकि मेरी यह कहानी वास्तविकता से जुड़ी रहे। मुझे युवा पीढ़ी के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता रहती है और उनकी प्रतिभा से मुझे प्रेरणा भी मिलती है।' अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में जयदीप बताते हैं, 'लाकडाउन के दौरान कामेडी ने ही मुझे बचाया है। इसलिए आगे मैं एक कामेडी शो प्रोड्यूस कर रहा हूं। उस पर काम चल रहा है, जल्द ही शूटिंग भी शुरू होगी।' इश्क मस्ताना में तान्या मानिकतला और स्कंद ठाकुर मुख्य भूमिका में हैं।

अब कामेडी शो बनाने की तैयारी कर रहे हैं जयदीप। इंस्टाग्राम

मैंने इस दौर के लिए बहुत समय तक इंतजार किया है : यामी गौतम

भूत पुलिस और ए थर्सडे समेत यामी की कई फिल्में हैं रिलीज की कतार में। इंस्टाग्राम

बाला और बदलापुर जैसी फिल्मों की अभिनेत्री यामी गौतम घर के सितारे इन दिनों बुलंद हैं। मौजूदा दौर की बात करें तो फिलहाल उनके पास भूत पुलिस, दसवीं, ए थर्सडे और लास्ट समेत कई फिल्में हैं। अपने करियर के इतने व्यस्त दौर को लेकर यामी ने एक लाइव चैट के दौरान कहा, 'मैंने इस दौर का बहुत लंबे समय से इंतजार किया है और अब यकायक इतनी सारी चीजें एक साथ मुझे मिल गई हैं। मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं। मुझे लगता है कि किसी डोनर और कुछ अन्य फिल्मों के बाद मेरे सफर की शुरुआत अब हुई है। मैं अपने इस दौर से खुश हूं और व्यस्तता को लेकर मुझे कोई शिकायत नहीं है। हालांकि, मैं उस स्थिति में नहीं जाना चाहती जहां मुझे अपने किरदार की तैयारी और उस पर होमवर्क करने का वक्त न मिले। मुझे सिर्फ फिल्मों की संख्या बढ़ाने में यकीन नहीं है। अगर आप कुछ अलग नहीं कर रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। मुझे खुद पर काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है, जो मैं अपनी हर फिल्म में कर रही हूं। मैं बहुत खुश हूं कि मैंने जिन फिल्मों का चुनाव किया है, वह सब जानर्स और किरदार समेत सभी मामलों में एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। लास्ट मेरी चौथी फिल्म है जिसकी शूटिंग मैं इस महामारी के दौरान कर रही हूं। आगे तीन और फिल्में लाइन में हैं, अगर कोरोना की तीसरी लहर नहीं आती है तो इस साल के अंत तक उनकी भी शूटिंग पूरी कर लूंगी।'

हीरा मंडी में रिचा चड्ढा की हो सकती है एंट्री

फिर भंसाली के साथ काम कर सकती हैं रिचा ● इंस्टाग्राम

फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग खत्म करने के बाद फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली का पूरा ध्यान अब अपनी आगामी वेब सीरीज हीरा मंडी पर है। अपनी फिल्मों की तरह इस सीरीज को भी भव्य बनाने की तैयारी जारी है। हीरा मंडी सीरीज में लंबी-चौड़ी स्टारकास्ट होने की संभावना जताई जा रही है। संजय इस सीरीज के लिए कई अभिनेत्रियों की तलाश में हैं। सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी पहले ही इस प्रोजेक्ट के लिए फाइनल कर ली गई हैं। जहां सोनाक्षी एक तरफ कथक क्लासेस लेने की तैयारी में हैं, वहीं माधुरी दीक्षित इस सीरीज के लिए एक बड़ा गाना भी शूट करने वाली हैं। इसी बीच एक और नाम सीरीज से जुड़ने की खबर है। वह नाम है रिचा चड्ढा का। सूत्रों के मुताबिक रिचा को संजय लीला भंसाली के आफिस जाते देखा गया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि हीरा मंडी में अभिनेत्री रिचा भी होंगी। इससे पहले रिचा संजय के निर्देशन में फिल्म गोलियों की रासलीला : रामलीला में अभिनय कर चुकी हैं। उसमें उनका छोटा सा किरदार था। दोनों एक दूसरे की कार्यशैली से वाकिफ हैं। बताया जा रहा है कि हीरा मंडी सीरीज बड़े स्केल पर शूट होने वाली है। यह संजय का डिजिटल डेब्यू भी होगा, ऐसे में वह स्टारकास्ट में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। संजय इस कोशिश में भी हैं कि हीरा मंडी में दिखाया जाने वाला मुजरा पाकीजा और उमराव जान जैसी फिल्मों से अलग हो।